3 राजधानी
एक जून से मेट्रो चलाने का दबाव

6 अभिमत
आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत

10 स्पोर्ट्स
लॉकडाउन में मानसिक तौर पर मजबूत रहना जरूरी : नारंग

11 विदेश
ट्रंप ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर साधा निशाना

RNI NO. DELHI/2012/48369
वर्ष 8 अंक 204
नई दिल्ली, शनिवार, 30 मई, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

मानुषी छिल्लर ने थामा यूनीसफ का हाथ

विविध-12

लॉकडाउन पर मन की बात करेंगे मोदी

- गृहमंत्री अमित शाह के साथ बनाई रणनीति, राज्यों को हिदायतों के साथ मिल सकते है और अधिकार
- पश्चिम बंगाल में एक जून से खुलेंगे मंदिर और मस्जिद

लॉकडाउन पर मंथन करते प्रधानमंत्री व गृह मंत्री

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

लॉकडाउन 4.0 के खत्म होने से दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लॉकडाउन के 31 मई के बाद भी जारी रहने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों के साथ और आर्थिक क्षेत्रों को खोलने के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के रुख पर चर्चा की।

पिछले तीन दिनों से गृह मंत्री सूचनाएं इकट्ठा कर रहे थे और सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा कर रहे थे। उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक केंद्र राज्यों को आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने तथा कंटेंनमेंट जोन की परिभाषा तय करने का अधिकार दे सकता है। बताया जाता है कि बहुत से मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन जारी रखने को प्राथमिकता दी लेकिन लगभग सभी ने इसके साथ साथ शॉपिंग मॉल और सार्वजनिक परिवहन को खोलने पर सहमति जताई। सभी मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से आर्थिक गतिविधियों को तेज करने तथा जनजीवन को धीरे धीरे सामान्य करने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई कि जब देश लॉकडाउन नियमों में ढील देगा तो मरीजों की संख्या में एकाएक तेज इजाफा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र द्वारा गठित विशेष कोविड-19 पैनलों में से दो ने लॉकडाउन से बाहर निकलने रणनीति पर अपनी सिफारिशें केंद्र को सौंपी है। इन पैनलों से सुझाव दिया है कि केंद्र स्कूल, कॉलेजों, मूवी हाल तथा धार्मिक स्थानों को हालात बेहतर होने तक बंद रखने के अलावा लॉकडाउन की अन्य सभी पाबंदियों को हटा सकता है।

पैनल ने अंतरराज्यीय यात्रा को भी अनुमति न देने की सिफारिश की है और कहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में कंटेंनमेंट के लिए उठाए गए कदमों को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। सबसे ज्यादा प्रभावित 13 जिलों में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली/नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता/हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू तथा थिरुवल्लूर (दोनों तमिलनाडु) शामिल हैं। इन 13 जिलों में देश भर के 70 फीसदी पाजिटिव मामले हैं। केंद्र और 13 जिलों से संबंधित राज्यों ने कंटेनमेंट जोन की भौगोलिक परिभाषा तय करने के लिए एक योजना पहले ही बना ली है। गृहमंत्री ने संवेदनशील शहरों के 13 पालिका आयुक्तों और जिलाधिकारियों से कैबिनेट सचिव के बीच हुई बातचीत से निकलकर आए निष्कर्षों के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा लॉकडाउन के बारे में केंद्र सरकार अगले दो दिनों के भीतर अपने फैसले का ऐलान कर देगी। प्रधानमंत्री 31 मई को 'मन की बात' में संभवत: इस बारे में बात करेंगे। मौजूदा लॉकडाउन नियमों के तहत कंटेनमेंट जोन में होटल, मॉल, सार्वजनिक परिवहन को खोलने की अनुमति नहीं है। उम्मीद है कि इसमें कुछ नरमी लाई जाए तथा मॉल में दुकानों और होटलों को सीमित संख्या में प्रवेश के साथ अनुमति दे दी जाए। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से सभी धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी लेकिन एक बार में 10 से ज्यादा व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकेंगे।

ममता ने कहा 'राज्य में मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और सभी धार्मिक स्थान बंद हैं। इन्हें एक जून से खोल दिया जाएगा तथा एक बार में 10 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक स्थानों पर सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी।' कोरोना वायरस के फैलाव को रोकन के लिए 25 मार्च को लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते पूरे देश में धार्मिक स्थान बंद हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने केंद्र से धार्मिक स्थानों, होटल, मोटल, लॉज खोलने की अनुमति देने की केंद्र से मांग की है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि देश के बड़े कंटेनमेंट जोन से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति जांचने का अधिकार राज्यों को जरूर दिया जाए। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मीडिया से कहा कि उन्होंने केंद्र को लॉकडाउन जारी रखने के बारे में सूचित कर दिया है लेकिन हास्पिटैलिटी सेक्टर को खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने धार्मिक स्थलों को खोलने पर आशंका जताई है। महामारी पर काबू पाने के बाद में ट्रेन और हवाई यात्रा शुरू होने के बाद राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्य, जहां केंद्र द्वारा रेल और हवाई यात्रा को खोलने के बाद कोरोना वायरस के मामले तेजी बढ़ने शुरू हो गए हैं, ने केंद्र से कंटेनमेंट जोन से आने वाले यात्रियों की गहन जांच कराने की बात कही है।

मोदी-ट्रंप में नहीं हुई लद्दाख और चीन मुद्दे पर कोई बात

- अमेरिकी राष्ट्रपति के मोदी का मूड ठीक नहीं बयान के बाद भारत ने ऐसी किसी चर्चा को नकारा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत ने शुक्रवार को इस बात से इनकार किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल में लद्दाख मुद्दे और चीन को लेकर टेलीफोन पर कोई बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने मोदी से बातचीत की है और 'चीन में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर वे अच्छे मूड में नहीं हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के विपरीत सूत्रों ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है। अंतिम बार दोनों नेताओं की चार अप्रैल को हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर बातचीत हुई थी। ट्रंप ने गुरुवार को मोदी से बातचीत का दावा किया था, उन्होंने भारत और चीन के बीच चल रहे अपने कथित 'बड़े विवाद' को लेकर की गई मध्यस्थता की पेशकश को फिर दोहराया था। वे लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव का उल्लेख कर रहे थे. जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच चार बार झड़प हो चुकी है।

व्हाइट हाउस में एक बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा 'मैं आपसे कह सकता हूं, मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी। चीन के साथ जो कुछ चल रहा है उसको लेकर वे अच्छे मूड में नहीं थे।' यह पूछे जाने पर कि क्या वे भारत और चीन सीमा पर हालात को लेकर चिंतित हैं, उन्होंने कहा 'भारत और चीन... उनके बीच बड़ा विवाद है। दोनों देशों (प्रत्येक की) की आबादी 1.4 अरब है। दोनों देशों के पास बेहद ताकतवर सेनाएं हैं। भारत खुश नहीं और संभवत: चीन भी खुश नहीं है।

राष्ट्रपति ने भी यह भी कहा कि वे भारत में मुझे पसंद करते हैं। इस देश में मीडिया जितना मुझे पसंद करता है मुझे लगता है कि उससे कही ज्यादा वे मुझे भारत में पसंद करते हैं। और मैं मोदी को पसंद करता हूं। मैं आपके प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करता हूं। वे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं।' नई दिल्ली ने भारत और चीन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्यस्थता की पेशकश को यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। पूर्वी लद्दाख में पिछले 25 दिनों (शेष पेज 9)

चीन ने ठुकराई ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश

भाषा। बीजिंग

चीन ने भारत के साथ सीमा पर अपने मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मध्यस्थता का प्रस्ताव शुक्रवार को खारिज कर दिया।

चीन ने कहा कि दोनों (पड़ोसी) देश वार्ता के जरिए अपने मतभेद दूर करने में सक्षम हैं और उन्हें किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

उल्लेखनीय है कि ट्रम्प ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए भारत-चीन सीमा विवाद में बुधवार को मध्यस्थता करने की पेशकश की और कहा कि वह दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के दौरान तनाव कम करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर पहली बार प्रतिक्रिया (शेष पेज 9)

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन

भाषा। रायपुर

फाइल फोटो

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का शुक्रवार को निधन हो गया। वह लगभग 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। रायपुर स्थित श्री नारायणा अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुनील खेमका ने शुक्रवार को यहां बताया कि 74 वर्षीय जोगी ने आज दोपहर बाद 3.30 बजे अंतिम सांस ली। अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अजीत जोगी का अंतिम संस्कार शनिवार को उनकी जन्मभूमि गौरेला में होगा। डॉ. खेमका ने बताया कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रमुख अजीत जोगी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें नौ मई को अस्पताल में (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	32,424	223
निफ्टी	9,580	90
सोना		/10g
चांदी		/kg

क्विक न्यूज

वाराणसी में गंगा में नहाते पांच किशोर डूबे

वाराणसी। वाराणसी के रामनगर के कोदोपुर क्षेत्र के सिपहिया घाट पर शुक्रवार की सुबह गंगा में टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान पांच किशोर डूब गए। पांचों को 11 एनडीआरएफ और पुलिस टीम गंगा से निकालकर अस्पताल ले गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रामनगर थाना के वारीगढ़ही के तौसीफ (17), फरदीन (14), शैफ (15), रिजवान (15) और सकी (14) अपने दो अन्य दोस्तों के साथ घर से लगभग एक किलोमीटर दूर सिपहिया घाट पर गंगा किनारे आए थे। बताया जाता है कि पांचों ने पहले रेत पर टिकटॉक वीडियो बनाया और इसके बाद गंगा में उतर गए।

डराने लगी है दिल्ली: एक दिन में 1106 मामले, 82 की मौत

पायनिय समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी में कोरोना संक्रमण की गति तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को 1106 नए मामले आए हैं। इस तरह पिछले दो दिनों में ही 2128 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कुल केस बढ़कर 17 हजार के पार पहुंच गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 316 से बढ़कर 398 हो गई है। इस तरह से मरने वालों का आंकड़ा 82 बढ़ा है। गत चौबीस घंटे में 351 लोग बीमारी को मात देकर अपने घर पहुंच गए हैं।

इससे दिल्ली में अब तक 7846 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 17386 मामले हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1106 नए मामले आए हैं। अब तक दिल्ली में 398 मौत हुई है। सफदरगंज तथा अन्य अस्पतालों की पुरानी रिपोर्ट आने के बाद यह ताजा आंकड़ा है। अभी दिल्ली में कुल 2100 मरीज भर्ती हैं। फिलहाल 5000 से ज्यादा एक्स्ट्रा बेड मौजूद हैं। इसमें निजी अस्पतालों के 1400 तथा सरकारी अस्पतालों के 3700 बेड शामिल हैं। हम इस संख्या को और बढ़ा रहे हैं। मरीजों की संख्या से दोगुना ज्यादा बेड की तैयारी है। अभी 28 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि 300 खाली वेंटीलेटर मौजूद हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश और दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं। लोगों को संक्रमण से खुद को बचाना जरूरी है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना से 13 मौत हुई है। साथ ही, 69 पुराने मामले भी जोड़े गए हैं। इसके कारण कल की तारीख में 82 मौत की रिपोर्ट दिखेगी। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कल हुई 13 मौत के अलावा शेष 69 मामले पिछले 34 दिन के हैं। यह अलग-अलग दिनों में हुई मौत की लेट रिपोर्टिंग है। इनमें 52 मामले सफदरगंज अस्पताल के शामिल हैं। सिसोदिया ने कहा कि होम क्वॉरंटीन के दौरान घर में किसी अलग कमरे की व्यवस्था करना बेहतर है। अगर अलग कमरे की व्यवस्था ना हो, तो अलग बेड की व्यवस्था कर सकते हैं। करीब 80-90 फीसदी मरीज होम क्वॉरंटीन से स्वस्थ हुए, हरेक को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं।

कोरोना से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय बरतना जरूरी है। सिर्फ किसी चीज को छूने से कोरोना नहीं होगा। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के थूक के ड्रॉपलेट्स का मुंह, नाक या आंख से इनटेक होने पर संक्रमण होगा। इसलिए किसी भी चीज को छूने के तत्काल बाद साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो लेने से संक्रमण नहीं होगा। मरीजों के ठीक होने की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सब मिलकर प्रयास करें और सावधानी बरते हैं तो कोंरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

कोविड-19 से मौत के मामले में चीन से आगे निकला भारत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या के लिहाज से भी भारत इस महामारी को जन्म देने वाले चीन से आगे निकल गया है। चीन में कोरोना से 4,638 लोगों की जान गई है और संक्रमितों की कुल संख्या 84,106 है जबकि भारत में मौत का आंकड़ा 4,706 और बीमारों का करीब एक लाख 66 हजार (1,65,799) पर पहुंच गया है। इसी के साथ कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों की सूची में तुर्की को पीछे छोड़कर देश नौवें स्थान पर आ गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी (जेएचयू) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत अब तुर्की को पीछे छोड़कर वायरस से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की लिस्ट में नौंवे पायदान पर पहुंच गया है। कोविड 19 के गंभीर संक्रमण के लिहाज से अन्य शीर्ष देश अमेरिका, ब्राजील, (शेष पेज 9)

संभल के मंदिर में मिला पुजारी व उसके बेटे का शव

संभल(भाषा)। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पुजारी और उसके बेटे के शव मिलने का मामला सामने आया है। शुक्रवार सुबह मंदिर में दोनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना संभल जिले के नखासा थाना इलाके के रसूलपुर सराय गांव की है। पुजारी पिता.पुत्र के शव शिव मंदिर में शुक्रवार को सुबह मिले। दोनों के गले पर निशान मिले हैं। घटना को पुलिस आत्महत्या मानकर चल रही है। इसके साथ ही घटना से जुड़े पहलुओं पर छानबीन चल रही है। पुजारी का नाम अमर सिंह उम्र 60 वर्ष है। बेटे का नाम जयवीर उम्र 21 वर्ष है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। इससे पहले 27 अप्रैल की देर रात बुलंदशहर के अनूपशहर कोतवाली में दो साधुओं की हत्या कर दी गई थी। मंदिर परिसर (शेष पेज 9)

आर्थिक सेहत नाजुक, विकास दर 11 साल के निचले स्तर पर

- कोरोना संकट के बीच जीडीपी आंकड़े जारी, चौथी तिमाही की विकास दर 3.1 फीसदी पूरे वर्ष की 4.2 फीसदी

भाषा। नई दिल्ली

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में घटकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।

इस तरह पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर गिरकर 4.2 प्रतिशत रह गई है। उपभोग और निवेश में गिरावट की वजह से जीडीपी की वृद्धि दर का आंकड़ा नीचे आया है। आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार 4.2 प्रतिशत रही है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में 6.1 प्रतिशत रही थी। यह 2008-09 के बाद जीडीपी की वृद्धि दर का सबसे कमजोर आंकड़ा है। 2008-09 में आर्थिक वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही थी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया था।

जनवरी-मार्च के दौरान दुनियाभर में आर्थिक गतिविधियां सुस्त रहीं, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 में आर्थिक वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। एनएसओ ने इस साल जनवरी और फरवरी में जारी पहले और दूसरे अग्रिम अनुमान में वृद्धि दर पांच प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से जनवरी-मार्च, 2020 के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 6.8 प्रतिशत की गिरावट आई है।

इस बीच, सीएसओ ने बीते वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के वृद्धि दर के आंकड़े को घटा कर 4.7 की जगह 4.1 प्रतिशत कर दिया है। इसी तरह बीते वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के आंकड़ों को भी क्रमश 5.6 से कम कर 5.2 प्रतिशत और 5.1 की जगह 4.4 प्रतिशत किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में चौथी तिमाही में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में इसमें 2.1 प्रतिशत की वृद्धि (शेष पेज 9)

दिल्ली-एनसीआर में दो महीने में 5वीं बार भूकंप के झटके

भाषा। नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार रात नौ बजकर आठ मिनट पर भूकंप से झटकों से धरती हिल उठी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.6 दर्ज की गई। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्लीए, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और गाजियाबाद समेत अन्य जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसे भूकंप के झटके आए लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र (एनसीएस) ने यह जानकारी दी। एनसीएस के अनुसार भूकंप के झटके रात नौ बजकर आठ मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप का केन्द्र पांच किलोमीटर की गहराई में स्थित था। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है। दिल्ली-एनसीआर में यह पांचवा मौका था जब भूकंप (शेष पेज 9)

दिल्ली, यूपी, बिहार में धड़ाधड़ मर रहे चमगादड़, दहशत

राजेश कुमार। नई दिल्ली

- वन विभाग के अधिकारियों-विशेषज्ञों की राय में भीषण गर्मी, तालाब-झीलों के सूखने से पानी की किल्लत हो सकती है मौत की वजह

पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहस्यमय तरीके से धड़ाधड़ मर रहे चमगादड़ों ने विशेषज्ञों और वन विभाग के अधिकारियों को हैरान कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के बीच रात में जगने वाले जीव की विचित्र मौत की घटना ने लोगों में भय पैदा कर दिया है क्योंकि चमगादड़ों को ही चीन के वुहान में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की वजह माना जाता है।

वन विभाग के अधिकारी फिलहाल यह आशंका जता रहे हैं कि तापमान में हुई जबर्दस्त बढ़ोतरी और गर्मी के चलते देश के तमाम हिस्सों में तालाबों व झीलों के सूख जाने से पैदा हुई पानी की किल्लत भी चमगादड़ों की मौत का कारण हो सकती है। बरेली स्थित इंडियन वेटरीनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईवीआरआई) की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, गोरखपुर के बेलघाट में भीषण गर्मी से चमगादड़ों को ब्रेम हैमरेज हुआ और वे मर गए। आईवीआरई निदेशक डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि मरे हुए चमगादड़ों में कोरोना वायरस अथवा रैबीज के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। चमगादड़ों में प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और वे किसी रोगाणु, वायरस अथवा बैक्टीरिया से प्रभावित नहीं होते। अलबत्ता वे कोरोना वायरस के कैरियर जरूर बन सकते हैं। दिल्ली सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ईश्वर सिंह ने पायनियर को बताया कि चमगादड़ों की मौत के पीछे भीषण गर्मी मुख्य वजह हो सकती है लेकिन कोरोना वायरस की महामारी को ध्यान में रखते हुए मृत चमगादड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि उनके मरने की असली वजह का पता लग सके।

एनडीएमसी के पशु पालन विभाग ने कारण जानने के लिए लुटियन दिल्ली इलाके में स्थित मोती लाल नेहरू मार्ग पर मरे चमगादड़ों को उठाया है। मोतीलाल नेहरू मार्ग चमगादड़ों (फ्रूट बैट) और तितलियों की बहुतायत के लिए जाना जाता है। दरअसल, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने सरकारी बंगले 3 मोतीलाल मार्ग पर इनके लिए प्राकृतिक घरौंदे बनवाए हुए थे। इस हफ्ते की शुरुआत में गोरखपुर के बेलघाट जिले में आम के एक बगीजे में लगभग 300 चमगादड़ मरे पाए गए जिससे स्थानीय लोगों के बीच दहशत व्याप्त हो गई थी।

सोशल मीडिया पर बगैर किसी वैज्ञानिक आधार के कोरोना महामारी के फैलने संबंधी अफवाहों के जोर पकड़ने से बौखलाए अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मृत चमगादड़ों को उठाकर मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। इसी तरह बिहार में आरा के पास भोजपुर जिले में भारी तादाद में चमगादड़ों की मौत हुई जिनके नमूनों को जांच के लिए पटना भेजा गया है।

हरियाणा सरकार ने बदला अध्यापक-छात्र अनुपात, विरोध में उतरे शिक्षक

शिक्षा मंत्री के दरबार में पहुंच किया विरोध

स्कूलों में पुराने फार्मूले को लागू करने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा के शिक्षक सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में अध्यापक व छात्र अनुपात बढ़ाए जाने के फैसले के विरोध में आ गए हैं। शिक्षकों ने शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके पुराने नियमों को लागू करने की मांग की है।

शिक्षकों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार ने उनकी यह मांग नहीं मानी तो अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर वह संघर्ष की रणनीति का ऐलान करेंगे। हरियाणा सरकार ने गुरुवार को एक पत्र जारी करके प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए सिरे से रेशनलाइजेशन फार्मूला लागू किया था। जिसके तहत अब स्कूलों में 1:25 की बजाए 1:30 के अनुसार पढ़ाई होगी।

विभाग ने जेबीटी, टीजीटी व सीएंडवी अध्यापकों के लिए रेशनलाइजेशन प्रक्रिया के लिए विवरण मांगा है। मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों को अध्यापक उपलब्ध कराने के लिए जेबीटी, टीजीटी व सीएंडवी अध्यापकों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए, विभाग ने प्रदेश के समस्त जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 31 मई तक विवरण उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा है। आरटीई एक्ट 2009 के नियमों के तहत 30 सितंबर 2019 को स्कूलों में दर्ज विद्यार्थी संख्या के आधार पर जेबीटी, टीजीटी व सीएंडवी अध्यापकों का रेशनलाइजेशन किया जाना है। रेशनलाइजेशन करते वक्त विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को आधार माना जाएगा।

मौलिक शिक्षा हरियाणा द्वारा रेशनलाइजेशन के मानदंड तय किए गए हैं। इस पर हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश मलिक, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रतिनिधि भूप सिंह वर्मा ने बताया कि रेशनलाइजेशन के नियम हाइकोर्ट द्वारा स्थापित नियमों के विपरित हैं। एसोसिएशन शीघ्र स्थानांतरण के पक्ष में है, लेकिन रेशनलाइजेशन बारे सभी जिला कार्यकारिणी और पदाधिकारियों व एसोसिएशन के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि समुचित और एक सर्वमान्य मांग सरकार के सामने रखी जा सके।

सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए शिक्षकों ने शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर से मुलाकात की। इस बैठक में शिक्षकों ने पुराने रेशनलाइजेशन फार्मूले को लागू करने, कैप्ट वेकेंसी को खोलने, प्रमोशन के बाद ही सरप्लस अध्यापकों को समायोजित करने की मांग की।

लॉकडाउन के दौरान निकाले सैकड़ों पीटीआई

सर्व कर्मचारी संघ ने उठाया एतराज

चंडीगढ़। हरियाणा में कर्मचारियों के एक वर्ग की अगुवाई कर रहे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने लॉकडाउन में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में 10 साल से तैनात 1983 पीटीआई को तीन दिनों में नौकरी से निकालने के निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सरकार के इस निर्णय से 1983 पीटीआई एवं उनके परिजनों और समस्त कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया कि 4 जून को प्रदेशभर में होने वाले प्रदर्शनों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने सरकार से 1983 पीटीआई को कार्यमुक्त करने के आदेश को वापस लेने और वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। लांबा ने बताया कि सकसं हरियाणा ने 28 अप्रेल को मुख्यमंत्री के साथ हुई कर्मचारी संगठनों की मीटिंग में इस मामले को गंभीरता से उठाया था। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार नहीं चाहेगी कि किसी की नौकरी जाएं। लेकिन सरकार ने ना तो वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने और न ही 8 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी बैंच चुनौती दी गई और ना ही पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सरकार ने सबसे आसान तरीका निकाला और दस साल से लगे पीटीआई को नौकरी से बाहर निकल दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में भी कहा था कि इस निर्णय को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद 5 महीनों में लागू करें। सरकार ने लॉकडाउन में भी समाप्त नहीं होने दिया।

उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अध्यापकों की मेरिट प्रक्रिया पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाया, सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को दोषी मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। फैसले के पालन में भर्ती प्रक्रिया को बीच में बदलने वाले अधिकारियों व नेताओं को, जिनको भर्ती प्रक्रिया बदलने के कारण लाभ मिला, उन पर कार्रवाई बनती थी न कि 10 वर्षों से मेहनत से सेवा कर रहे शिक्षकों पर कार्रवाई।

हिसार के वैज्ञानिकों ने की श्वांस नली में रुकावट के इलाज के लिए सस्ती तकनीक की खोज

लुवास में स्वनिर्मित इंडोस्कोपिक कैमरे की सहायता से शुरू हुआ उपचार, स्मार्टफोन से हो सकेगी अटैच

पायनियर समाचार सेवा। हिसार

लुवास के वैज्ञानिक डॉ. रामनजर चौधरी ने श्वास नली या खाने की नली में किसी प्रकार के रोग के डायग्नोसिस के लिए बहुत ही सस्ती तकनीक की खोज की है। ये तकनीक बहुत ही सरल व उपयोगी है। इसका प्रयोग फील्ड के डॉक्टर भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं।

लुवास वैज्ञानिकों के अनुसार पारम्परिक इंडोस्कोपिक यूनिट काफी महंगी व जटिल बनावट की होती है, जिसका अनुमानित लागत करीब 50 लाख रुपये है। इसको फील्ड में गांव-गांव ले जाना भी मुश्किल है एवं इसके उपयोग के लिए बिजली का होना अर्निवार्य होता है। इसका संचालन करने के लिये एक कुशल इंडोस्कोपी प्रशिक्षित डॉक्टर की आवश्यकता होती है। साथ ही उपयोग के दौरान पशु द्वारा मशीन को हानि पहुंचाने की संभावना काफी ज्यादा है। लुवास द्वारा स्वनिर्मित इंडोस्कोपिक यूनिट को बनाने की कीमत मात्र 1500 रुपये है। इसको किसी भी स्मार्टफोन के साथ जोड़ कर चलाया जा सकता है। हालांकि इसमें सुधार की अभी और गुंजाइस है परन्तु लुवास द्वारा इसको नाक, मुंह, खाने एवं श्वास की नली के विभिन बीमारियों के पहचान के लिए

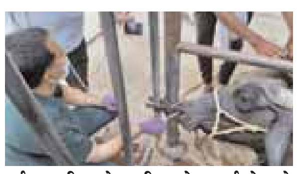

नई तकनीक से मशीन को स्मार्टफोन से जोड़कर एक भैंस का उपचार करते लुवास के वैज्ञानिक व चिकित्सक।

उपयोग में लाया जा रहा है। इसको जलरोधी कैमरे को आवश्यकतानुसार संशोधन करके बनाया गया है। इससे प्राप्त जानकारी (चित्र एवं फिल्म) को संचय करने की भी सुविधा है। डॉ. चौधरी के इस खोज को रिसर्च रिव्यु कमेटी के सामने भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसे डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ने काफी सराहा। इसके परीक्षण में डॉ. सतबीर, डा. संदीप गोयल एवं डॉ. रामनिवास का भी सराहनीय योगदान रहा।

शुक्रवार को इस यूनिट का इस्तेमाल करके भैंस की नाक में ग्रेन्युलोमा नामक बीमारी का आसानी से पता लगा कर इसका इलाज शुरू किया है। इस बीमारी के कारण भैंस के नाक से कई दिनों से खून बह रहा था व बीमारी नाक के अंदरूनी हिस्से में होने के कारण, खून स्त्रोत का पता ही नहीं चल रहा था। इससे पहले भी कई पशुओं में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। ये तकनीक बहुत सस्ती है और फील्ड में भी इसे आसानी से लागू किया जा सकता है।

इसके प्रयोग से हरियाणा के पशुपालकों को काफी फायदा पहुचेगा और शीघ्र ही लुवास विश्वविद्यालय इस इंडोस्कोपिक यूनिट के प्रशिक्षण की व्यवस्था हरियाणा के वेटरनरी सर्जनों के लिए करेगा ताकि वो फील्ड में इसका सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकें।

मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पंजीकरण दोबारा खोला जाए

कुरुक्षेत्र। भाकियू ने हरियाणा में मक्का व सूरजमुखी की फसल की सरकारी खरीद शुरु करवने और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण खोलने की मांग की है। मांग को लेकर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से निवेदन किया है किसानों की मक्का व सूरजमुखी की फसल पक कर तैयार हो चुकी है और मंडियों में आने भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा सरकार के कथन अनुसार 1 जून से मक्का व सूरजमुखी की खरीद शुरू करने की व्यवस्था पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मक्का व सूरजमुखी की फसल की ज्यादा आवक होती है।

सरकार का पोर्टल बंद!

किसान नहीं करवा पाए सूरजमुखी व मक्का फसल का पंजीकरण

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने प्रदेश में सूरजमुखी व मक्का की पैदावार करने वाले किसानों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल को चिट्ठी लिखकर किसानों के सामने पेश आ रही समस्याओं को खत्म किए जाने की मांग की है।

भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूंनी ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश में मक्का व सूरजमुखी की फसलें पक्की होकर तैयार हो चुकी हैं और मंडियों में आने भी शुरू हो चुकी हैं। इस लिए सरकार को तुरंत ही एक जून से मक्का व सूरजमुखी की खरीद शुरू करने की व्यवस्था पूरी कर लेनी चाहिए ताकि किसानों को आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत न आए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में मक्का व सूरजमुखी की फसल की ज्यादा आवक होती है परंतु वह सरकारी खरीद सेंटर न होने के कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे किसानों का भारी अर्थिक नुक्सान होता है उन जिले की सभी मंडियो में मक्का और सूरजमुखी का खरीद सेंटर बनाया जाए।

चढ़ूंनी ने आरोप लगाया है कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर भारी मात्रा में किसान अपनी मक्का व सूरजमुखी फसल दर्ज नहीं करवा पाए जिसका बड़ा कारण है फसल बीजाई से पहले ही पोर्टल का बन्द होना अभी किसानों ने पूरी फसल की बिजाई भी नही कर पाए थे की विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल को बन्द कर दिया इसके अलावा भी भारी मात्रा में सरसों के खेत में सूरजमुखी की फसल का पैदावार होती है ओर यदि किसान चालू पोर्टल में सूरजमुखी की फसल पंजीकरण करवाता तब उसकी सरसों की फसल बिकने से रह जाती क्योंकि सरसों व सूरजमुखी का पंजीकरण एक ही समय पर दर्ज हो रहा था इसलिए किसान ने सूरजमुखी की फसल का पंजीकरण से वंचित रह गए अब उन्होंने सूरजमुखी की फसल उगाई हुई है ओर उनकी फसल पोर्टल पर दर्ज नही है कृपा मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल को जल्द से जल्द चालू किया जाए।

खेड़ी मारकंडा में महिला मिली पॉजिटिव

पायनियर समाचार सेवा। कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र जिले से एक महिला का सैम्पल कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। जिले में अब तक कोरोना वायरस के 27 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, इनमें से 13 मरीज ठीक होकर अपने-अपने घर जा चुके हैं और 14 एक्टिव केस है। जिला सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने शुक्रवार देर सायं जारी एक हेल्थ बुलेटिन में कहा कि खेड़ी मारकंडा में उतर प्रदेश से एक परिवार के कुछ लोग 26 मई को पहुंचे थे, इन सभी का 27 मई को सैम्पल लिया गया और एक 22 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

इस महिला की चैन में 16 सैम्पल लिए गए है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को 435 सैम्पलों की रिपोर्ट एक साथ पहुंची है, इनमें से 434 सैम्पलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

सीएमओ डा. सुखबीर सिंह

उन्होंने बताया कि अजराना खुर्द के 27 व 25 वर्षीय युवकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन मरीजों को ठीक होने पर आदेश मेडिकल कालेज व अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ ही गांव घुराला, गांव बकाली और लाडवा के वार्ड 9 सैनी मोहल्ला व वार्ड नम्बर 11 के कोरोना पॉजिटिव मरीज भी ठीक हो गए है। इन चारों को मुलाना मेडिकल कालेज व अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, इस प्रकार कुरुक्षेत्र से एक ही दिन में 6 मरीजों को रिकवर होने पर छुट्टी दे दी गई है। इस समय 14 एक्टिव केस मुलाना मेडिकल कालेज में उपचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में दिसम्बर माह से लेकर अब तक कुल 2376 लोग आए है, इनमें से 2349 लोग स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार 28 दिन का समय चक्र पूरा कर चुके है और 5 व्यक्तियों को होम क्वांरटाइन किया गया है तथा 22 को होटल में क्वांरटाइन किया है। उन्होंने कहा कि 14 लोगों को मुलाना मेडिकल कालेज में दाखिल करवाया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के लिए इस जिले से अब तक 5463 सैम्पलों में 5175 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और 261 सैम्पलों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। इस जिले में अब तक 27 पॉजिटिव केस सामने आ चुके है।

आरटीआई में हुड्डा विभाग की खुली पोल

कैथल। केंद्र व राज्य सरकारें भले ही सफाई को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है और इसके लिए करोड़ों व अरबो रुपयों की योजनाये भी चलाती है पर आज उनके सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है क्योंकि बात जब धरातल की आए तो सचाई कुछ और ही सामने आती है। ऐसी ही एक पोल आर.टी.आई एक्टिविस्ट जयपाल रसूलपुर ने कैथल के हुड्डा विभाग की खोली है जिसमे पता चला है की हुड्डा विभाग ने कैथल के सेक्टर 18 के सीवरेज लाईन की कहीं पर भी कोई निकासी नही की हुई और उल्टा सेक्टर वासियों से सीवरेज बिल के नाम से 199 रुपये चार्ज कर रहे है जो की सरेआम लाखों रुपयों खुली लूट है क्योंकि जब सीवरेज की निकासी ही नहीं तो उसका चार्ज क्यों लिया जा रहा है।

अमेरिका से लौटे हरियाणा वासी पहुंचे पुलिस की शरण में

हरियाणा के 70 लोगों ने थानों में दर्ज कराई एफआईआर

कोई जमीन बेचकर तो कोई कर्ज लेकर गया था अमेरिका

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

अपनी जमीनें गिरवीं रखकर अमेरिका गए हरियाणा वासियों ने इंसाफ के लिए अब पुलिस से गुहार लगाई है। गृहमंत्रालय के निर्देशों पर हरियाणा के 70 लोगों ने प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में उन फर्जी ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

सभी युवक कबूतरबाजों को मोटी रकम देकर गैर कानूनी ढंग से अमेरिका गए थे और वहां पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। अमेरिका ने हालही में हरियाणा के 76 लोगों को डिपोर्ट किया था। इनमें से अधिकतर को एकांतवास में रखा गया है। इनमें से अधिकतर लोग फर्जी ट्रेवल एजेंटों के चंगुल में फंसकर गलत तरीके से अमेरिका पहुंचे थे।

> **मैक्सिको के रास्ते पहुंचाया अमेरिका**
>
> **गृह मंत्री** ने माना कि डिपोर्ट होकर आए इन सभी हरियाणा के युवाओं को गैर कानूनी तरीके से भेजा गया था। उन्हें कभी कभी जंगल में रखा गया तो कभी कश्ती में समुंदर में घुमाया गया। मैक्सिको में जाकर वहां के रास्ते इन लोगों को अमेरिका में उतारा गया। यह लोग डालर कमाने वहां गए थे। उनके मां बाप और भाई बहनों की आंखों में कई तरह के सपने थे। कुछ ने रिश्तेदारों से कर्ज लिए थे। कुछ ने ब्याज पर पैसा उठाया था और वहां जाकर यह युवक जेल चले गए। हमने सभी की एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सभी एफआइआर दर्ज होने के बाद इन कबूतरबाजों को हिरासत में ले लिया जाएगा।

इस मामले की जांच हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल द्वारा की जा रही है।

अब तक हुई जांच में पता चला कि डिपोर्ट होकर लौटने वालों में से कोई अपना मकान बेचकर विदेश गया था तो किसी के मां-बाप ने प्लाट, दुकान और जमीनें बेचकर अपने लाडलों को डालर कमाने के लिए विदेश भेजा था।

गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में बताया कि इस मामले में अब तक 70 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। सभी युवक एफआईआर में उन तमाम लोगों के नाम लिखवा रहे हैं, जिन्होंने उन्हें विदेश भेजा और उसके बदले में पैसे लिए। प्रत्येक व्यक्ति के नाम से एफआईआर हो रही है और उसमें ही कबूतरबाजों द्वारा ली जाने वाली रकम का उल्लेख है। गृह मंत्री ने बताया कि हरियाणा में कई गिरोह सक्रिय हैं। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव से कहा गया है कि सभी ऐसे लोगों की सूची उन्हें सौंपी जाए, जो विदेश भेजने का काम करते हैं। इनमें ऐसी सूची भी तलब की गई है, जो अवैध ढंग से लोगों को विदेश भेजते हैं।

इन संख्या सैकड़ों में हो सकती है। गृह मंत्री के अनुसार हरियाणा सरकार अब ऐसे लोगों का भी पता लगाने में जुटी है, जो विदेश गए हुए हैं। हरियाणा के विदेश गए तमाम लोगों की सूची तलब की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि कौन व्यक्ति किस एजेंट के जरिये किस काम के लिए किस देश में गया हुआ है।

हनी ट्रैप मामले में दो महिला समेत चार गिरफ्तार

पलवल। हनीट्रेप मामले में आरएमपी डाक्टर को फंसाकर दो लाख रुपये मांगने के आरोप में अमरपुर चौकी पुलिस ने दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

पलवल अमरपुर चौकी इंचार्ज प्रीतम ने बताया कि गांव बलई निवासी शिवकुमार ने 23 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता विष्णू आरएमपी डॉक्टर है और वे अमरपुर चौक पर दुकान करते हैं। प्रतिदिन की तरह पीड़ित के पिता 23 मई को जब घर नहीं पहुंचे तो पीड़ित ने दुकान पर आकर देखा। दुकान बंद थी और बाहर बाइक खड़ी हुई थी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 26 मई को विष्णु ने अपने पुत्र शिवकुमार के पास फोन कर दो लाख रुपये लेकर आने की बात कही। शिवकुमार ने रुपये वाली बात पुलिस को बताई तो पुलिस के शक की सुईं कहीं और घुमी। टीम गठित कर फोन के आधार पर दबिश दी गई तो एक कमरे से विष्णु को बरामद किया।

पलवल में 2.77 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई गेहूं की खरीद : डीसी

डीसी नरेश नरवाल ने दी जानकारी, जिला प्रशासन द्वारा खरीद किसानों को भुगतान व मंडियों से उठान की नियमित रूप से की जा रही मॉनिटरिंग

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान पलवल जिला की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी है। जिला में मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत 21503 किसानों से दो लाख 77 हजार 545 मीट्रिक टन अनाज की खरीद हो चुकी है। खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद के साथ-साथ किसानों को भुगतान व मंडियों से उठान का कार्य भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

उपायुक्त नरेश नरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल जिला में गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से आरंभ हुई थी। उन्होंने किसानों को होने वाले भुगतान के लिए आढ़तियों से भी खरीद एजेंसियों को दी जाने वाली जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर जल्द भेजने की बात कही ताकि किसानों को भुगतान समय पर हो सके। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक राम अवतार सिंह ने एजेंसीवार खरीद की बताया कि जिला में अब तक हैफेड ने 7806 किसानों से एक लाख 758 मीट्रिक टन, हरियाणा वेयरहाउस कार्पोरेशन ने 6178 किसानों से 76039 मीट्रिक टन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 2806 किसानों से 41934 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 4713 किसानों से 58814 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। जिला की मंडियों से अब तक एक लाख 97 हजार 762 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदना सरकार की प्रतिबद्धता है साथ ही भुगतान प्रक्रिया की भी नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

नगर परिषद थानेसर ने लोगों के हितों पर किया कुठाराघात

कुरुक्षेत्र। आप पार्टी के जिला संयोजक, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ता जवाहर लाल गोयल ने कहा कि नगर परिषद थानेसर अपनी मनमानी कर रही है। मनमर्जी से लोगों पर बेवजह बोझ डाला जा रहा है। कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए शुल्क पर नप अधिकारियों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सरासर शहर के लोगों के साथ अन्याय है। नगर परिषद के चुनाव में नप चेयरपर्सन उमा सुधा व विधायक सुभाष सुधा ने लोगों को आश्वासन दिया था कि कूड़ा उठान के लिए शहर वासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब शुल्क लगाकर लोगों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार जहां किरायेदारों से किराया नहीं लेने की बात कह रही है, दूसरी ओर नप कूड़ा शुल्क लगा कर संकट की इस घड़ी में लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। कोरोना वायरस के चलते लोगों के काम धंधे चौपट हो चुके हैं। लोगों के सामने दो जून की रोटी का जुगाड़ करने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन नप अधिकारियों को लोगों की चिंता नहीं है। उन्होंने नगर परिषद के 10 पार्षदों द्वारा कूड़ा उठान शुल्क लगाने के विरोध में दिए गए सामूहिक इस्तीफे पर उनका समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने शहर की जनता के हक में अपने इस्तीफे दिए हैं। नप को कूड़ा उठान शुल्क न लगाने के बारे में जल्द फैसला लेकर लोगों को राहत देनी चाहिए।

पेंशनभोगियों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली

चंडीगढ़। हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय ने राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन से जुड़े मामलों और शिकायतों के निपटान के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है। हरियाणा के प्रधान महालेखाकार विशाल बंसल ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन से जुड़े मामलों के निपटान के लिए शुरू की गई इस विशेष सुविधा के तहत संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों को ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, ट्रेजरी और पेंशनर को पेंशन प्राधिकार ऑनलाइन भेजे जाएंगे। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी अपने स्तर पर अपनी यूजर आईडी से पेंशन प्राधिकार स्वयं भी प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा के लिए पेंशनर को अपने स्तर पर इस प्रणाली पर स्वयं का पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी इस कार्यालय से टोल फ्री नम्बर 18001023292 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली पर अपने मोबाइल नम्बर द्वारा अपना पंजीकरण करवाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगी को शिकायत के निवारण की जानकारी उसके मोबाइल के साथ-साथ शिकायत निवारण प्रणाली पर भी दी जाएगी।

विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

इन्द्री। पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर की गई धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी अनुसार पुलिस को दी शिकायत में गांव खेड़ी मानसिंह के रहने वाले राहुल ने बताया है कि इसराना जिला पानीपत के रहने वाले ओमप्रकाश ने उसकी मुलाकात गांव पिचोलिया जिला करनाल के रहने वाले कुलदीप से करवाई थी।कुलदीप ने राहुल को कहा कि तुम बाहर जाकर 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हो।इसके लिए तम्हारे 20 लाख रुपये लगेंगे।जो तुम्हें जॉब लगने के बाद देने होंगे।जो पिछले वर्ष 24 जनवरी को राहुल इकाडोर के लिए दिल्ली से रवाना हुआ परंतु गवाटामाला पहुंचने पर उसे हथियारों से लैस 5 से 6 डोंकरो ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि एजेंट को 20 लाख नही दोगे तो हम तुम्हे जान से मार देंगे। राहुल के घरवालो ने 20 लाख एजेंट कुलदीप को दे दिए जिसके बाद उसे गवाटामाला से मैक्सिको तो पहुंचा दिया गया परंतु मैक्सिको से कैलिफोर्निया में एंट्री करते समय उसे पुलिस ने पकड़ लिया और काफी समय तक जेल में रखा। पुलिस ने राहुल की शिकायत पर कुलदीप के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। राहुल के अनुसार करीब 10 दिन मैक्सिको में रहने के बाद उसके पास एक फोन आया ओर कहा कि मै तुम्हे कैलिफोर्निया पहुंचा दूंगा। जिसके बाद चार डोंकरो ने उसे कैलिफोर्निया पहंचा दिया। परंतु कैलिफोर्निया में दीवार कूदते हुए उसे पुलिस ने पकड़ लिया। कंई दिनों तक जेल में रखने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जहां जज ने राहुल से पासपोर्ट दिखाने को कहा तो राहुल ने बताया कि उसका पासपोर्ट डोंकरो ने छीन लिया था। जिस पर जज ने उसका केस इमीग्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया। इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसको व्हाइट पासपोर्ट जारी कर इंडिया भेजा। इस मामले में थाना प्रबंधक सतपाल का कहना है कि राहुल की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।हर एंगल से केस की जांच की जा रही है।जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे।

उपायुक्त ने एलएनजेपी अस्पताल के नए भवन का किया मुआयना

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि एलएनजेपी अस्पताल के अधिकारियों और चिकित्सकों की सभी जरुरतों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक अधिकारी और चिकित्सक से प्रशासन की तरफ से बारीकि से फीडबैक ली गई है। वे शुक्रवार को एलएनजेपी अस्पताल के नए भवन का मुआयना करने के उपरांत एलएनजेपी अस्पताल के अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। इससे पहले उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा, अंडर ट्रेनिंग आईएएस वैशाली सिंह ने एलएनजेपी अपस्ताल के नए भवन का मुआयना किया। उपायुक्त ने ओपीडी के साथ-साथ अन्य कक्षों को भी देखा और सीएमओ डा. सुखबीर सिंह, मेडिकल सुपरीडेंट डा. शैलेन्द्र शर्मा ममगई आदि अधिकारियों और चिकित्सकों से बातचीत कर अस्पताल में चिकित्सकों और अधिकारियों की जरूरतों के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में और अधिक सुधार लाने के सम्बन्ध में जो फीडबैक मिला है। उसके अनुसार अधिकारियों और चिकित्सकों की जरूरतों और अस्पताल की कमियों को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सकों को अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डा. एनपी सिंह, डा. एसएस अरोड़ा सहित अन्य चिकित्सक व अधिकारी मौजूद रहे।

अध्यापक संघ ने मनाया काला दिवस

कैथल। पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राजनीति का शिकार, शिक्षकों के रोजगार जाने की नौबत को लेकर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने जिला स्तरीय 'काला दिवस' मना कर धरना प्रदर्शन कर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कैथल शमशेर सिरोही के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया। काला दिवस रोष धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान विजेंद्र मोर ने और संचालन जिला सचिव रामपाल शर्मा ने किया। राज्य सचिव कंवरजीत, बसाऊ राम, शारीरिक शिक्षक संघ के जिला प्रधान नरेश भनवाला व रमेश डीपी ने बोलते हुए कहा कि पूरे फैसले में पीटीआई का कोई दोष नहीं है। सारा दोष न्यायालय ने भर्ती एजेंसी को ठहराया है, तो इसकी सजा भी भर्ती एजेंसी को ही मिलनी चाहिए न 10 वर्षों से कार्यरत 1983 शारीरिक शिक्षकों को। उन्होंने कहा सरकार को चाहिए कि 68 पेटीशनर को समायोजित करते हुए सब की सेवा सुरक्षा की की जानी चाहिए। राज्य सचिव सतबीर गोयत, जिला प्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश कुंडू, रोशन लाल व शारीरिक शिक्षिका गुरमीत कौर ने सरकार से अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करते हुए अध्यादेश जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उनकी सहायता की जगह सरकार रोजगार छीनने पर तुली हुई है। कोर्ट ने भी लॉकड़ाउन समाप्त होने के बाद 5 महीने का समय दिया हुआ है। अगर सरकार चाहती और उसकी मंशा साफ होती तो इनका हल निकालना मुश्किल नहीं था।

पायनियर
नई दिल्ली, शनिवार, 30 मई 2020

नोएडा, ग्रेनो और गाजियाबाद के बिल्डरों के साथ करार

मुख्यमंत्री योगी का एलान-उत्तर प्रदेश लौटे ढाई लाख श्रमिकों को देंगे रोजगार

रिंकु यादव। नोएडा

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश के श्रमिक वापस लौटकर आए हैं। श्रमिक अपने गांव पहुंच गए हैं और इन्हें बहुत जल्दी काम की जरूरत होगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिशों में लगी है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डरों की संस्था नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (नरेडको), भारतीय उद्योग परिसंघ और देश के एमएसएमई उद्यमियों की अग्रणी संस्था इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के साथ एमओयू साइन किए हैं।

इन तीनों एमओयू के तहत साढ़े नौ लाख श्रमिकों को रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे। सुपरटेक के एमडी और नरेडको उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आरके अरोड़ा के नेतृत्व में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र और गाजियाबाद के बिल्डर गुरुवार को लखनऊ पहुंचे। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आरके अरोड़ा ने कहा, नरेडको रियल्टी क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों को रोजगार देगा। गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में काम शुरू करने के लिए ढाई लाख श्रमिकों की आवश्यकता है। अगर सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं तो यह संख्या चार लाख तक पहुंच जाएगी। अभी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने में बिल्डरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एमओयू का आदान-प्रदान करते बिल्डर। फोटो : दीपक यादव

आरके अरोड़ा ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों से लौटकर आए मजदूरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार की योजना है कि अपने राज्य के श्रमिकों को अपने ही राज्य में काम दिया जाए। हम इसके लिए सरकार के साथ खड़े हैं। हम भी यही चाहते हैं कि राज्य के प्रत्येक काम करने योग्य व्यक्ति के पास काम होना चाहिए। हम लोगों ने सरकार से लिखित समझौता किया है। वह हमें ढाई लाख श्रमिक उपलब्ध करवाएंगे और हम उन्हें काम देंगे। दूसरी ओर देश में एमएसएमई उद्यमियों की सबसे बड़ी संस्था आईआईए ने लगभग पांच लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार का सृजन करने की जिम्मेदारी ली है।

सीआईआई ने दो लाख श्रमिकों को रोजगार देने में मदद करेगा। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि समझौता ज्ञापन नौकरियों का पता लगाने और श्रमिकों को वर्गीकृत करने में मदद करेगा। ये एजेंसियां कुशल प्रवासी श्रमिकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण भी सुनिश्चित करेंगी। सरकार श्रमिकों को शिक्षुता भत्ता भी प्रदान करना चाह रही है।

नाइट कर्फ्यू में गंभीर के पिता की एसयूवी चोरी

नई दिल्ली। लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली में शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। इसके बावजूद चोर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज ओपनर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर के पिता की एसयूवी कार पर हाथ साफ करने में कामयाब हो गए। यह चोरी गुरुवार तड़के हुई। इस मामले में दिल्ली के राजेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच में जुटी है। चूंकि मामला बीजेपी सांसद से जुड़ा हुआ है, लिहाजा जिला पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। डीसीपी सेंट्रल के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए चोरों की सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। गौतम गंभीर अपने पिता के साथ ही रहते हैं।

पुलिस उपायुक्त संजय भाटिया के अनुसार पुलिस को भाजपा सांसद गौतम गंभीर के घर से फॉर्च्यूनर कार के चोरी होने की सूचना मिली थी। एसएचओ इस बाबत ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित उनके घर गए थे। यह कार गंभीर के पिता दीपक गंभीर की है।

संक्षिप्त समाचार

रेल मंत्रालय की यात्रियों से अपील

नई दिल्ली। भारतीय रेल, देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, ताकि प्रवासियों की अपने घरों को वापसी सुनिश्चित की जा सके। यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड़-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी मिले हैं। ऐसे में कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-छरू-द्य(ं) दिनांक 17.05.2020 के तहत, अपील की है पूर्व ग्रसित बीमारी (जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्करोग, कम प्रतिरक्षा) वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा करने से बचें।

चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि

गाजियाबाद। पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौ. चरण सिंह को उनकी 33वीं पुण्यतिथि पर गाजियाबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील दत्त त्यागी के नेतृत्व में बार पदाधिकारी व वकीलों ने किसान नेता को अपनी श्रद्धांजलि दी। बार अध्यक्ष ने कहा कि चौ. चरण सिंह ने किसानों के हित के लिए ताउम्र कार्य किए। वे कहा करते थे कि भारत का तब तक विकास नहीं हो सकता है, जब तक किसानों का विकास नहीं होगा। देश की खुशहाली का रास्ता खेतों से होकर जाता है। सपा अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष रमेश यादव एडवोकेट ने कहा कि चौ. चरण सिंह के बताए रास्ते पर चलकर ही किसान और कृषि का विकास हो सकता है। इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव विजय गौड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरप्रीत सिंह जग्गी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।

'लॉकडाउन ने ऑनलाइन कामकाज को गति दी'

नई दिल्ली। हंसराज कॉलेज में 'कामकाज के बदलते तौर तरीके और तकनीक' विषय पर गूगल मीट के माध्यम से राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था। इसे हंसराज कॉलेज के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव भी प्रसारित किया गया। सत्र के वक्ता बालेन्दु शर्मा दधीच, निदेशक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया थे। हंसराज कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रमा के वक्तव्य के साथ सत्र की शुरुआत की गई और सत्र का संचालन और समन्वय हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. विजय कुमार मिश्र ने किया। बालेंदु ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण हमने डिजिटल तकनीक को काफी तेजी से अपनाया है। लॉकडाउन ने ऑनलाइन कामकाज के तरीके को गति दी है। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक डॉ. विजय कुमार मिश्र ने बालेन्दु दाधीच, प्रो. रमा और देशभर से सहभागिता कर रहे प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

सैलून खोलने की मांग को लेकर दिया ज्ञापन

गाजियाबाद। एकता बारबर एसोसिएशन ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर सैलून खुलवाने की मांग की है। अपने ज्ञापन में संचालकों ने शर्तो के साथ सैलून खोलने की अनुमति मांगी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुस्तकिम सलमानी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण बंद चल रहे सैलून विशेषकर छोटे सैलून संचालक भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं।

वीडियो से दी जानकारी-कैसे रहें होम क्वॉरंटीन

● पन्द्रह मिनट के वीडियो में बताए गए हैं सावधानी के उपाय

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केजरीवाल सरकार ने वीडियो से जानकारी दी कि होम क्वारंटीन में कैसे रहें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 80 फीसदी से ज्यादा मामलों में कोरोना के मरीज में कोई लक्षण नहीं होते या बहुत ही मामूली होते हैं, जैसे मामूली बुखार, खांसी। ऐसे लोगों को अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत नहीं होती है। मरीज अपने घर में ही खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं।

घर में रहकर क्या करना है। एहतियात क्या बरतनी है। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 15 मिनट का वीडियो जारी कर उसमें जरूरी दिशा-निर्देश दिया है। इस वीडियो में मरीज के साथ-साथ देखभाल करने वाले और पड़ोसियों के लिए भी निर्देश हैं। देश में पहला मौका है, जब दिल्ली सरकार कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन कैसे करते हैं, यह समझाने को वीडियो जारी किया है।

डॉक्टरों के मुताबिक जिनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं या मामूली लक्षण हैं, ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है।

सीएम बताएं-तेजी से क्यों बढ़े कोरोना केस : भाजपा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा है। भाजपा नेता ने कहा कि सभी तरह के स्वास्थ्य इंतजाम का दावा करने वाले मुख्यमंत्री जवाब दें कि दिल्ली में अचानक से कोरोना वायरस के मामले तेजी से क्यों बढ़ गए।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। केजरीवाल लोगों को संक्रमण से सुरक्षित करने के बजाय अपना सारा ध्यान विज्ञापन के जरिए खुद को चमकाने पर केंद्रित रखा है।

एक जून से दिल्ली मेट्रो चलाने का दबाव

राष्ट्रीय राजधानी में खुल सकते हैं सलून और जिम, मार्च से हैं बंद

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

रेल और घरेलू उड़ानों व डीटीसी बसों के शुरू होने के बाद एक जून से राजधानी दिल्ली में मेट्रों चलाने का दबाव है। इसके परिचालन से लोगों को अपने गंतव्य तक आने जाने में में आसानी होगी। इसके मद्देजन दिल्ली मेट्रो रेल निगम दोबारा मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लिया है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है।

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद डीएमआरसी परिचालन शुरू करने की तारीख का ऐलान करेगा। साथ ही यात्रा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। बीमारी को फैलने से बचाने के लिए उन उपायों को सख्ती से लागू करेगा। सफर के दौरान मेट्रो में एक सीट छोड़कर नहीं बैठने पर यात्रियों पर जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि नियम लागू करने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग क पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।

मॉक ड्रिल कर ट्रेन चलाने का लिया जायजा

नोएडा। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) ने मेट्रो रेल चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत शुक्रवार को एनएमआरसी के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल कर ट्रेन चलाने की तैयारियों का जायजा लिया। एनएमआरसी की मीडिया प्रभारी संध्या शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते नोएडा मेट्रो रेल के परिचालन को 31 मई तक बंद किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय नगर विकास मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को सूचित किया गया है, कि वे मेट्रो संचालन की तैयारी पूरी रखें।

स्कूल ने नहीं दिया अपने कर्मचारियों को वेतन

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उनकी मासिक वेतन दिलाई जाए।

कर्मचारियों ने बताया कि स्कूल ने अप्रैल माह की 40 फीसदी सैलरी देने के बाद यह कहकर टरका दिया कि अगर अभिभावक फीस का भुगतान करते हैं तो उनकी बाकी की सैलरी दे दी जाएगी। स्कूल द्वारा शिक्षणकार्य जारी है वहीं अभिभावकों फीस भी दे रहे हैं। बावजूद इसके उनकी सैलरी को लेकर मैनेजमेंट सिर्फ आश्वासन दे रहा है।

दादरी रेलवे स्टेशन पर अपने घर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ते प्रवासी मजदूर।

नोएडा से 77,803 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उनके गृह नगर

नोएडा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन की वजह से गौतमबुद्ध नगर में फंसे विभिन्न राज्यों के रहने वाले 77,803 प्रवासी मजदूरों को पिछले 11 दिनों में जिला प्रशासन ने ट्रेनों से उनके गृह नगर भेजा है। वहीं विभिन्न प्रांतों के रहने वाले करीब 45,000 लोगों को जिला प्रशासन ने बस से उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा है।

जेवर के तहसीलदार दुर्गेश सिंह ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए जिला प्रशासन ने 16 मई से श्रमिक ट्रेनें चलवाई।

तबलीगी जमात पर सीबीआई का शिकंजा, शुरू की जांच

नई दिल्ली। सीबीआई ने तबलीगी जमात पर शिकंजा कस दिया है। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर संदिग्ध लेन-देन करने और विदेशी चंदा लेने की बात अधिकारियों से छिपाने को लेकर जमात के आयोजकों के खिलाफ शुरूआती जांच शुरू कर दी है।

दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मार्च के पहले पखवाड़े में तबलीगी जमात के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले इसके कई सदस्यों के कोविड-19 से संक्रमित होने की खबरें मीडिया में सुर्खियों में रही थी।

बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, मौत

● शव कार में रखकर ले जा रहा था ठिकाने लगाने, हुआ गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

एक कार चालक ने मोटर साईकिल में टक्कर मार दी जिसमें उस पर सवार एक इंजीनियर की मौत हो गई जबकि उसके साथ काम करने वाली युवती घायल हो गई।

टक्कर मारने के बाद कार चालक घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय इंजीनियर के शव को कार में डालकर उसे ठिकाने लगाने के लिए जाने लगा लेकिन, कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद उसका एक अन्य वाहन से फिर एक्सीडेंट हो गया जिसके बाद मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

एनएच-9 पर कार की टक्कर लगने से बाइक सवार कंपनी के सीनियर इंजीनियर की मौत हो गई वह नंदग्राम में रहने वाला मंशा पाल का बेटा ज्ञान चन्द्रपाल था जो नोएडा 63 में स्थित यूकेबी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीनियर इंजीनियर था। गुरुवार रात में वह मोटर साईकिल से घर लौट रहा था। उसके साथ कंपनी में काम करने वाली सहयोगी संगीता निवासी शिवपुरी विजयनगर भी थी। जैसे ही वह एनएच-9 पर शनि मंदिर के निकट पहुंचे तो उन्हें एक कार ने टक्कर मार दी।

दुर्घटना में ज्ञान चन्द्रपाल की मौत हो गई, जबकि संगीता घायल हो गई। इसके बाद कार चालक परविंदर निवासी ग्रेटर नोएडा अपनी जान बचाने को लेकर शव को गाड़ी में डालकर ठिकाने लगाने के लिए चल दिया। एबीईएस कॉलेज के निकट कार से दूसरा एक्सीडेंट होने पर लोगों ने कार चालक को दबोचा।

बारिश-ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज

शुक्रवार शाम को लगातार दूसरे दिन हुई बरसात से मिली भीषण गर्मी से राहत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन शाम को बारिश हुई। बारिश के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। बूंदाबांदी के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

स्काइमेट के प्रमुख मौसम विज्ञानी महेश पलावत ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने से दिल्ली के मौसम में परिवर्तन आया। नमी वाली हवा के चलने से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूर्वानुमान जताया है कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी शुक्रवार से और कम होगी। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शनिवार को भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री तक भी जा सकता है।

इससे पहले गुरुवार को भीषण गर्मी से राहत मिली थी। शाम को 7 बजे के बाद दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी शुरू हुई। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम वैज्ञानिक आरबी सिकेरा ने बताया कि हफ्ते भर बाद तापमान में गिरावट आयी है।

बुधवार को 47 डिग्री सेल्सियस से तापमान बृहस्पतिवार को 40 डिग्री सेल्सियस आ गया है। न्यूनतम तापमान भी 27 डिग्री सेल्सियस रहा है। बूंदाबांदी के कारण वातावरण में नमी भी 39 फीसद रही। मध्यम हवा भी पूर्व से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बही। वहीं हवा के झोके की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे रही।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में

50 साल के व्यक्ति का तीन बार लिया कोरोना सेंपल

पहले तो इस व्यक्ति को बिना रिपोर्ट आए ही किया जा रहा था आइसोलेशन

गुरुवार को दोबारा रिपोर्ट लेने पहुंचा तो फिर से ले लिया सेंपल

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

आखिर स्वास्थ्य विभाग को हो क्या गया है। जिस कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया प्रभावित है। डरी हुई है, उस बीमारी को विभाग शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा, जितना लेना चाहिए। तभी तो यहां से लोगों के दो-दो बार सेंपल लेने के बाद भी उनकी रिपोर्ट का कुछ अता-पता नहीं है।

एक ही व्यक्ति के साथ विभाग ने एक तरह से खिलवाड़ कर दिया है। सेंपल देने के बाद उसे घर में क्वारंटाइन (अज्ञातवास) में भेज दिया जाता है। इससे उसका जीवन, जॉब प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को तीसरी बार उस व्यक्ति का कोरोना सेंपल लिया गया, जिसे दूसरी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर सीएमओ कार्यालय की ओर से आईसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। यहां सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में तीसरी बार कोरोना टेस्ट के लिए सेंपल देने पहुंचे 50 साल के व्यक्ति ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया है। पहला सेंपल उनका 18 मई को यहां नागरिक अस्पताल सेक्टर-10 में लिया था। 23 मई को सीएमओ कार्यालय की ओर से उन्हें पॉजिटिव बताकर सेक्टर-9 ईएसआईसी अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में एम्बुलेंस में बैठाकर भेज दिया। वहां कागज जांचने पर पता चला कि कागजों में गड़बड़ी है। वापस सेक्टर-10 अस्पताल पहुंचे और दिनभर भटकने के बाद रात करीब 8 बजे बताया गया कि वह रिपोर्ट उसके नामराशि किसी अन्य व्यक्ति की है।

मतलब उसे किसी और की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग ने आईसोलेशन करने की घोर लापरवाही की। उसे अगले दिन रविवार को फिर से सेंपल देकर जाने को कहा। खैर, पीड़ित ने गत रविवार 24 मई को सेंपल दिया और उसे तीन दिन बाद का समय दिया। वह शुक्रवार सुबह जब वह सेक्टर-10 नागरिक अस्पताल में अपनी रिपोर्ट का पता करने पहुंचा। वहां जवाब सुनकर वह निराश हो गया। उसे बताया कि उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। दोबारा से सेंपल देना पड़ेगा। पीड़ित ने कहा कि दोबारा से नहीं यह तीसरी बार सेंपल होगा। आखिर उसके सेंपल गायब क्यों हो रहे हैं। इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

काम-धंधा हो रहा है प्रभावित, घर में परेशानी

पीड़ित 50 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि वह अपना काम-धंधा छोड़कर घर बैठा है। घर में खाने की भी अब समस्या आ रही है। क्योंकि हर बार सेंपल लेकर उन्हें घर में क्वारंटाइन रहने को कह दिया जाता है। दो बार वह घर में क्वारंटाइन हो चुका है। एक ही कमरे के घर में वह एक कोने में रहता है। घरवाले दूर से ही उसे खाना देते हैं। सभी नियमों को वह मानते हुए घर से बाहर भी नहीं निकलता। बार-बार उसका सेंपल गायब कर दिया जाता है।

खेल विभाग के कर्मचारी की पॉजिटिव रिपोर्ट पर भी लापरवाही

रिपोर्ट पॉजिटिव बताकर कह दिया अब जाओ

कायदे से एम्बुलेंस बुलाकर भेजना था आइसोलेशन सेंटर

गुरुग्राम। स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही शुक्रवार को उजागर हुई। यहां के जिला खेल विभाग कार्यालय का एक कर्मचारी अपने कोरोना सेंपल की रिपोर्ट का पता लगाने पहुंचा। उसका कहना है कि पहले तो उसे नेगेटिव बता दिया और बाद में कहा कि पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपोर्ट बताने के बाद उसे क्या करना है, क्या नहीं। इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई।

यहां नेहरू स्टेडियम स्थित खेल विभाग के कार्यालय में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 22 मई 2020 को सेंपल लिया था। उसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई। वह अपनी रिपोर्ट यहां सीएमओ कार्यालय में पता करने गया। कर्मचारी का कहना है कि पहले तो उसे रिपोर्ट नेगेटिव बताई। वह निश्चिंत हो गया, लेकिन दफ्तर जाने के लिए रिपोर्ट की कॉपी चाहिए थे। जिसे देने से मना कर दिया। काफी अनुरोध किया। करीब दो घंटे के बाद उसे यहां पॉजिटिव बता दिया। इससे वह कर्मचारी परेशान हो गया। वह सीएमओ कार्यालय के बाहर ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कायदे से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे विभाग की ओर से एम्बुलेंस में बैठाकर आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। वह सीएमओ कार्यालय के बाहर इधर से उधर घूमता रहा, किसी ने भी उसे यह नहीं कहा कि वह यहीं पर रुके या फिर क्या करे। इसी से पता चलता है कि यहां स्वास्थ्य विभाग कोरोना को कितनी गंभीरता से ले रहा है।

गुरुग्राम में एक ही दिन में कोरोना का शतक, शुक्रवार को आए 115 केस

अब यहां कुल कोरोना पॉजिटिव केस हुए 520

बढ़ते केसों ने बढ़ाई प्रशासन, सरकार की चिंता

गुरुग्राम का रेड जोन में जाने का खतरा मंडरा रहा, लेकिन निर्णय नहीं

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

जिला में शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना पॉजिटिव केसों का शतक लगा। अकेले शुक्रवार को ही 115 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जो कि अब तक के एक ही दिन में कोरोना पॉजिटिव केसों में सबसे अधिक है। अब यहां कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 520 हो गई है।

एक दिन पूर्व गुरुवार को गुरुग्राम में कोरोना के 68 पॉजिटिव केस आए थे, जो कि इस दिन तक के आंकड़ों में सबसे अधिक थे। अब शुक्रवार को एक ही दिन में कोरोना के केसों का शतक पार हो गया। यानी 115 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए। अब यहां कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 520 हो गई है। कभी पूरे प्रदेश में इतने आंकड़े होते थे, लेकिन अब अकेले गुरुग्राम शहर का यह आंकड़ा है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं और बढ़ भी तेजी से रहे हैं, उससे साफ है कि हालात अभी सुधरने की बजाय बिगड़ने हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली तो लोग एक-दूसरे को कोरोना के प्रति जागरुक रहने का ज्ञान बांटने लगे। यह जरूरी भी है कि हम सभी जागरुक हों और दूसरों को भी करें। अब यह जरूरी हो गया है कि बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों का घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बहुत सी सेवाएं हैं, जो कि ऑनलाइन हैं। खरीदारी ऑनलाइन की जा सकती है। यहां तक कि डॉक्टर्स से भी ऑनलाइन ही परामर्श लिया जा सकता है। ज्यादा गंभीर स्थिति हो, तभी बाहर निकलें।

काले बिल्ले लगाकर एक जून को विरोध प्रदर्शन करेगा सर्व कर्मचारी संघ

सोहना। सर्व कर्मचारी संघ कार्यकर्ता एक जून को अपनी मांगों को लेकर काले बिल्ले लगाकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी और गेट मीटिंग की जाएगी।

सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान उमेश खटाना ने बताया कि राज्य सरकार कर्मचारियों की वर्षो से लंबित मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। कर्मचारियों को आश्वासन पर आश्वासन देकर मांगों को पूरा नहीं कर रही है। जिला प्रधान ने बताया कि एक जून को सबडिविजन स्तर पर उनकी यूनियन का कार्यकर्ता और पदाधिकारी एसडीओ कार्यालय परिसर में एक घंटे का विरोध प्रदर्शन करेगा। गेट मीटिंग करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी।

कोरोना पॉजिटिव को घर से निकालने पर मकान मालिक पर एफआईआर

कमरा छोड़ परिवार के साथ रिश्तेदारों के पास दिल्ली जाना पड़ा

गुरुग्राम। कोरोना पॉजिटिव किराएदार से मकान खाली कराने संबंधी मामले में गांव चकरपुर निवासी राजेन्द्र पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की है।

संक्रमित मरीज से मकान खाली कराने का मामला उपायुक्त अमित खत्री के संज्ञान में आने पर उन्होंने गुरुग्राम के एसडीएम जितेन्द्र कुमार को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। बिहार के मधुबनी क्षेत्र के निवासी अजय कुमार ने शिकायत की थी कि वह पिछले 5-6 सालों से गांव चकरपुर के मकान नंबर-263 में किराए पर रहता है। शिकायतकर्ता एक निजी अस्पताल के डाक्टर का ड्राइवर है। उसने बताया कि इसी बिल्डिंग में उसका साला शंकर भी रहता है जो कोरोना पॉजिटिव है। उसके संपर्क में आने के कारण जब अजय कुमार अपने सेंपल की जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई। जिस पर डॉक्टरों ने उसे होम क्वारंटाइन कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार जब इसकी जानकारी मकान मालिक राजेन्द्र को दी तो उसने तुरंत मकान खाली करने के लिए कह दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे अपनी मोटरसाइकिल पर अपने दोनों बच्चों के साथ दिल्ली अपने भाई के घर जाना पड़ा।

गर्मी के मौसम में पशुपालक रखें पशुओं का विशेष ध्यान : विरेंद्र

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

बढ़ती गर्मी के साथ पशु पालकों को अपने पशुओं की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की खास जरूरत है। बदलते मौसम के पशुओं के रहन-सहन के साथ-साथ चारा, पानी पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है। पशुपालन एवं डेरिंग विभाग के उपनिदेशक डा. नरेन्द्र यादव ने बताया कि बढ़ती गर्मी में पशुओं के चारे पर ध्यान न देने से दूध की क्षमता में कमी आ सकती है।

पशुओं पर गर्मी का प्रभाव माह मई में गर्मी बढ़ने से पशुओं के शरीर में पानी के साथ-साथ अन्य खनिज प्रदार्थों की कमी होने लगती है। जिसके कारण पशुओं में बीमारी से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और पशु शारीरिक तौर से कमजोर हो जाते हैं।

उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में पशुओं को छायादार स्थान पर बांधना चाहिए। जमीन के ऊपर रेत डालकर अच्छी तरह से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। यदि पशुओं को कमरे या टिनशेड में बांधकर रखा जाता है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह स्थान हवादार होना चाहिए। पक्की छत के मकान में वेंटिलेटर लगे होने चाहिए। ज्यादा गर्मी पड़ने पर पशुओं को दो-तीन बार स्नान अवश्य कराएं। डा. नरेंद्र यादव ने बताया कि पशुओं में नमक की पूर्ति करने के लिए पशु बाधने के स्थान पर सफाई के साथ-साथ पशुओं की खोर में साबुत सेंधा नमक का बड़ा टुकड़ा अवश्य रखें और समय-समय पर पशुओं को कैल्सियम की उचित खुराक देते रहें। कैल्सियम की कमी से पशुओं में कई बीमारी जन्म ले लेती हैं।

केठेदार की लापरवाही गेहूं भरे कट्टों पर पड़ रही भारी

देवीलाल स्टेडियम में 12 हजार कट्टे गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में गेहूं से भरे 12 हजार कट्टे खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन अधिकारी ने ठेकेदार द्वारा बरती जा रही लापरवाही को लेकर अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है।

सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में गेहूं की सरकारी खरीद की गई थी। हरियाणा वेयर हाउस कार्पोरेशन ने सोहना में मंडियों से गेहूं उठाने का ठेका अनिल मग्गू पलवल निवासी ठेकेदार को सौंपा था, लेकिन ठेकेदार गेहूं से भरे कट्टों को उठाने में लापरवाही कर रहा है। जिसके कारण देवीलाल खेल स्टेडियम में 12 हजार कट्टा गेहूं खुले आसान के नीचे पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार, शनिवार और रविवार में बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि गुरुवार रात हुई हल्की बूंदाबांदी के दौरान गेहूं के भरे कट्टों पर सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में रखे गेहूं भरे कट्टे। नीचे बिखरा पड़ा गेहूं।

कट्टों से गिरकर खराब हो रहा गेहूं : स्टेडियम परिसर में रखे गेहूं से भरे कट्टों में से 60 फीसदी की सिलाई तक नहीं की गई है। जिससे कट्टों का मुंह खुला होने के कारण बारिश का पानी, आंधी से आने से धूल आदि गिर रही है। कट्टों का मुंह खुला होने से जमीन पर गेहूं बिखर रहा है। जो मिट्टी में मिलकर खराब हो रहा है।

चोरी होने की आशंका : देवीलाल स्टेडियम में सुबह चार बजे सब्जी मंडी भी लगती है। जहां पर रात्रि 2 बजे से आढ़ति और किसान सब्जियां लेकर आने लगते हैं। सुबह चार बजे दूर-दराज क्षेत्र से और शहरी दुकानदार अपने-अपने वाहनों को लेकर सब्जी लेने आते हैं। सब्जी मंडी में भीड़ होने और वाहन साथ होने से गेहं के भरे कट्टों की चोरी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कट्टों के पास उनकी रखवाली करने वाला कोइ नहीं होता है।

क्या कहते हैं अधिकारी : हरियाणा वेयर हाउस कार्पोरेशन के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ठेकेदार ने 10 मई को गेहूं के भरे कट्टों को उठाया था। 19 दिन में एक भी कट्टा नहीं उठाया है। जिसके खिलाफ अपने अधिकारियों को लिखित में और फोन पर लापरवाही बरते जाने की जानकारी दे दी गई है।

बिजली बिल जमा करने में रुचि नहीं ले रहे उपभोक्ता

सोहना। नरेश कुमार

कोरोना काल के बीते दो माह में बिजली निगम को सिर्फ 30 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही बिल की अदायगी की है। उपभोक्ताओं द्वारा बिल की अदायगी न करने से निगम को दो माह के अंदर करीब 11 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

24 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के बीते करीब दो माह में बिजली उपभोक्ताओं ने अपने घरों में रहकर लगभग 17 करोड़ रुपये की बिजली की खपत की है, लेकिन बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ता 25 से 30 फीसदी ही हैं। जिन्होंने ऑनलाइन अपने बिजली बिलों का भुगतान किया है। सबसे ज्यादा बिजली निगम को आर्थिक नुकसान औद्योगिक क्षेत्रों से हुआ है।

जहां से सोहना सबडिविजन को प्रतिमाह करीब सात करोड़ की आय होती है, लेकिन कोरोना काल में औद्योगिक जगत ठप होने के कारण फैक्ट्रियां बंद होने से निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पर घरेलू बिजली मीटरों से निगम को हर माह दो करोड़ रुपये की आय होती है, लेकिन कोरोना काल में अपने घर में रहते हुए 65 से 70 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं ने निगम को बिल का भुगतान नहीं किया है।

कोरोना काल में सिर्फ 30 फीसदी लोगों ने किया अपने बिल का भुगतान

जनस्वास्थ्य विभाग से 45 लाख का नुकसान : सोहना सबडिविजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनस्वास्थ्य विभाग के अलग-अलग क्षेत्र में लगे ट्यूबवेलों पर बिजली की सप्लाई दी जाती है। जिसमें सोहना सबडिविजन के गांव व शहरी क्षेत्र तावडू, नूंह और पलवल के गांवों में भी सोहना सबडिविजन से बिजली सप्लाई दी जाती है। कोरोना काल में जनस्वास्थ्य विभाग से समय पर बिल का भुगतान न किए जाने से 40 से 45 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

कृषि ट्यूबवेलों से पांच लाख का नुकसान : बिजली निगम द्वारा कृषि पैदावार के लिए अलग से बिजली सप्लाई दी जाती है। कोरोना काल में किसानों द्वारा भी समय पर बिजली का बिल का भुगतान न करने से करीब पांच लाख रुपये नुकसान हुआ है। जबकि किसानों से फैसल पैदावार के लिए दी जाने वाली बिजली सप्लाई से मात्र 10 पैसा यूनिट बिल की वसूली की जाती है।

क्या कहते हैं अधिकारी : सोहना सबडिविजन के एसडीओ रविन्द्र बैरवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से बिजली बिल का भुगतान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उपभोक्ता बिजली बिल जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। जिससे बिजली निगम को इस कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है।

गुरुग्राम में 700 कमरों में सेल्फ व गवर्नमेंट पेड आइसोलेशन व्यवस्था

गुरुग्राम। केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइड लाइन्स की पालना में गुरुग्राम प्रशासन की ओर से पेड आइसोलेशन सुविधा के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा 12 स्थानों पर लगभग 700 कमरों की सेल्फ तथा गवर्नमेंट पेड आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों में गर्वनमेंट पेड आइसोलेशन सुविधा के अंतर्गत 9 स्थानों पर 424 कमरों की व्यवस्था की गई है, जिनके रेट भी निर्धारित किए गए हैं। इन सुविधाओं में पुराने गुरुग्राम क्षेत्र में ओयो हिम ज्योति में 68 कमरे, कैपिटलो-द ग्रेस इन में 30 कमरे, सेक्टर-14 स्थित फ्रेंडस हार्श विला में 50 कमरे, सदर बाजार क्षेत्र में होटल सम्राट में 60 कमरे, बसई चौक स्थित होटल आरके रेजीडेंसी में 30 कमरे, होटल डेल्टा स्क्वेयर में 30 कमरे, राजीव चौक स्थित होटल विवा डेस्टिनेशन में 42 कमरे, राजीव चौक पर ही होटल वेदांता में 44 कमरे तथा दरबारीपुर स्थित होटल सेफ्रयर में 70 कमरे शामिल हैं।

सिंगार कलस्टर के 12 गांवों पर खर्च होंगे 136 करोड़

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के अंतर्गत सिंगार क्लस्टर के 12 गांव में डिटेल प्रोजेक्ट के आधार पर प्राथमिकता वाइज कार्य सूची व टाइमलाइन निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त विक्रम सिंह यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक मीटिंग हुई।

बैठक में एडीसी ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सिंगार क्लस्टर के 12 गांव शामिल किए गए हैं उनमें लगभग 136 करोड रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि इन गांव में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सके। उन्होंने कहा कि रोजगार सर्जन करने के साधन, शिक्षा को बढ़ावा देना, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेरी, वीटा चिलिंग प्लांट, सोलर सिस्टम व स्वास्थ्य गतिविधियों के साथ-साथ सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य किया जाना है।

बैठक करते अधिकारी।

एडीसी ने बताया कि वर्ष 2020 -21 की कार्य योजना के अंतर्गत इस मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। एडीसी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के साथ-साथ सभी विभागों द्वारा अपने अपने विभागों की गतिविधियों को भी बढ़ावा देना है ताकि गांव का समग्र विकास तेजी से हो सके। बैठक में सभी कार्यकारी अभियंता, उप निदेशक कृषि, उपनिदेशक पशुपालन, जिला बागवानी अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आदि अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

संक्षिप्त समाचार

इंसानों के साथ साथ गोमाता की भी चिंता कर रहा है द यूथ फाउंडेशन

गुरुग्राम। कोरोना महामारी के दौरान इंसानों के साथ गोमाता के लिए भी द यूथ फाउंडेशन लगातार कार्य कर रहा है। बहुत सी गोशाला ऐसी है जो केवल आम जनता के द्वारा दिए गए दान से ही चलती हैं। गोशालाओं के लिए चारे की समस्या आ गई, जिसे द यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष धर्मेन्द्र मानेसर ने अपने प्रयासों से दूर किया। धर्मेंद्र यादव के मुताबिक बाबा न्यारम दास गोशाला मानेसर के प्रधान मास्टर बलवीर द्वारा जानकारी दी गई कि गोशाला में चारे की कमी हो गई है। इसलिए संस्था कुछ सहायता कराए। बाबा न्यारम दास गोशाला काफी बड़े एरिया में फैली हुई है और यहां पर काफी संख्या में गाय भी हैं। संस्था ने दानदाताओं से संपर्क करना शुरू किया। शुक्रवार को बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव से अनुरोध करके गोशाला में 15 क्विंटल खल भिजवाई। द यूथ फाउंडेशन के महामंत्री भरत सिंह यादव ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान एक बार पहले भी हमारी संस्था ने नवकल्प फाउंडेशन को फोन करके डॉ. सुनील आर्य के माध्यम से उनके सहयोग से गौशाला में खल, गुड़ और आटा दिलवाने का कार्य किया गया।

बिजली की आंख मिचौली पर किसानों ने की जेई से शिकायत

फर्रूखनगर। फर्रूखनगर शहर व ग्रामीण इलाके में पिछले दो माह से चल रही आंख मिचौनी से ग्रामीणों में रोष है। शुक्रवार को दर्जनों किसान बिजली की समस्या को लेकर बिजली दफ्तर पहुंचे तो एसडीओ जोगिंद्र कौशिक की अनुउपस्थिति में जेई चेतन शर्मा को अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह प्रदर्शन के लिए मजबूर हो सकते है। किसान नेता राव मानसिंह, मास्टर जेपी यादव, रामबीर यादव, ओमप्रकाश, ईश्वर सिंह यादव, अधिवक्ता मनोज यादव आदि ने बताया कि गत एक सप्ताह से झुलसा देने वाली लू में किसानों का बुरा हाल है। पेयजल व्यवस्था भी चरमरा गई। बिजली कटौती के कारण पशुओं के लिए पीने के पानी की भी किल्लत बन गई है। किसानों को 24 घंटों में मुश्किल से 5 से 6 घंटे ही बिजली दी जा रही है। वो भी किस्तों में बिजली कब गुल हो जाये कहा नहीं जा सकता है। अगर किसी गांव में बिजली की लाइन में कोई फाल्ट आ जाता है तो पूरे पूरे दिन बिजली नहीं आती। लोगों खेतों में पेड़ के नीचे झुलसती गर्मी से राहत पाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनवर्टर भी पर्याप्त बिजली नहीं आने से पूरे चार्ज नहीं होंते है। कोरोना के चलते बच्चे भी घर पर ही रहते है। बिना बिजली के उन्हीं पढ़ाई भी पूरी नही हो पा रही है। उन्होंने कहा कि फर्रूखनगर शहर व गांव से जुडी सभी ढ़ाणियों को जगमग योजना से जोड़ा जाए। किसानों के घर व ट्यूबवैलों के मीटर कनेक्शन भी अलग है। शहर की ढाणियों में रहने वाले किसान स्ट्रीट लाईट के रूप में एमसी टैक्स भी देते है। बावजूद भी उन्हें बिजली सरकार व विभाग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुरुप बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है।

चलाकर देखने के बहाने आरोपी ले उड़े कार

सोहना। कार खरीदने आए तीन युवक मालिक से चलाकर देखने के बहाने लेकर भाग गए। सोहना सिटी थाना पुलिस ने नामजद चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जिला नूंह के गांव कौराली निवासी बिलाल पुत्र शाहबुद्दीन ने सोहना सिटी थाना पुलिस को बताया कि उसने 12 सितम्बर 2019 को रोजका मेव निवासी साजिद पुत्र रफीक से कार खरीदी थी। उस कार पर बैंक की 45 किस्त बाकी थी। उसने यह कार एक लाख 20 हजार रुपये देकर खरीदी थी। साथ में कार खरीदते समय बैंक की कार पर बकाया किस्तों को भरने का हल्फनामा भी दिया था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण वह बैंक को कार की किस्त जमा नहीं कर सका। बुधवार को 11, 12 बजे उसके मोबाइल पर गांव आलमपुर जिला फरीदाबाद निवासी आजाद पुत्र तैयब ने फोन करके कहा कि उसके पास तीन युवक भेज रहा हूं। जो कार उसने साजिद से खरीदी थी। उसे दिखा देना और ये युवक उस कार को खरीदना चाहते हैं। कुछ समय के बाद तीन युवक कार से आए और उन्होंने उसे सोहना में नूंह जाने वाले मार्ग पर निरंकारी कॉलेज के सामने कार लेकर बुलाया। दो युवक उसकी कार में बैठ गए और कार चलाकर देखने की कही। जो बाद में लौटकर नहीं आए। बिलाल ने पुलिस को बताया कि आजाद और तीन अन्य युवकों ने उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए कार ले गए। सिटी थाना के सहायक थाना प्रभारी एसआई वेदपाल ने बताया कि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

पूजनीय स्थल पर कूड़ा डाल रहे वाहनों का ग्रामीणों ने रोका रास्ता

फर्रूखनगर। नगरपालिका प्रशासन के लिए शहर का कूड़ा डोर-टू डोर उठाना सिर दर्द बन गया है। चारागाह की 25 एकड़ भूमि पर कूड़ा डालने से कोर्ट ने रोक लगा दी तो वहीं गांव खुर्रमपुर खेडा के निकट मन्नत वाली जोहड़ी में कूड़ा डालना शुरू किया। अब वहां पर भी ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पिछले 10 दिनों से शहर से कूड़ा उठाने का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। जिसके चलते शहर के विभिन्न स्थानों पर कूड़े के ढेर लग गये हैं। गंदगी से उठती बदबू से स्थानीय लोगों का रहना भी दुभर हो गया है। शुक्रवार को सैंकड़ों ग्रामीणों ने कूड़ा लेकर खुर्रमपुर पहुंचे आधा दर्जन टाटा टीपर, ट्रैक्टर, ट्राली को ग्रामीणों ने विरोध करके लौटा दिया। सरपंच विनोद कुमार वाल्मीकि, सरपंच रामनिवास चौधरी, पंचायत समिति सदस्या कौशल्या, धर्मी यादव, नरेश यादव, देविंद्र कुमार, भीम सिंह, महेंद्र सिंह यादव, मुकेश कुमार, छत्तर सिंह, दयाराम आदि ने बताया कि गांव खुर्रमपुर खेड़ा की सीमा क्षेत्र से फर्रूखनगर हेलीमंडी रोड के पास मन्नत वाली जोहड़ी प्राचीन काल से ही क्षेत्रवासियों के लिए पूजनीय स्थल है। इसके चारों और कृषि योग्य भूमि तथा उसमें बनी ढाणियां हैं। इस मन्नत वाली जोहड़ी के पानी में नहाने तथा छींटे लगाने मात्र से ही हर प्रकार के रोगों का निदान हो जाता है। जनवरी माह से नगरपालिका प्रशासन फर्रूखनगर शहर से हर रोज निकलने वाले कूड़े को इसमें डाल रही है। जिससे आसपास का वातावरण काफी दूषित तो हो ही रहा है। ग्रामीणों के बार-बार आग्रह पर भी नपा प्रशासन कूड़ा डालने से बाज नहीं आ रहा है। इस बारे में जिला उपायुक्त को भी ग्रामीण लिखित में शिकायत दे चुके है। नपा प्रशासन कूड़ा डालने की कहीं और जगह तलाशे। एक तो कोरोना महामारी का भय उपर से गंदगी से उठती बदबू से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है।

कोरोना : 20 पॉजिटिव और एक मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 307

उद्योगपति, कंपनी कर्मी और पोस्टमैन पॉजिटिव पाए जाने से दहशत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

स्वास्थ्य विभाग के लाख दावों के बावजूद जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बृहस्पतिवार को जहां 25 पॉजिटिव आने से आंकड़ा 287 पर पहुंच गया था। वहीं पिछले 24 घंटे में शुक्रवार की शाम तक 20 पॉजिटिव आने से आंकड़ा 307 पर पहुंच गया। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर विभाग के अधिकारी इतना बौखला गए है कि दाखिल मरीजों का आंकड़ा 307 और पॉजिटिव का आंकड़ा भी 307 बता रहे हैं। जबकि इनमें से 138 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि विभाग के द्वारा की गई है।

यहां से पाए पॉजिटिव

पॉजिटिवों में बल्लभगढ़ से एक ही परिवार के चार सदस्य जिसमें 44 वर्षीय व्यक्ति, 40 वर्षीय महिला, 25 वर्षीय युवक, 22 वर्षीय युवती शामिल है।

संजय कालोनी से 29 वर्षीय गर्भवती महिला, पर्वतीया कालोनी से 55 वर्षीय पोस्टमैन, एनएच-एक डी ब्लॉक से 32 वर्षीय गर्भवत, एनएच-दो एल ब्लॉक से 22 वर्षीय छात्र, सेक्टर-23ए से दो जिसमें 42 वर्षीय व्यक्ति एक कम्पनी का कर्मचारी है और उसका 14 साल का बच्चा, आदर्श नगर बल्लभगढ़ से 26 वर्षीय मीडिया कर्मी, महावीर कालोनी बल्लभगढ़ से 25 वर्षीय नौकरीपेशा व्यक्ति, पटेल नगर झुग्गी से 35 वर्षीय व्यक्ति, सेक्टर-55 बल्लभगढ़ से 21 वर्षीय छात्र, सेक्टर-29 से नौकरीपेशा 30 वर्षीय व्यक्ति, भूदत्त कालोनी से 67 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति और 33 वर्षीय नौकरीपेशा, सेक्टर-17 से एक कारोबारी परिवार के तीन सदस्य जिसमें 50 वर्षीय महिला, 33 वर्षीय व्यक्ति, 60 वर्षीय बुजुर्ग शामिल है। सेक्टर-37 से 42 वर्षीय उद्योगपति के अलावा नचौली गांव से 40 वर्षीय नौकरीपेशा व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है।

यह है आंकड़े

जिला नोडल अधिकारी डा. रामभगत ने बताया कि जिले में अब तक 10404 यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है, जिनमें से 3635 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 7625 लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 10961 होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 11504 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनमें से 10500 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 701 की रिपोर्ट आनी शेष है। अब तक 307 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 114 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा 47 पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार ठीक होने के बाद 138 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक आठ मरीजों की मौत हो चुकी है जिसमें कोरोना के साथ-साथ अन्य विभिन्न बीमारियों भी कारण रही।

पॉजिटिव युवक के क्रिकेट खेलने से 63 प्रभावित

लापरवाही

सरपंच ने कर दिया सील, 63 बच्चों के सैम्पल लेकर किया क्वॅरेंटाइन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले के नरियाला गांव में एक युवक को चिकित्सक ने जांच कराने के बाद घर में क्वॅरेंटाइन किया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर खुलासा हुआ कि क्रिकेट खेलने के दौरान युवक के सम्पर्क में 63 लोग आए हैं। 63 लोगों के सम्पर्क में कितने लोग आए होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। इससे पूरे गांव में हडकंप मच गया है।

यह है पूरा मामला

29 साल का युवक गांव नरियाला के लिए खतरनाक साबित हो गया। युवक दिल्ली के एक अस्पताल में कार्यरत है। उसे आठ-नौ दिन से खांसी और बुखार की शिकायत थी। जिस पर उसने मेडिकल मोबाइल टीम के चिकित्सक डॉ. राजेश से अपनी जांच गत 23 मई को कराई। कोरोना के लक्षण देखते हुए, डॉ. राजेश ने पीएचसी छायंसा में रेफर कर दिया। पीएचसी ने उसका सैम्पल बीके स्थित आईडीबीएसएसी लैब से कराया। रिपोर्ट न आने तक क्वॅरेंटाइन कर दिया था। लेकिन वह घर से निकल गया क्रिकेट और बॉलीबॉल खेलने। जिससे खतरा बढ़ गया।

पॉजिटिव के सम्पर्क में 63

29 वर्षीय युवक ने सैम्पल देने के अगले दिन गांव ही करीब 20 से 25 युवकों के साथ गत बॉलीबॉल का मैच खेला। खेलते समय उसने युवकों के साथ खाना भी खाया।

अगले दिन उसने क्रिकेट मैच खेला। इस दौरान भी उसके सम्पर्क में करीब 25 से 30 बच्चे सम्पर्क में आए। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सरपंच ने खेल के मैदान में पानी भर रखा था। ताकि कोई खेल न सके। लेकिन युवकों ने सरपंच की अनुपस्थिति में मैदान को मिट्टी डालकर सूखा दिया और खेलना शुरू कर दिया। अब उसके सम्पर्क में आए 63 बच्चों को क्वॅरेंटाइन रहना पड़ रहा है।

कर दिया गांव सील

पता चलते ही सरपंच योगेन्द्र कौशिक ने गांव को सील कर दिया। उन्होंने बच्चों के सैम्पल दिलवा कर उन्हें घरों के कमरों में बंद करवा दिया है, एहतिहात के तौर पर पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया गया है। सरपंच का कहना है कि मैदान में खेलना बंद था, लेकिन बच्चों ने उनकी अनुपस्थिति में मैदान को सुखा दिया। फिलहाल गांव से किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिन बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, उनके परिजनों की भी जांच कराई जाएगी। अगर संभव हुआ तो पूरे गांव के लोगों की जांच कराई जाएगी।

कोविड से संबंधित सूचना पोर्टल के माध्यम से मिलेगी : अरोड़ा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग राजीव अरोड़ा ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि लोगों को सीधे सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक अच्छा तंत्र विकसित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को कहां पर जाकर टेस्ट करवाना है तथा प्राइवेट लैब कौन-कौन सी हैं और उनके क्या चार्जेज हैं, यह सब सूचनाएं पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त जिस भी व्यक्ति की जांच में संक्रमण पाया जाता है उसे फोन या संदेश के माध्यम से तुरंत अलग-थलग रहने के निर्देश दिए जाएं। ताकि वह और लोगों में संक्रमण ना फैला सकें।

बैठक के दौरान यह भी निर्णय हुआ कि जिन व्यक्तियों में बीमारी के लक्षण नहीं आते हैं उन्हें अपने घर में अगर जगह है तो वहां, सामूहिक तौर पर अलग से बनाए गए स्थान पर अथवा अगर वह किसी होटल आदि में रहना चाहता है तो उसकी सुविधाएं भी की जाए तथा इन सभी के रेट निर्धारित कर दिए जाएं। ऐसे सभी व्यक्तियों की देखरेख लगातार की जाए और उसके लिए अधिकारियों की अलग से ड्यूटी लगाई जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी संक्रमित व्यक्तियों के इलाज की सुविधा देनी चाहिए और इस तरह के रोगियों के लिए आयुष्मान भारत के रेट के हिसाब से सरकार पैसा देगी।

विद्यालय प्रबंधन समिति में गठित की कमेटी

फरीदाबाद। एनएच-तीन स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य रविन्द्र कुमार मनचन्दा की अध्यक्षता में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष के रूप में दलीप को चुना गया। विद्यालय के एक अध्यापक, प्राचार्य और एक समाजसेवी ओपी ढींगरा तथा सोलह अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया, इस प्रकार बीस सदस्यों की समिति बनाई गई। प्राचार्य रविन्द्र कुमार मनचन्दा ने समिति से आग्रह किया कि वे विद्यालय में नए बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करवाएं, जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं अर्थात ड्रॉप आउट हैं उन्हें भी पुन: विद्यालय में दाखिला दिलवाने के प्रयास करें। सभी सदस्यों को अवगत करवाया गया।

उद्योग गंभीर आर्थिक चुनौतियों का कर रहे सामना

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने केंद्र सरकार व जीएसटी काउंसिल से वर्तमान परिवेश में एमएसएमई सेक्टर को राहत प्रदान करने के लिए जीएसटी की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाने का आग्रह किया है।

डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा ने कहा है कि वर्तमान में जबकि उद्योग गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में केवल मांग को बढ़ाकर ही

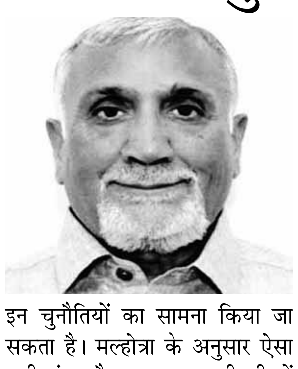

इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। मल्होत्रा के अनुसार ऐसा तभी संभव है जब उत्पादन की कीमतें कम होंगी और उपभोक्ता उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित होगा, जिसके लिए सबसे पहले जीएसटी की दरों को न्यूनतम स्तर पर लाया जाना आवश्यक है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि बढ़ी हुई कीमतों में जीएसटी की भूमिका काफी अधिक है।

मल्होत्रा ने जीएसटी काउंसिल की अगले माह होने वाली बैठक में जीएसटी दरों में कमी लाने हेतु कारगर पग उठाने का आग्रह करते हुए कहा है कि जीएसटी को अपनी बेसिक कैटेगरी को न्यूनतम स्तर पर लाना होगा। मल्होत्रा के अनुसार 18 प्रतिशत तक जीएसटी वास्तव में प्रोडक्ट को महंगा बना देता है, जिस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए घोषित आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए मल्होत्रा ने कहा है कि इस पैकेज से उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, परंतु एमएसएमई सेक्टर सरकार से उम्मीद कर रहा था कि उन्हें तुरंत व शॉर्ट टर्म के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

राशन वितरण की गड़बड़ के विरोध में प्रदर्शन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

वामपंथी पार्टियों की ओर से मजदूरों को राशन देने की मांग को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सभी जरूरतमंद लोगों को राशन दो, राशन वितरण में हो रहे गड़बड़ झाले पर रोक लगाओ के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सीपीएम के जिला सचिव शिवप्रसाद और सीपीआई के जिला सचिव आरएन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। प्रदर्शन के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन डीडीपीओ राजेश मोर को सौंपा गया। इसकी एक प्रति देश के माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम भी भेजा गया।

आज की इस कार्रवाई का संचालन सीपीएम के जिला कमेटी सदस्य वीरेंद्र सिंह डंगवाल कर रहे थे। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर जरूरतमंद लोगों को राशन देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि राशन वितरण प्रणाली न्याय संगत नहीं है असल में जिन लोगों के लिए शासन ने राशन की व्यवस्था की है। उन्हीं को इससे वंचित रखा जा रहा है। इसके लिए बहाना राशन कार्डों को अपडेट नहीं करने का बनाया जाता

है। उन्होंने कहा यह अजीब विडंबना ही है। कि एक तरफ जहां राज्य और केंद्र की सरकारें सभी लोगों को राशन देने की घोषणा टीवी चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से करती है। असल में इन खबरों के लिखित आदेश जारी नहीं किए जाते हैं।

जैसा कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों को बताया कि उनके पास सरकार की तरफ से इस तरह के आदेश नहीं आए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। इसी का परिणाम है की गरीबों और मजदूरों को उनका हक नहीं मिलते हैं।

वाहन पंजीयन ऑथॉरिटी के घोटाले का पर्दाफाश

फरीदाबाद। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ही टीम ने शुक्रवार को सेक्टर 12 स्थित वाहन पंजीयन ऑथॉरिटी में वाहन मालिक, दलाल और कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहे घोटाले का पर्दाफाश किया है। यह सरकार राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे थे। उड़नदस्ते के डीएसपी देवेंद्र कुमार ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है।

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम द्वारा वाहन पंजीकरण कार्यालय बल्लभगढ़ में फर्जी दस्तावेज तैयार करके वाहन पंजीकरण में मोटर वाहन टैक्स कम जमा किये जाने पर किये गए जा रहे अनुसंधान के दौरान उड़नदस्ता डीएसपी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में टीम को फरीदाबाद के विश्वसनीय खुफिया सूत्रों से पता चला कि इस प्रकार का अपराध वाहन पंजीकरण अधिकारी फरीदाबाद में भी हो रहा है। आरोप सत्य पाए जाने पर थाना सेंट्रल में अभियोग अंकित

कराया गया है।

वाहन पंजीकरण कार्यालयों में इस प्रकार के गबन का यह चौथा मामला है जिसमे श्री देवेंद्र कुमार द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में भी वाहन मालिको व दलालों द्वारा वाहन पंजीयन ऑथॉरिटी सेक्टर 12 फरीदाबाद कार्यालय के कर्मचारी अधिकारियों से मिलीभगत करके वाहनों के रजिस्ट्रेशन करने में फर्जी तरीके से गाड़ी की इनवॉइस तैयार की गई। जिसमे वाहन की असल कीमत से कम कीमत के फर्जी बिल बनाकर फर्जी तरीके से वाहन पंजीयन कार्यालय फरीदाबाद में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया। अनुसंधान के दौरान यह बड़े घोटाले का उजागर होने की उम्मीद है।

संक्षिप्त समाचार

पुल के निर्माण को मिली मंजूरी

फरीदाबाद। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अथक प्रयासों से सेक्टर-3 और सैक्टर-8 को जोड़ने वाले पुल निर्माण को मंजूरी मिली है। यह पुल काफी लंबे समय से जर्जर हो चुका था। यह छ: मार्गीय पुल सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सिंचाई विभाग के एसडीओ अरविंद शर्मा ने बताया कि यह पुल कई साल से जर्जर अवस्था में था। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पर संज्ञान लिया कि कोई बड़ा हादसा न हो, इसीलिए, सरकार से इस पुल को बनाने की बात रखी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। यह पुल 7 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। खास बात यह कि टेंडर प्रक्रिया हो जाने के बाद मात्र 3 महीने में ही यह पुल जनता के लिए तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

कुछ स्थानों पर मास्क उपयोग पर प्रतिबंध लगाया

फरीदाबाद। कोविड-19 के चलते हरियाणा सरकार ने मॉस्क न पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसलिए पब्लिक प्लेस में मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क पहनने की अनिवार्यता होने पर अपराधिक तत्व मास्क का फायदा उठाकर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में पुलिस आयुक्त केके राव ने कुछ स्थानों पर मास्क हटाना अनिवार्य कर दिया है।

पुलिस आयुक्त केके राव ने सभी डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और सीआईए प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि डीजीपी के आदेश पर कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अब धीरे-धीरे लॉकडाउन खुलने पर सुनार की दुकानें, शोरूम एवं नकदी लेन-देन करने वाली लोन कंपनियों के दफ्तर भी खुलने शुरू हो गए हैं। ज्वैलरी की दुकानें और शोरूम हमेशा से अपराधियों के निशाने पर होते हैं। इस परिस्थिति का अपराधिक तत्वों द्वारा लाभ उठाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अपराधिक तत्व अपने चेहरों पर मॉस्क पहनकर चोरी या लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। मॉस्क पहनने के कारण वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी पूरी फोटो कवर नहीं हो पाएगी और उनकी धरपकड़ करना मुश्किल हो जाएगा। सीपी केके राव ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्थित प्रत्येक ज्वैलरी शॉप, शोरूम, बैंक, मुथूट फाइनेंस आदि गोल्ड लोन कंपनी में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा होकर अपना मॉस्क हटाएगा। ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सके और दुकान या कंपनी में अपना कार्य निपटाने के बाद फिर से सीसीटीवी कैमरे के सामने मॉस्क लगाएगा।

डिस्ट्रिक अटार्नी ने किया विदाई समारोह को सम्बोधित

फरीदाबाद। सरकारी सेवा में रहते हुए कर्मचारी व अधिकारी जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं उसी क्रम में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उन्हें सहयोगी के रुप में कार्य करना चाहिए यही अपेक्षा सेवानिवृत व्यक्ति से होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण रूप से करने के साथ ही सरकारी सेवा के अपने साथियों की मदद करता रहता है। उक्त विचार डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी के पद से 41 वर्ष की सेवा के उपरांत सेवानिवृत हुए नरेश कुमार राठौर के विदाई समारोह को बतौर मुख्यातिथि के रूप में संबोधित करते हुए डिस्ट्रिक अटार्नी धर्मेन्द्र राणा ने व्यक्त किए। इस मौके पर स्टाफ के अधिकारियों व कर्मचारियों ने सोशल डिस्टिंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए विदाई समारोह का आयोजन किया और राठौर के स्वस्थ्य व सुखद जीवन की मंगल कामना की। इस मौके पर सेवानिवृत अधिकारी को स्मृति चिंह, अंग वस्त्र व अन्य उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी अजय चौहान, बीएल सोनी, एसएन बाली, जगमेन्द्र, आकाश व सुनील परमार तथा एडीए नवीन, प्रगति दहिया, कुनाल, प्रवेश बागड़ी, दीपि, पूर्व एसडीएम प्रताप सिंह, मदन लाल, जगवीर, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के सहायक पुरुषोत्तम सैनी तथा क्लर्क अनंगपाल समेत डीडीए का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

2833 मजदूरों को भेजा घर

फरीदाबाद। कोविड-19 महामारी व लॉकडाउन की परिस्थितियों में प्रवासी लोगों की मदद करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें उनके गृह राज्यों को भेजा जा रहा है। प्रवासी लोगों के लिए ट्रेन व बसों की व्यवस्था की जा रही है तथा सभी को खाने-पीने के सामान के साथ-साथ यात्रा का किराया भी सरकार की ओर से दिया जा रहा है। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि ओल्ड फरीदाबाद से शुक्रवार को दो ट्रेन रवाना की गई। पहली ट्रेन पूर्णिया, बिहार भेजी गई, जिसमें करीब 1383 यात्री थे तथा दूसरी ट्रेन भागलपुर बिहार भेजी गई जिसमें करीब 1450 यात्री थे। उन्होंने बताया कि ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रवासी लोगों को भेजने की प्रक्रिया जारी है।

रेडक्रॉस कर रही जरूरतमंदों की मदद

फरीदाबाद। उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में कोविड-19 के मद्देनजर जिला रेडक्रास सोसायटी द्वारा जरूरतमंद लोगो को पके भोजन के पैकेट तथा राशन, मास्क, सनेटाइजर बोटले, गल्व्ज, पैरासिटामोल, विटामिन टेबलेट तथा सेनेटरी पैड का वितरण निरंतर किया जा है। इस कार्य में प्रशासनिक अधिकारियों और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा स्वयं सहायता समूहों के लोगों द्वारा फरीदाबाद की कालोनियों तथा अन्य क्षेत्रों में अब तक 35 लाख 45 हजार 660 पके भोजन के पैकेट वितरित किए है। इसी कड़ी में 49 हजार 387 परिवारों को राशन उपलब्ध करवाया गया है।

फरीदाबाद के 40 मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा अवार्ड

सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन ने मीडियाकर्मियों की करी प्रशंसा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

सामाजिक संस्था राह ग्रुप फाउंडेशन ने डिजिटल अवार्ड ऑफ एक्सिलेंसी-2020 के तहत फरीदाबाद के 40 मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया है। मीडिया कर्मियों को ये अवार्ड कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल कर देश को जागरुक करने व गरीबों व जरुरतमंदों की आवाज उठाने में इनके सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है।

यह जानकारी देते हुए राह ग्रुप फाउंडेशन की इकाई राह क्लब के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश फोगाट व सलाहकार राजीव पंवार ने बताया कि डिजिटल अवार्ड ऑफ एक्सिलेंसी-2020 के दूसरे चरण में शेष मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। फोगाट के अनुसार मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा अवार्ड प्रदान करते हुए हमें बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। कोरोना काल में आपने अपनी जान जोखिम में डाल कर जो कार्य किया है।

कोरोना की दहशत के बीच लोगो में पानी के लिए मारामारी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

ओल्ड फरीदाबाद नगर निगम के अंतर्गत शिव कॉलोनी, बाबा नगर, गोपी कॉलोनी व राजा गार्डन की निवासियों को कोरोना की मार से भी भयावह पानी की सप्लाई न होने की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। फरीदाबाद नगर निगम के केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर 0129241 5549 कॉल करके दी गई शिकायत नंबर वन 1593 जोकि 24 मई के बाद भी पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए नगर निगम के अधिकारी पानी का टैंकर कभी-कभार भेज रहे हैं। समस्या के संपूर्ण समाधान की तरफ किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

कोरोना संकट के चलते नगर निगम कमिश्नर ने सभी नगर निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की एसेंशियल सर्विसेज को समयबद्ध तरीके से निपटाना है। इसके बावजूद रविवार को की गई शिकायत के बाद 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं। शिव कॉलोनी के निवासी कमलजीत सिंह ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों को पानी की पाइपलाइन को ही नए सिरे से बदल

कर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो पानी की सप्लाई इसी तरह से लोगों को परेशानी हो जाती रहेगी। इसके अलावा नगर निगम के जूनियर इंजीनियर रविंद्र चौहान ने बताया कि नगर निगम के पास पैसों की कमी है। जिस कारण नई बोरिंग या पानी की नयी पाइपलाइन नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा आने में 6 से 8 महीने लगेंगे (वही लोगों ने कहा कि कोरोना संकट के बीच पानी न होना अपने आप में बहुत बड़ी जंग लड़ने के बराबर है। रंजीत सिंह चौहान निवासी संजीव चौहान ने बताया कि समस्या नगर निगम से कमिश्नर यश गर्ग के संज्ञान में दादी गई है के बाद भी लोगों को पानी न मिलने समस्या से बुझते हुए 72 घंटे से अधिक हो गए हैं और अभी भी लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है।

आम आदमी पार्टी की हरियाणा की जौनल महिला अध्यक्ष मंजू गुप्ता ने कहा कि उनके पास भी शिव कॉलोनी के निवासी समस्याओं को लेकर आए थे। कोरोना के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पानी की समस्या को जल्द से जल्द समझाया जाए, क्योंकि पानी के टैंकर से पानी भरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन से नहीं हो पाता है। पार्टी के जोनल सचिव बृजेश नागर ने कहा कि बुजुर्गों तथा महिलाओं को पानी की समस्या से सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी के दोनों पदाधिकारियों ने कहा कि अगर समस्या का समाधान अभी 24 घंटे में नहीं होता है तो वह नगर निगम कमिश्नर से खुद जाकर उनके निवास पर मिलेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सके।

पायनियर
नई दिल्ली, शनिवार, 30 मई, 2020

प्रवासी श्रमिकों की समस्या

राष्ट्रीय डाटाबेस की आवश्यकता

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकार किया कि 91 लाख दिहाड़ी श्रमिक व कामगार शहरों से अपने गृह राज्यों को गए हैं जिससे श्रम बाजार की संरचना हमेशा के लिए बदल सकती है। लाकडाउन के बाद ठेकेदारों और फैक्ट्रियों से से ठुकराए, तथा बचत, आवास अथवा सेवायोजकों या सरकार द्वारा अंतरिम राहत के अभाव में वे अपने जीवन को खतरे में डाल कर गांवों की ओर भागे। इस प्रकार वे बीमारी व भुखमरी के संकट में भी पड़े। भले ही वे वापस आएं, पर जल्दी वापस नहीं आएंगे। बड़े शहरों द्वारा ठुकराए जाने के बाद वे अपने गृह राज्यों में मनरेगा व ढांचागत परियोजनाओं में काम करना ज्यादा अच्छा समझेंगे। बड़े शहरों में अब उनकी कमी अनुभव होने लगी है। ड्राइवर, एलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लंबर, घरेलू कामगार, माली व राजगीर, आदि सभी पलायन कर गए हैं। अनेक राज्य अब लौटने वाले श्रमिकों का कौशल के आधार पर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और उनको दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके श्रमिकों का काम मिल सकता है। लेकिन परंपरागत श्रम-निर्यातक राज्य लौटते श्रमिकों की बाढ़ का शिकार हैं और उनको रोजगार देने के प्रयास कम पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में उल्लेखनीय पहल की है। पिछले सप्ताह तक लौटे लगभग 23 लाख श्रमिकों को उन्होंने कौशल व कार्यक्षेत्रों के अनुसार बांटा है। 15 लाख श्रमिकों का डेटाबेस तैयार हो गया है और उद्योगों ने पांच लाख से अनुबंध का प्रस्ताव किया है। उन्होंने राज्य में सभी प्रवासीी श्रमिकों के लिए श्रमिक आयोग का गठन किया है जो उनको रोजगार देने के साथ एक कार्ड देकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। एक बीमा योजना भी शुरू होने जा रही है। वर्तमान समय में क्षेत्रीय श्रम कार्टेलों का विकास हो सकता है जो कुशल कामगारों के लिए अब श्रमिकों की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ज्यादा पैसा मांग सकती हैं। राजस्थान ने सभी 33 जिलों से कुशल व अकुशल श्रमिकों का डेटा एकत्र करना शुरू किया है जिसे जल्द ही 18 उद्योग क्लस्टरों में फैक्ट्री मालिकों को दिया जाएगा। उसने 1.2 मिलियन बेरोजगारों के विस्तृत विवरण एक पोर्टल पर डालने की तैयारी की है ताकि श्रमिकों के लिए कार्यक्रम बनाने, उनको जल्दी से रोजगार देने तथा मांग-सप्लाई कमी पूरी करने के काम हो सकें। इससे उद्योगों की आवश्यकताओं तथा श्रमिकों की योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना पुनः शुरू की है जिसमें लौटे सभी प्रवासी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा तथा उनके परिवारी सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा, बच्चों को स्कूल फीस व बीमा मिलेगा। यहां कामगारों का डेटाबेस तैयार है। बिहार व झारखंड भी आंतरिक पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। स्थानीय श्रमिकों की कमी वाले पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को पुनः काम देने के लिए पोर्टल बनाए हैं तथा उनको विभिन्न कार्यस्थलों पर जाने की सलाह दी जा रही है।

प्रधानमंत्री द्वारा 'लोकल के लिए वोकल' का मंत्र भी श्रम बाजार के लिए नए अर्थ लाया है, लेकिन यह तात्कालिक प्रभाव वाला हो सकता है। अनेक राज्यों में मजदूरी व रोजगार की क्षमता सीमित है। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश सभी प्रवासियों को काम देने में सफल होता है तो भी उनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 70,000 होगी, जबकि यह महाराष्ट्र में 2 लाख तथा दिल्ली में 4 लाख है। इसलिए महामारी का खतरा टलने के बाद श्रमिक फिर दूसरे स्थानों पर जाने लगेंगे। लौटने वाले अनेक प्रवासी आईटी, होटल व बीपीओ क्षेत्रों से हैं जिनका कौशल व क्षमता बड़े शहरों में काम करने की है। वे अपने मूल गांवों में नहीं रुक सकते हैं। ऐसे में श्रमिकों के लिए एक अखिल-भारतीय डेटा बेस की आवश्यकता है जिसमें सभी उद्योगों को शामिल करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। भारत के जनसंख्या लाभांश का लाभ उठाने तथा राज्यों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए यह जरूरी है।

आत्मविश्वास से भरा आत्मनिर्भर भारत

पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज के द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' के अभ्युदय का नया सूरज उगाया है।

अमित शाह

विगत छः वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में भारतवर्ष की विकास यात्रा अद्भुत, अकल्पनीय और प्रशंसनीय रही है। 2014 से पहले की किंकर्तव्यविमूढ़ता, अकर्मण्यता और खोखले वादों के पिटारे पर मोदी कार्यकाल में जन-मानस ने नेतृत्व, विश्वास, सहयोग और आत्मबल के सहारे समय से पूर्व ही लक्ष्य को बेधने की क्षमता हासिल कर ली है। देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, मोदी सरकार के अब तक के छः वर्षों के कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में अंकित किये जायेंगे। इसी तरह मोदी सरकार 2.0 का पहला वर्ष भी समय के शिलालेख पर भारत के कभी न मिटने वाले उन कालजयी पदचिह्नों की कहानी है जिसकी कल्पना किसी ने की भी नहीं थी। निस्संदेह मोदी सरकार ने छः वर्षों में छः दशक की खाई को पाट कर आत्मनिर्भर भारत की बुलंद बुनियाद खड़ी की है।

फ्रेजाइल फाइव से भारत को विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाना, आतंकवाद के साए से देश को निकालकर उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार करना, स्वच्छता को हर भारतवासी का संस्कार बनाना, सच्चे अर्थों में गांव-गरीब-किसानों का कायाकल्प करने का संकल्प और चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने की निपुणता तो भारत ने मोदी सरकार के पहले ही कार्यकाल में देख लिया था। दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष ने देश की जनता को सपनों के सच होने का यकीन भी दिला दिया।

कुछ करने का जज़्बा और हौसला जब प्रधानमंत्री श्री मोदी जैसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने घोषणापत्र के एक-एक वादे को जमीन पर उतार कर दिखाया है वरना चुनावी घोषणापत्र को तो देश की जनता महज झूठ का एक पुलिंदा भर ही समझती थी जो केवल कुछ पार्टियों द्वारा जनता को धोखा देने और उन्हें गुमराह करने के लिए लाया जाता था। केंद्र सरकार के संकल्प पत्र ने लोकतंत्र में घोषणापत्र की महत्ता को तो स्थापित किया ही, लोकतंत्र की जड़ों को भी मजबूत किया।

जम्मू-कश्मीर से धारा 370 और 35 का उन्मूलन, श्री राम मंदिर के निर्माण के मार्ग का प्रशस्तीकरण, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति और नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से आजादी के 70 सालों से वंचितों को उनका अधिकार देने जैसे कई कालजयी निर्णयों से एक ओर मोदी सरकार ने आज़ादी के बाद की ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा है तो वहीं दूसरी ओर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत' से देश के लगभग 50 करोड़ गरीबों को इलाज के बोझ से मुक्ति दिलाने, करोड़ों गरीब महिलाओं का उज्ज्वला योजना के माध्यम से सशक्तीकरण, किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक कृषि सहायता राशि, हर गरीब को छत और हर नागरिक की जन-धन खाते के माध्यम से बैंकों तक पहुंच जैसे सर्वस्पर्शी निर्णयों के माध्यम से नए भारत का सृजन किया है। इस तरह मोदी सरकार सृजन और सुधार के समांतर समन्वय की अभूतपूर्व मिसाल बनी है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सभी महत्वपूर्ण विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुए जबकि राज्य सभा में हमारा बहुमत भी नहीं था। यह दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र कितना परिपक्व हुआ है।

भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के निर्णायक प्रहार ने देश में एक अलग तरह का आत्मविश्वास जगाया है। यूएपीए और एनआईए एक्ट में संशोधन कर आतंकवाद पर नकेल कसने को संबल मिला है। भारत की ऊर्जस्वी विदेश नीति और रक्षा नीति ने देश को अग्रिम कतार में खड़ा किया है और दुनिया का देश को देखने के प्रति नज़रिये में आमूल-चूल बदलाव आया है।

मोदी सरकार के द्वितीय संस्करण के प्रथम वर्ष में ऐसे कई इनिशियेटिव लिए गए जिससे वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिली जैसे कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एफडीआई का मार्ग प्रशस्त करना, कार्पोरेट टैक्स को कम करना, बैंकों का विलय, एनबीएफसी लोन पर मोरोटोरियम, कम्पनी एक्ट में सुधार, एमएसएमई के विकास के लिए आसान ऋण की व्यवस्था आदि। वर्षों से लंबित ब्रू-रियांग शरणार्थी समस्या तथा बोडो समस्या का समाधान भी मोदी सरकार 2.0 के पहले साल में हुआ।

दशकों से लंबित चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। आरसीईपी का विरोध करके देश के किसानों एवं व्यवसायियों के हितों की सुरक्षा की गई जिसकी महत्ता कोरोना वायरस के मामले में चीन की भूमिका के मद्देनज़र और बढ़ जाती है। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरीडोर बना कर न सिर्फ विदेशी निवेश को आकर्षित किया गया बल्कि इससे लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने वाली मोदी सरकार ने सामाजिक उत्थान को अपना मूल मंत्र बनाया। किसान, मजदूर एवं छोटे उद्यमियों के लिए पेंशन योजना, जल शक्ति मंत्रालय का गठन, एक देश - एक राशन कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों की एमएसपी को डेढ़ गुना से अधिक करने का निर्णय, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स की विकास योजना, उज्ज्वला और सौभाग्य योजना के साथ-साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति के आंदोलन ने यह स्थापित किया कि गरीब कल्याण के सहारे भी जीडीपी ग्रोथ हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समस्याओं को चुनौती के रूप में लेकर उसे अवसरों में ढालना सीख लिया है। मोदी सरकार 2.0 का जिक्र कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के बगैर पूरा नहीं हो सकता। नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने दुनिया को इस दिशा में अलग राह दिखाई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित लोगों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, कृषि एवं उद्योगों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके 'आत्मनिर्भर भारत' के अभ्युदय का नया सूरज उगाया है। अब तक लगभग 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केवल दो महीनों में गरीबों, मजदूरों, किसानों, विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के एकाउंट में हस्तांतरित किये जा चुके हैं। गरीबों के लिए पांच महीने तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है और मनरेगा के तहत 60 हजार करोड़ के बजटीय आवंटन से अलावा 40 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किये गए हैं। उन्होंने इसके माध्यम से न केवल सुदृढ़ 'न्यू इंडिया' बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को भी साकार करने खाका तैयार किया है। इसके माध्यम से भारत के भाल पर नव-निर्माण का सुनहरा भविष्य लिखा जायेगा।

आत्मनिर्भर भारत की झलक भी पिछले डेढ़ माह में दिख गई कि भारत किस तरह चुनौतियों से पार पाने में सक्षम है। अप्रैल की शुरुआत में हम जहां पीपीई किट, वेंटिलेटर और एन-95 मास्क के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर थे, वहीं आज हम स्वयं बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन कर रहे हैं। आज देश में प्रतिदिन लगभग 3.2 लाख पीपीई किट (अब तक 1 करोड़ पीपीई किट भारत में बनाये गए हैं) और ढाई लाख एन-95 मास्क बनाए जा रहे हैं। वेंटिलेटर का स्वदेशी संस्करण भी बाजार मूल्य से काफी कम कीमतों में देश के कई संस्थाओं ने तैयार कर लिया है। दस लाख से अधिक कोरोना बेड तैयार किये जा चुके हैं और हमें रोजाना डेढ़ लाख टेस्टिंग की क्षमता भी हासिल कर ली है। संकट के समय हमने दुनिया के 55 से अधिक देशों को जरूरत की दवाइयों की आपूर्ति की है जिसकी सराहना दुनिया के सभी देशों ने की है। सही समय पर लॉकडाउन के चलते भारत ने कोरोना को काफी हद तक रोकने में सफलता पाई है। कोरोना संकट के दौर में देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा देते हुए देश की आत्मा को जगाया है। साथ ही 'लोकल के लिए वोकल% कह कर स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार हर क्षेत्र में अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं जो भारत को सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बनाएगा। उनकी अगुआई में भारत एक ऐसे राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है जहां न कोई शोषक होगा न शोषित, न कोई मालिक होगा न मजदूर, न अमीर होगा न गरीब। सबके लिए शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और उन्नति के समान और सही अवसर उपलब्ध होंगे।

(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री हैं)

जीवन तथा आजीविकाओं को बचाना अनिवार्य

> समाप्त होती आजीविकाओं का सवाल निराशा को जन्म दे रहा है। आज महामारी से ज्यादा उसका उपचार महंगा पड़ रहा है।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक वरिष्ठ नीति विश्लेषक हैं)

ग्रेटर नोएडा में लर्गभग 3,000 परिवारों वाली एक आवासीय सोसायटी में इस सप्ताह एक परिवार के कोविड-19 संक्रमित पाए जाने के कारण संपूर्ण आवासीय परिसर को सील कर दिया गया। ये परिवार, जिनमें से अधिकतर पहली बार फ्लैट के मालिक बने थे, स्व-रोजगार करने वाले अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी निजी उपक्रम के अधीन काम कर रहे थे, जो इस क्षेत्र के निवासियों में सापेक्षतः नए हैं। सीलिंग के द्वारा उनमें से अधिकतर को आवासीय परिसर के भीतर कैद कर दिया गया जबकि उनके नियोक्ताओं ने उन्हें वेतन में कटौती करने की धमकियां दीं। मार्च के अंत में लाकडाउन प्रारम्भ होने के बाद से शायद पहली बार आवासीय सोसायटी में रहने वाले आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी आजीविकाओं को बचाने के लिए संगठित होकर प्रदर्शन किया।

प्रवासी श्रमिकों को उनके राज्यों तक वापस पहुंचाने के लिए चलाई गई कुछ दर्जन विशेष ट्रेनों के कथित रूप से मार्ग बदल दिए गए और उन्हें लंबे रास्तों पर डाल दिया गया, जिसके फलस्वरूप अंततः वे देशभर में गलत गंतव्यों पर पहुंच गईं। देश में परिचालन बहाल किए जाने के पहले दो दिनों के भीतर ही बहुत सी उड़ानें निरस्त कर दी गईं। उच्च तीव्रता वाले महाचक्रवात ने पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई और जबर्दस्त तबाही का मंजर पैदा कर दिया। राजधानी नगर कोलकाता में बिजली आपूर्ति बहाल करने में चार दिन लग गए तथा अर्ध नगरीय एवं ग्रामीण इलाकों तक स्वच्छ जल जैसी मूलभूत सुविधाएं व राहत पहुंचना अभी बाकी है।

उपरोक्त उदाहरण एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में राज्य सरकार के विविध अंगों के बीच कुप्रबंधन की खेदजनक कहानी बयां करते हैं। यदि हम केंद्र, राज्य, जिला, नगर एवं पड़ोसी क्षेत्र के प्रशासन की सतहों को जोड़ना प्रारम्भ करें, तो भारत के वर्तमान में जारी महामारी संकट समाधान व्यवस्था का समझ से परे मकड़जाल उभरकर आता है। मानवता के लगभग पांचवे हिस्से पर दो महीने से अधिक की अवधि का लाकडाउन थोपने के लिए किसी प्रधानमंत्री में साहस तथा हिमालयी ऊंचाई वाला विश्वास चाहिए। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जीवन बचाने के लिए एक कदम उठाया जिसके बदले में 400 मिलियन आजीविकाओं को होम करना पड़ा, उन लोगों की जिन्होंने हाल ही में बिजली, स्वच्छ जल, गैस कनेक्शन तथा लगभग 150 डॉलर प्रतिमाह की आमदनी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ अर्ध-वैश्विक अस्तित्व प्रारम्भ किया था। मात्र दो महीनों के भीतर, अभी भी एक गरीब राष्ट्र होने की कठोर वास्तविकताएं उभरकर सामने आने लगी हैं।

अब इन सुर्खियों पर गौर कीजिए, यथा, "भारत में सबसे बड़ी मंदी", "लाखों चेहराविहीन, अज्ञात लोग बेरोगजार होकर भटक रहे", "नहीं है लाकडाउन से निकलने की रणनीति।" वास्तविक मुद्दा जो हमारे सामने आना प्रारम्भ हुआ है और हम धीमे-धीमे महसूस करने लगे हैं कि लाकडाउन से निकलने की कोई रणनीति है ही नहीं।

इससे हमें एक अन्य योद्धा का स्मरण होता है। महाभारत में, वीर अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु, जब अपनी मां के गर्भ में था तभी उसने युद्ध कौशल सीख लिया था। मगर उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था, यद्यपि उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तथा युद्ध में एक दिन जीतना आता था। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि मानव जीवन को कम से कम क्षति के साथ कैसे बाहर निकला जा सकता है, खासकर यदि युद्ध सीमाओं पर न हो रहा हो?

यही महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसी स्थिति में और यहां पर कुछ सुरक्षित धारणाएं हैं : कोविड-19 मानव से मानव संपर्क के साथ तेजी से फैलता है। गलत सूचना अथवा अविश्वास कोविड से ज्यादा बड़ा वायरस है और वह यहां लंबे समय तक रहने वाला है। इसकी वैक्सीन, यदि बन भी जाती है तो विकसित जगत से आने में कम से कम एक वर्ष लगेगा और हमारे जैसे गरीब मगर आकांक्षी देशों तक और विलंब से पहुंचेगी। विकासशील जगत केवल और ज्यादा गर्मी तथा घरेलू उपचारों पर निर्भर रह सकता है। आश्चर्यजनक तत्व यह है कि इस घातक वायरस में निबटने के लिए कुछ प्राचीन सामान्य जानकारी कारगर होती है।

उपरोक्त दावों को सिद्ध करने के लिए कोई सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकतर का काफी महत्व है। इस स्थिति में भारतीय महामारी के प्रति सामान्य समझ से निर्देशित दृष्टिकोण की कामना कर सकते हैं। सार्वजनिक सूचनाके आधार पर, अभी तक भारत में इस बीमारी से ठीक होने की दर अच्छी है और शेष विश्व की तुलना में इससे संक्रमित होने वालों में मृत्यु दर भी कम है। इस जानकारी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि 1.5 मिलियन फोनधारकों वाले देश में सच को ज्यादा लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। कोई न कोई गड़बड़ी को पकड़ अवश्य लेगा और जानकारियां प्रेषित कर देगा। हमें यह भी स्वीकर करना है और सजग रहना है कि भारत ने अभी तक नियंत्रण बनाए रखने में सफलता प्राप्त की है तथा जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि खत्म होने वाले जीवनों से ज्यादा जीवन बचाए गए हैं।

आजीविकाओं का सवाल निराशा को जन्म दे रहा है। आज महामारी से ज्यादा उसका इलाज महंगा पड़ रहा है। आज बचा ली गई हर जिंदगी निकट भविष्य में कुपोषण, भूख, प्रतिरोध्य बीमारी अथवा आपदा की शिकार हो सकती है। धरातल पर कानून के रक्षक भी महामारी अथवा गलत सूचनाओं के प्रवाह से सुरक्षित नहीं है और एक आकार सभी पर लागू होना कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता। महामारी से निबटने का अत्यधिक सूक्ष्म-स्थानीय तथा सशक्त दृष्टिकोण वायरस के खिलाफु दीर्घकलीन संघर्ष का समाधान हो सकता है।

हालांकि, यह भी याद रखें किअधिक शक्ति के साथ अधिक जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। इसलिए, वर्तमान परिस्थितियों में अग्रिम पंक्ति के विधि निर्माताओं, वरिष्ठतम से लेकर वायरस के प्रवाह को रोकने के लिए पड़ोस की रक्षा करने वालों तक, सभी को आजीविकाओं तथा सामाजिक दूरी को साथ-साथ सुनिश्चित करना होगा।

आप की बात

चीन की घुसपैठ

लद्दाख में भारत-चीन नियंत्रण रेखा पर चार स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से चीनी सैनिकों की घुसपैठ हो रही है। रिपोर्टों के अनुसार विवादित क्षेत्र में चीन बंकर भी बना रहा है तथा बड़ी संख्या में सैनिकों के अलावा साजो सामान भी लाया जा रहा है। जाहिर है चीन का इरादा इलाके में तनाव बढ़ाने का है। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है इस महीने के शुरु में सिक्किम के पास भी झड़प हो चुकी है। आमतौर पर विवादित क्षेत्रों में निगरानी के लिए घूमती टुकड़ियों में तनातनी होती रहती है लेकिन वर्तमान प्रकरण उनसे बिलकुल अलग है। भारतीय सेना की तरफ से इन जगहों पर सैनिकों की संख्या बढा दी गई है। हालिया रवैये का संज्ञान लेते हुए चीन की इस कवायद को व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अभी चीन कोरोना वायरस के बारे में समय से जानकारी ना देने के आरोपों तथा व्यापारिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वह हांगकांग और ताइवान पर धौंस जमाने से बाज नही आ रहा है। हाल के दिनों में चीन की राह पर नेपाल और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी का सिलसिला शुरु किया है। चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया में भारत को लदाख और सिक्किम में आक्रमक रुप में दिखाने का रुख भी इसी कड़ी में है।

– **भूपेंद्र सिंह रंगा**, हरियाणा

बड़ों का बड़प्पन

ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ने ध्यान ना रहने पर लॉक डाउन तोड़ने पर ना केवल राष्ट्र से माफी मांगी है, बल्कि इस गलती की जिम्मेदारी लेते हुए जिस रेस्टोरेंट्स में बैठ कर दोस्तों से चर्चा कर रहे थे, उस रेस्टोरेंट पर जो भी जुर्माना लगाया जाएगा,वह जुर्माने की राशि स्वयं राष्ट्रपति भरेंगे। किसी भी देश के शासकों मे ऐसा ही जिम्मेदारी का भाव व सद्चरित्र होना बेहतर शासन के लिए पहली शर्त है। जो राजनीति में शुचिता के लिए बेहद आवश्यक है। अपनी भूलों गलतियों को साहस के साथ स्वीकार करना उसके लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना ही बेहतर शासक की निशानी है। काश! हमारी भारतीय राजनीति में भी अगर सभी नेता राजनीति की शुचिता के लिए अपनी गलतियों को स्वीकारने लगे व कंधों पर जिम्मेदारी लेने लगे तो हमारा देश भी श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। सबसे पहले आदर्श की मिसाल पेश की अपेक्षा शासकों से ही की जाती है। चाहे वे जनप्रतिनिधि हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति स्वयं आदर्श की मिसाल पेश नहीं करेंगे तब तक एक आम आदमी से कैसे अपेक्षा करें कि वह शुचिता के लिए आदर्श की बानगी बने।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

बिजली का बिल माफ हो

आज देश में कोरोना महामारी के चलते लाकडाउन है। जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। अब सरकार ने कुछ शर्तो पर छूट दी है। सरकार ने गरीब व निम्न मध्यवर्गीय जिसकी लाकडाउन के चलते आय शून्य हो गयी थी उन सभी का इस लाकडाउन में, सरकार ने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश एवं प्रदेश के समस्त कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट अनाज देने का निर्णय लिया वो भी मुफ्त में। परन्तु आज उन्ही गरीब , निम्नमध्यवर्गीय के समक्ष एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है और वह है बिजली का बिल। आखिर इस समय जब इन सभी की आमदनी शून्य है, लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं। उन्हें आय के नए स्रोत खाजने की जरूरत है। ऐसे समय में वह अपनी बिजली का बिल कैसे भरेंगे। केंद्र सरकार ने बीस लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया है। सरकार से आग्रह है कि वह इस ओर अपना ध्यान इंगित करें। अगर आधा भी बिजली का बिल माफ हो जाए तो उन जरुरतमंदों को इस लाकडाउन में बड़ी राहत मिल सकती है।

– **अभिनव दीक्षित**, बांगरमऊ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

फरमाया

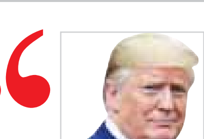

रिपब्लिकनों को लगता है कि सोशल मीडिया मंच कंजरवेटिव्ज को खामोश कर देते हैं। ऐसा होने से पहले हम उन्हें विनियमित करें और बंद कर देंगे।

– **डोनाल्ड ट्रंप**
अमेरिकी राष्ट्रपति

हम वैश्विक स्तर पर चुनावों के बारे में गलत अथवा विवादित जानकारियों का उल्लेख करते रहेंगे। हमसे जो गलतियां हुईं उन्हें स्वीकार करेंगे।

– **जैक डॉरसी**
ट्विटर सीईओ

उनका डर, उनकी पीड़ा, उनकी सिसकी देश में सबने सुनी मगर शायद सरकार ने नहीं सुनी।

– **सोनिया गांधी**
कांग्रेस अध्यक्षा

प्रदेश के निर्माण में हाथ बंटाएंगे प्रवासी श्रमिकः योगी

- सरकार तथा इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नारडेको के बीच हुआ करार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना संक्रमण के चलते उत्पन्न रोजगार के संकट निपटने के लिये राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज राज्य सरकार तथा इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नारडेको के साथ अहम करार हुआ। जिससे प्रदेश के 11 लाख कामगारों को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन तथा फिक्की 3-3 लाख तथा लघु उद्योग भारती एवं नारडेको ढाई-ढाई लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराएंगी।

ग्यारह लाख श्रमिकों के नये रोजगार का रास्ता साफ

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरी दुनिया में न केवल औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो गयी हैं, बल्कि सामान्य जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से जितने भी श्रमिक प्रदेश में आ रहे हैं वही हमारी ताकत हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल प्रदेश के निर्माण के लिए करेंगे। प्रदेश सरकार ने कामगारों की स्किल मैपिंग का कार्य किया है। सरकार हर हाथ को काम व हर घर को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पेंटर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, पैरामेडिक्स, कम्प्यूटर आपरेटर सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्किल्ड लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। योगी ने कहा कि कामगारों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने एक आयोग के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सेवायोजन कार्यालयों को सक्रिय किया जा रहा है। इसकी मानीटरिंग राज्य स्तर पर गठित आयोग द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि विगत दिनों प्रदेश सरकार द्वारा आनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। शुभारम्भ के अवसर पर 56 हजार 754 उद्यमियों को 2 हजार 2 करोड़ 49 लाख रुपये का ऋण आनलाइन वितरित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया। स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस क्रम में प्रदेश सरकार एएसएमई तथा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के सम्बन्ध में नीतियों में संशोधन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपीसीडा लैण्डबैंक बनाने का कार्य तेजी से कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से कामगारों की सुरक्षित वापसी कराते हुए इन्हें 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता एवं राशन किट भी उपलब्ध करायी गयी है। जनधन खाते में 500-500 रुपये की धनराशि दो बार अन्तरित की जा चुकी है। 86 लाख वृद्धावस्था, दिव्यांगजन तथा निराश्रित महिला पेंशन लाभार्थियों को दो माह की पेंशन का भुगतान एक साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही समय पर सही निर्णय लिया। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है कि भारत आज सुरक्षित स्थिति में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 94 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने श्रमिकों व कामगारों को मानदेय देने का कार्य किया है, जो सराहनीय है।

इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी तथा अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी सहित अन्य अधिकारी एवं इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती तथा नारडेको के पदाधिकारी उपस्थित थे।

पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह की पुण्य तिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ

रालोद ने की पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- प्रदेश भर में श्रद्धा से मनाई गई किसान नेता की 33 वीं पुण्य तिथि

राष्ट्रीय लोकदल द्वारा किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौ.चरण सिंह की 33 वीं पुण्य तिथि शुक्रवार को पूरे प्रदेश में श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाई गई। इस अवसर पर रालोद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जनपदों में चौ. चरण सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके अपने प्रिय नेता को याद किया। इस मौके पर सभी नेताओं ने एक स्वर से किसान मसीहा चौ.चरण सिंह को केन्द्र सरकार से भारत रत्न देने की माँग की।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित प्रान्तीय मुख्यालय पर रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ विधि विधान से यज्ञ करके चौ.साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। यज्ञ के पश्चात राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डा.मसूद अहमद, राष्ट्रीय महासचिव शिवकरन सिंह, राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी सहित अन्य नेताओं ने सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए विधान भवन स्थित चौ. साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सम्पूर्ण उप्र में रालोद कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर रहते हुए चौ. साहब को याद किया तथा गरीबों, असहायों एवं मरीजों को भोजन तथा फल इत्यादि का वितरण किया।

कार्यों की गुणवत्ता परखने को स्थानीय स्तर पर संयुक्त कमेटी का गठन करें: नीलकंठ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- समीक्षा बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश

पर्यटन मंत्री डा.नीलकंठ तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग की समस्त योजनाओं की गुणवत्ता के निरीक्षण हेतु स्थानीय स्तर पर एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाए जिसमें कार्यदायी संस्थाओं के अलग-अलग अभियन्ता, पर्यटन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी एवं पर्यटन स्थल से संबंधित उपजिलाधिकारी को शामिल किया जाए। उन्होंने परियोजना प्रबन्धक, यूपीसिडको लखनऊ को यह निर्देश दिए कि पर्यटन विभाग के विभिन्न जनपदों में संचालित योजनाओं की अवमुक्त धनराशि के अन्तर्गत समस्त कार्य नई टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण करायी जाए। पर्यटन मंत्री श्री तिवारी ने यह निर्देश शुक्रवार को पर्यटन निदेशालय के सभाकक्ष में पर्यटन विभाग की स्वीकृत, चालू एवं निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने मुख्य अभियंता राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ से पर्यटन विभाग की स्वीकृत एवं चालू योजनाओं के संबंध में योजनावार विस्तृत समीक्षा की तथा सभी निर्माण कार्यों के फोटोग्राफ्स एवं इन्वेन्ट्री सहित अद्यतन प्रगति सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री ने गोरखपुर स्थित वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एवं झील मनोरंजन की योजना के कार्य हेतु महाप्रबन्धक जल निगम, लखनऊ को स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। पर्यटन मंत्री ने स्व. अटल बिहारी बाजपेई की जन्मस्थली बटेश्वरधाम के समग्र विकास हेतु पर्यटन विभाग एवं संस्कृति विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव पर्यटन जितेन्द्र कुमार को दिए।

किसान व गरीब की चिंता करने वाले नेता थे चरण सिंहः शिवपाल

लखनऊ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि वह गरीबों व किसानों के नेता थे। जबकि चौधरी साहब के पहले व बाद में प्रधानमंत्री बने अधिकांश प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिल चुका है। शिवपाल यादव ने कहा कि चौ. चरणसिंह को जब जब सत्ता में रहने का अवसर मिला उन्होनें किसानों और गरीबों के जीवन स्तर को उठाने वाली नीतियों को आगे बढ़ाया। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर गरीबों व अन्नदाताओं के मसीहा चौधरी चरण सिंह मौजूदा समय में होते तो अपने प्रदेश से बाहर कमाने गए किसान और गरीबों के बच्चों और मजदूरों को सड़कों पर रात नहीं गुजारनी पड़ती। चौधरी चरण सिंह द्वारा किसान और मजदूर हितों के लिए किए गए कार्य आज भी लोगों के दिल में हैं। वह किसान और गरीब की चिंता करने वाले थे। शिवपाल यादव ने कहा कि चरण सिंह जानते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव, खेत खलिहानों से ही निकलेगा। इसलिए जीवन भर यही कोशिश करते रहे कि कैसे किसानों को खुशहाल बनाया जाए। शिवपाल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह व लोहिया के सपने को पूरा करना ही उनके राजनीतिक कर्म का उद्देश्य है।

भाजपा नेतृत्व का गांवों से दूर-दूर तक कोई सम्बंध नहींः अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि को ताकत देने की नीतियों को लागू किया।

श्री यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने केन्द्र में वित्तमंत्री के समय जो बजट लोकसभा में पेश किया था उसमें कृषि क्षेत्र, गांवों और किसानों की समृद्धि के लिए 70 प्रतिशत की व्यवस्था की थी। उसी आधार पर समाजवादी सरकार में चार वर्ष पूर्व जो बजट उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया उसमें खेती, किसान और गांवों के विकास के लिए बजट में 75 प्रतिशत हिस्सा रखा गया था लेकिन भाजपा से यह आशा करना अर्थहीन है कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए कभी भी संवेदनशील होगी। श्री यादव ने कहा कि भाजपा नेतृत्व का भी गांवों से दूर दूर तक कोई सम्बंध नहीं रहा। तभी तो कारपोरेट व्यवस्था को तरजीह देकर कोपरेटिव फार्मिंग की चर्चा शुरू की जा रही है। इसका दूरगामी दुष्परिणाम होगा कि किसानों के खेत भी कारपोरेट के जाल में फंस जायेंगे तथा किसान के खेत की जमीन का स्वामित्व खतरे में पड़ सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान गांव और कृषि जब तक आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक आत्मनिर्भर भारत की बात करना दिवास्वप्न ही है।

जेपी नड्डा करेंगे सम्पर्क व संवाद अभियान की शुरुआत

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष कल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर पार्टी द्वारा शुरू किये जा रहे सम्पर्क व संवाद के अभियान का शुभारम्भ कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा फेसबुक के माध्यम से लाइव सम्बोधन द्वारा करेंगे। अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के द्वारा लिखे पत्र जिसमें आत्मनिर्भर भारत की विश्व कल्याण में भूमिका को प्रदेश में व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करेगें। पार्टी कार्यकर्ता व्यक्तिगत सम्पर्क और डिजिटल सम्पर्क का अभियान चलाकर मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल की प्रथम वर्ष की उपलब्धियों के साथ अन्य विषयों पर जनता के बीच अपनी बात पहुंचाएंगे। प्रदेश में 6 वर्चुअल रैली भी आयोजित की जाएंगी। इन रैलियों में समाज के विभिन्न वर्ग समूह के लोग सम्मिलित होंगे। साथ ही पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा व अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम सम्पर्क संवाद का अभियान चलाएंगे।

निजीकरण के विरोध में पहली को काला दिवस मनाएंगे बिजली कर्मी

लखनऊ। बिजली के निजीकरण के लिए लाए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के विरोध में प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता पहली जून को काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाएंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों ने बताया कि 15 लाख बिजली कर्मियों के साथ उत्तर प्रदेश के भी तमाम बिजली कर्मी आगामी 1 जून को काला दिवस मनाएंगे जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों , परियोजनाओं के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर अपने कार्य पर रहते हुए पूरे दिन दाहिने बाजू पर काली पट्टी बांधकर निजीकरण हेतु लाए गए बिल का पुरजोर करेंगे और अपराहन 3 बजे से सायं 5 बजे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे।

कोरोना संकट से खड़ी हुई संवैधानिक चुनौतीः दीक्षित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- संसदीय कार्यवाही का बाधा रहित संचालन करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक

संसद और विधान सभाओं के सदनों की कार्यवाही को बाधा रहित संचालन करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक आज विधान सभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। जिसमें श्री दीक्षित ने कहा कि कोविड.19 के कारण विधायिका के समक्ष एक नई चुनौती है। ऐसे माहौल में जिन सदनों में 6 माह की अवधि व्यतीत हो रही है, उनकी बैठक संवैधानिक अपरिहार्यता के कारण बुलायी जानी है।यह समिति अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा गठित की गयी थी। इस समिति का अध्यक्ष उप्र के विस अध्यक्ष तथा इसके सदस्य के रूप में गुजरात, पंजाब, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ एव तमिलनाडु के अध्यक्षों को मनोनीत किया गया था।

श्री दीक्षित ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि विगत 2 माह से कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति के कारण बैठक सम्पन्न नहीं हो सकी। कोविड.19 के कारण विधायिका के समक्ष एक नई चुनौती है। ऐसे माहौल में जिन सदनों में 6 माह की अवधि व्यतीत हो रही है उनकी बैठक संवैधानिक अपरिहार्यता के कारण बुलायी जानी है। उन सदनों की बैठकें किस प्रकार आहूत की जाय। यह विचारणीय प्रश्न है।

प्रवासी श्रमिकों की रोजी-रोटी की समस्या का निदान सरकारों का पहला कर्तव्यः मायावती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोरोनावायरस के संक्रमण के दौरान बेसहारा लाखों प्रवासी श्रमिकों की रोजी रोटी की मूलभूत समस्या केंद्र के साथ राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय मायावती ने शुक्रवार को ट्वीट भी किया। मायावती ने कहा कि इस दिशा में श्रमिकों की समस्या सरकारों का पहला कर्तव्य है।

मायावती ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पिछले 66 दिन से लॉकडाउन के कारण हर प्रकार की उपेक्षा तिरस्कार से पीड़ित जैसे तैसे घर लौटने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए अन्ततः कोर्ट को कहना पड़ा कि रेल बस से उन्हें फ्री घर भेजने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। बीएसपी की इस माँग की सरकार अनदेखी करती रही है। किन्तु खासकर यूपी व बिहार में घर वापसी कर रहे इन बेसहारा लाखों प्रवासी श्रमिकों की रोजी रोटी की मूलभूत समस्या का समाधान करना केन्द्र व राज्य सरकारों का अब पहला कर्तव्य बनता है। इन्हें इनके घर के आसपास स्थाई रोजगार उपलब्ध कराना ही सरकार की नीयत, नीति व निष्ठा की असली परीक्षा है। वास्तव में केन्द्र ने देर से ही सही 20 लाख करोड़ रुपये का जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है उसके भी जनहित में उचित उपयोग की परीक्षा अब यहां होनी है।

बलरामपुर अस्पताल से गोरखपुर भेजी गई कोरोना जांच मशीन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- ड्रग कारपोरेशन ने पौने 12 लाख रुपए में खरीदी थी, कमरे में थी बंद

बलरामपुर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लाई गई मशीन गोरखपुर भेज दी गई है। लंबे समय से यूपी ड्रग सप्लाई कारपोरेशन की तरफ से खरीदी गई यह मशीन बलरामपुर अस्पताल में रखी थी। मानक के अभाव में अस्पताल प्रशासन के द्वारा मशीन का संचालन नहीं किए जाने की वजह से स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर मशीन को बलरामपुर अस्पताल प्रशासन से लेकर गोरखपुर भेजी गई है।

बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए यूपी ड्रग सप्लाई कारपोरेशन ने करीब पौने 12 लाख रुपए डेढ़ माह पूर्व मंगाई थी। लंबी जद्दोजहद के बाद भी बलरामपुर अस्पताल का प्रशासन इस मशीन से जांच का संचालन शुरू नहीं कर सका। मशीन ओल्ड स्पेशल वार्ड के एक कमरे में बंद पड़ी थी। जानकारों का कहना है कि लाखों रुपए कीमत की मशीन कुछ दिन न चलने पर खराब हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि बलरामपुर अस्पताल में मशीन संचालन के लिए माइक्रो बायोलॉजिस्ट तक तैनात नहीं है। न ही माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए कोई सही इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिलहाल बलरामपुर के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित करके नई मशीन मंगवाई जाएगी। उससे मरीजों की जांच की जा सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल की ओर से एक ट्रेनी महिला डॉक्टर और एक लैब टेक्नीशियन को केजीएमयू में मशीन संचालन के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। वहीं इस बारे में अस्पताल के सीएमएस डॉ आरके गुप्ता का कहना है कि कोरोना संक्रमण जांच के लिए ड्रग कारपोरेशन से मशीन आई थी। स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के निर्देश पर उसे गोरखपुर भिजवा दिया गया है।

चार तस्कर गिरफ्तार, 10 कुंतल गांजा बरामद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- एसटीएफऔर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने झांसी जिले में की कार्रवाई

एसटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने झांसी जिले में कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले चार अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से एक ट्रक में लदा 10 कुंतल गांजा बरामद हुआ है, जिसे उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया था।

एसटीएफ को सूचना मिली कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर अन्य राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर विक्रय किया जा रहा है। इसी क्रम में विश्वसनीय स्रोतों से सूचना प्राप्त की गयी कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 लोग अवैध मादक पदार्थ गांजा उड़ीसा राज्य के सम्भलपुर से रायपुर, छत्तीसगढ़ के रास्ते ला रहे है जो जनपद झांसी में सप्लाई किया जाना है। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मऊरानी थाना क्षेत्र में गांजे से लदी एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक पर सवार चार तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 कुंतल गांजा बरामद किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में शंकर बारी उर्फ विक्रम उड़ीसा, संजय कुमार सिंह छत्तीसगढ़, छोटेलाल देवरिया, उत्तर प्रदेश और विनोद कुमार सिंह बिहार का रहने वाला है। अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग गौरव गेस्ट हाउस के मालिक राजेन्द्र सर्राफ उर्फ राजू निवासी मऊरानीपुर के लिये यह तस्करी करते हैं।

मजदूरों की मदद करने वालों को निशाना बना रही सरकारः कांग्रेस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि सरकार मजदूर विरोधी रुख अख्तियार करते हुए उनकी मदद का प्रयास कर रहे कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रही है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज मालिक ने कहा कि अब तक कांग्रेस के 90 से ज्यादा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मजदूरों की सेवा के अपराध में जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि खुद उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं इलाहाबाद, बांदा, जालौन, गौतम बुद्धनगर के कई पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। योगी सरकार मजदूरों की सेवा करने के जगह मजदूरों की मदद करने वालों को निशाना बना रही है। इन फर्जी मुकदमों से हमारा सेवा कार्य नहीं रुकेगा।

नदियों को जीवित करने व रोजगार के अवसर को लेकर छेड़ी गई मुहिम

- प्रदेश की उन्नीस नदियों में शुरू होगा कार्यः मोती सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने कहा कि प्रदेश की 19 नदियों के पुनरोद्धार का कार्य प्रारम्भ किया जाय, जिससे नदियों को जीवित बनाया जा सके और इस कार्य के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। उन्होंने पुनरोद्धार के कार्य को प्राथमिकता दिये जाने की भी हिदायत दी । प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 19 नदियां यथा सई, पांडु, मंदाकिनी, टेढी, मनोरमा नदी, वरुणा नदी, ससुर खदेरी, अरिल, मोरवा, तमसा, नाद, कर्णावती, बान, सोन, काली पूर्वी , डाढी, ईशन, बूढ़ी गंगा तथा गोमती नदियों के पुनरोद्धार का कार्य किया जाएगा । इस क्रम में सई नदी, मंदाकिनी नदी तथा पांडु नदी को प्रथम चरण में चयनित करते हुए उनके पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । नदियों के पुनरोद्धार के संबंध में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु ग्राम्य विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें जल शक्ति मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री सदस्य होंगे । इसके साथ ही नदियों के पुनरोद्धार के कार्य में बेहतर समन्वय हेतु राज्य स्तर पर ग्राम विकास विभाग द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने बैठक में निर्देश दिया कि चयनित नदियों का विस्तृत डीपीआर सिंचाई विभाग के माध्यम से बनवा लिया जाए। बैठक में मौजूद जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि नदियों के पुनरोद्धार कार्य को प्राथमिकता देते कार्ययोजना तैयार कराया जाय। इसके साथ ही जलाशय, डैम, चेक डैम की शिल्ट साफ करायी जाय । इससे मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के साथ ही सभी सिंचाई प्रणालियों को जीवनदान मिलेगा। उन्होंने शिल्ट सफाई के बाद निकाली गयी मिट्टी का निस्तारण कराते हुए राजस्व अर्जित करने का भी सुझाव दिया ताकि नहरी आदि के सफाई के लिए अलग से धन की जरूरत न पड़े।

राजकीय निर्माण निगम के स्थानिक अभियन्ता निलम्बित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर शुक्रवार को अनिल कुमार स्थानिक अभियन्ता सिविल, तत्कालीन इकाई प्रभारी अयोध्या को

- अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायत पर हुई कार्रवाई

तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। राजकीय निर्माण निगम प्रबन्ध निदेशक यूके गहलौत ने बताया कि निलंबित किए गए अभियंता अनिल कुमार को अति. महाप्रबन्धक तकनीकी, राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध कर दिया गया है। श्री गहलौत ने बताया कि अनिल कुमार के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुयी थी। शिकायत की गम्भीरता के दृष्टिगत इन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

जहरखुरानी व विदेशी यात्रियों से चोरी की घटनाएं अब विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने राजकीय रेलवे पुलिस के अंतर्गत होने वाले जहरखुरानी सहित आधा दर्जन अपराधों को विशेष आख्या अपराध (एसआर केस) की श्रेणी में रखकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में डीजीपी की ओर से एडीजी रेलवे आईजी रेलवे व जीआरपी के सभी पुलिस कप्तानों को परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर .101 में इंगित कतिपय अपराधों को राजकीय रेलवे पुलिस में विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुए कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने निर्देशित किया है कि राजकीय रेलवे पुलिस में रेल यात्रियों के साथ व रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ विशेष प्रकार के अपराधों में गहन विवेचना, सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कार्रवाई की आवश्यकता होती है । पूर्व में निर्गत परिपत्र में इंगित विशेष आख्या अपराधों सहित निम्नलिखित अपराधों को भी राजकीय रेलवे पुलिस से सम्बन्धित विवेचनाओं के उच्चस्तरीय एवं बेहतर पर्यवेक्षण के उद्देश्य से विशेष आख्या अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है।

गुजरात में न्यायाधीशों के रोस्टर में बदलाव चिंता का विषय है: कांग्रेस

मुम्बई। महाराष्ट्र कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय की कोविड–19 संकट से निपटने की राज्य सरकार के तौर तरीके पर तीखी टिप्पणी की पृष्ठभूमि में वहां न्यायाधीशो के रोस्टर में बदलाव चिंता का विषय है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि पिछले छह सालों में भाजपा शासित गुजरात में कई न्यायाधीशों का आकस्मिक तबादला किया गया। उनमें से ज्यादातर न्यायाधीश या तो संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे थे या उनकी टिप्पणी एवं फैसले भाजपा सरकार के विरूद्ध थे। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि इन तबादलों को नियमित बताया गया।

सावंत ने कहा कि गुजरात में न्यायाधीशों के रोस्टर में नवीनतम परिवर्तन चिंता पैदा करते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब एक ही दिन पहले गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना वायरस महामारी के संबंध में स्वत: संज्ञान के रूप में ली गई एक जनहित याचिका और अन्य संबंधित अर्जियां नई पीठ को सौंप दी।

पिछली पीठ ने इस संकट से निपटने के गुजरात सरकार के तौर तरीके पर और खासकर अहमदाबाद सिविल अस्पताल की दशा पर कुछ तीखी टिप्पणी की थी। सावंत ने कहा कि न्यायाधीशों ने दो दिन पहले ही स्वास्थ्य प्रणाली की दयनीय दशा पर पर गुजरात सरकार को भला–बुरा कहा था। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा कोरोना वायरस संकट से निपटने के तौर तरीको में भयंकर खामियां हैं और गुजरात में महाराष्ट्र के बाद कोविड–19 के सबसे अधिक मामले हैं।

गुजरात सरकार ने स्वयं ही उच्च न्यायालय के सामने माना कि वह इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित अहमदाबाद में पर्याप्त कोरोना वायरस परीक्षण नहीं कर रही है। जब अहमदाबाद के निगम आयुक्त विजय नेहरा ने कहा कि मई के अंततक शहर में आठ लाख कोविड–19 मामले होंगे तब उनका तत्काल तबादला कर दिया गया। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला और आई जे वोरा की खंडपीठ ने शनिवार को अपने आदेश में अहमदाबाद सिविल अस्पताल को कालकोठरी करार दिया था। यह पीठ कोविड–19 से जुड़े सभी मुद्दों पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़णनीस ने राज्य की एमवीए सरकार पर कोरोना वायरस संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। तब से महाराष्ट्र सरकार गुजरात की भाजपा सरकार को कोविड–19 के मुद्दे पर निशाना बना रही है।

तमिलनाडु में दो मंदिरों के बाहर मांस मिलने से तनाव

कोयंबटूर। तमिलनाडु के कोयंबटूर में दो मंदिरों के बाहर असामाजिक तत्वों द्वारा कच्चा मांस बिखेरे जाने के बाद शुक्रवार को तनाव फैल गया। मांस के बारे में माना जा रहा है कि यह सुअर का है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों और भक्तों ने यहां सुल्लिवन मार्ग पर स्थित वेणुगोपाल स्वामी और श्री राघवेंद्र मंदिरों के बाहर मांस पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जो मौके पर पहुंच गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस बलों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। विभिन्न हिंदू संगठनों के नेता भी मौके पर पहुंचे और दोषियों को पकड़े जाने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई की महासचिव वी श्रीनिवासन ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्वाई किए जाने की मांग की। यह पता चला है कि दोपहिया वाहन पर सवार लोग आए और उन्होंने वेणुगोपाल स्वामी तथा श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर के परिसर के भीतर सुअर के मांस का टुकड़ा फेंका।

जबलपुर में कुएं से पानी निकालते ग्रामीण।

तबलीगी जमात के नकद लेन-देन और विदेशी चंदे की प्रारंभिक जांच शुरू

भाषा। नई दिल्ली

सीबीआई ने कथित तौर पर संदिग्ध नकद लेन–देन करने और विदेशी चंदा प्राप्त करने की बात अधिकारियों से छिपाने को लेकर तबलीगी जमात के आयोजकों के खिलाफ एक प्रारंभिक जांच दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने जांच में किसी खास व्यक्ति को नामजद नहीं किया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह जांच एक शिकायत पर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया है कि जमात के आयोजक अवैध एवं अनुचित तरीकों से संदिग्ध नकद लेन–देन में संलिप्त हैं। उन्होंने बताया कि यह भी आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने विदेशी चंदा प्राप्त करने की बात का खुलासा अधिकारियों के समक्ष नहीं किया, जबकि इस तरह के उद्देश्य के लिए विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम के तहत जानकारी दी जानी चाहिए थी।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बाद तबलीगी जमात के वित्तीय लेन–देन की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मार्च के प्रथम पखवाड़े में तबलीगी जमात के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले इसके कई सदस्यों के कोविड–19 से संक्रमित होने की खबरें मीडिया में सुर्खियों में रही थी।

अधिकारियों ने बताया कि किसी मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी विस्तृत जांच पर आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री है या नहीं, उस बारे में फैसला करने के लिए प्रारंभिक जांच शुरुआती कदम है। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न प्राधिकारों से जमात के रिकार्ड जुटाना शुरू कर दिया है और इस बारे में पत्र भेजे हैं।

भाजपा विधायकों की बैठक ने दी अटकलों को हवा मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाने की खबरें की खारिज

भाषा। बेंगलुरू

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा ने इन रिपोर्टों को शुक्रवार को खारिज कर दिया कि बेलगावी में भाजपा विधायकों के एक समूह की बैठक के बाद उन्होंने कुछ पार्टी विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। बेलगावी में भाजपा विधायकों के एक समूह की बैठक के बाद सत्तारूढ़ पार्टी में असंतोष की अटकलों को बल मिल गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उत्तरी कर्नाटक के विधायकों ने राज्य से राज्यसभा की चार सीटों के लिए आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि में बेलगावी जिले के बेल्लाद बागेवाडी में पूर्व सांसद रमेश कट्टी के आवास पर बृहस्पतिवार शाम को मुलाकात की।

ऐसा माना जा रहा है कि विधायक उमेश कट्टी के भाई रमेश कट्टी को चार में से एक सीट दिलाने के लिए उनके समर्थन में यह बैठक की गई इससे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों के उस समूह के बीच अंसतोष की अटकलों को हवा मिल गई है, जिन्हें पिछले साल जून में एदियुरप्पा के सत्ता में वापस आने पर मंत्री का पद नहीं मिला था। इस बैठक के बाद मीडिया में इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि मुख्यमंत्री तसल्ली देने के लिए कुछ विधायकों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन एदियुरप्पा ने इन दावों को खारिज कर दिया है।

उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया, मैंने कुछ समाचार चैनलों में प्रसारित की जा रही खबरें देखी हैं कि मैंने कुछ विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस प्रकार की कोई बैठक नहीं बुलाई है। इस बीच रमेश कट्टी ने अपने आवास में बैठक होने की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इसका राज्यसभा चुनाव से कोई लेना–देना नहीं है। हालांकि, उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि उनके भाई उमेश को एदियुरप्पा सरकार में मंत्रिपद नहीं दिया गया। रमेश के अनुसार एदियुरप्पा ने उमेश कट्टी को भरोसा दिलाया था कि उन्हें (रमेश) राज्यसभा सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने हाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें इसके बारे में (राज्यसभा सीट) याद दिलाया। मुख्यमंत्री ने भी ऐसा करने का भरोसा दिया।

उमेश ने भी कहा कि बैठक में राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा, हम लंबे समय से मिले नहीं थे, इसलिए एक–दूसरे से मिलने के लिए भोज का आयोजन किया गया था... हमने राजनीति या असंतोष या विद्रोह से संबंधित किसी बात पर चर्चा नहीं की। मैं एक जिम्मेदार विधायक हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे समय में इस प्रकार की चीजों पर बात करना उचित नहीं है।

बैठक में शामिल हुए भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने एदियुरप्पा को लेकर अंसतोष जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से विधायकों के कई बार कहने के बावजूद कुछ काम पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने इन कामों के बारे में जानकारी नहीं दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बैठक में शामिल हुए विधायकों ने अपने सुख–दु:ख साझा किए। यह पूछे जाने पर कि क्या एदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि वह मीडिया में इस बारे में बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मैं हमारे आला कमान के कहे का पालन करूंगा... यदि वे कहते हैं कि मुख्यमंत्री को बने रहना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए और यदि वे नेतृत्व में बदलाव करना चाहते हैं तो हम उसका पालन करेंगे।

महाराष्ट्र में विधानसभा का मानसून सत्र छोटा करने पर विचार

मुम्बई। कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र कम अवधि के लिए ही सही लेकिन राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पहले विधानसभा की बैठक करने और फिर उसके बाद 78 सदस्ईय परिषद की बैठक आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में 288 सदस्य हैं इसलिए सत्र विधानसभा इमारत में निर्धारित निचले सदन की बजाय सेंट्रल हॉल में भी आयोजित किया जा सकता है ताकि विधायकों के बीच उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके। सेंट्रल हॉल काफी बड़ा है और सामान्य परिस्थितियों में दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठकें वहां होती हैं। सूत्र ने बताया कि सत्र की अवधि, तारीख आदि का निर्णय व्यवसाय सलाहकार समिति (बीएसी) नौ जून को होने वाली बैठक में लेगी। बीएसी में सरकार और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल हैं। इससे पहले मानसून सत्र 22 जून को शुरू होने वाला था।

नगालैंड: चेन्नई से लौटे सात व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि

कोहिमा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से चेन्नई से नगालैंड पहुंचने के कुछ दिन बाद, शुक्रवार को सात व्यक्तियों मे कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई जिसके बाद राज्य मे कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। स्वास्थ्य मंत्री एस पांगंयु फोम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए सामने आए मामलों में से दो दीमापुर, चार कोहिमा और एक तुएनसांग जिले का है। उक्त सभी संक्रमित व्यक्ति 22 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से चेन्नई से वापस आए थे। ट्रेन से राज्य के,328 निवासी वापस आए थे जो लॉकडाउन के कारण तमिलनाडु में फंसे रह गए थे। नगालैंड में संक्रमण के कुल 25 मामलों में से 13 मरीजों का दीमापुर के अस्पताल मे उपचार चल रहा है। कोहिमा के छेडेमा अस्पताल मे सात और तुएनसांग के अस्पताल में कोविड-19 के पांच मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी तक राज्य में कोविड-19 से किसी की मौत की खबर नही आई है।

राजद विधायकों और पुलिस के बीच कहासुनी

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता पर रविवार की रात हुए जानलेवा हमले और उनके परिवार के तीन लोगों की हत्या के खिलाफ गोपालगंज जिले की ओर कूच करने के लिए शुक्रवार को 10, सर्कुलर रोड पर जमा हुए पार्टी विधायकों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। इस हत्याकांड में सत्तारूढ़ जद(यू) के कुचाईकोट से विधायक अमरेन्द्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय कथित रूप से संलिप्त है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी विधायकों को प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया था, यह नोक-झोंक वहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने धमकी दी थी कि अगर पांडेय को बृहस्पतिवार शाम तक गिरफ्तार नही किया गया तो वह अपने समर्थकों के साथ मिलकर गोपालगंज के लिए कूच करेंगे। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास राजभवन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग के पास स्थित है। उनके आवास पर तैनात पुलिस ने वहां जमा हुए राजद विधायकों से अनुरोध किया कि वे तितर-बितर हो जाएं और कोविड-19 के मद्देनजर दो गज की दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करें। तेजस्वी यादव इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे।

हर जिले में कोविड-19 जांच लैब संभव नहीं : महाराष्ट्र सरकार

मुंबई।महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि राज्य के हर जिले में कोविड-19 जांच प्रयोगशाला (लैब) स्थापित करना व्यावहारिक रूप से संभव नही है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के.के. ताटेड के समक्ष पेश किए गए एक नोट में सरकार ने कहा कि अभी राज्य में 72 जांच केंद्र हैं। शुरूआत में जब महामारी शुरू हुई थी, तब सिर्फ तीन जांच केंद्र--नागपुर, मुंबई और पुणे मे एक-एक--थे।अतिरिक्त सरकारी वकील मनीष पाबले ने अदालत से कहा, जांच प्रयोगशाला की संख्या अब बढ़ कर 72 हो गई है, जिनमें 42 प्रयोगशाला सरकारी अस्पतालों में है, जबकि शेष 33 निजी प्रयोगशाला हैं। पीठ खलील वास्ता नाम के एक मछुआरे की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने गैर-रेड जोन जिलों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने को लेकर सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। पीठ को शुक्रवार को पाबले ने बताया कि रत्नागिरि सदर अस्पताल में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। हालांकि सरकार ने अदालत से कहा कि संसाधनों एवं तकनीकी बुनियादी ढांचा के अभाव के चलते राज्य के हर जिले में प्रयोगशाला स्थापित करना संभव नही है। अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए दो जून की तारीख निर्धारित की है।

डिब्रूगढ़ के पलटन बाजार स्थित पोलो मैदान में बम डिफ्यूज करने की तैयारी करते सेना के जवान

आंध्र में राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कम करने संबंधी अध्यादेश किया खारिज

अमरावती। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार को झटका देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त (एसईसी) का कार्यकाल पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष करने संबंधी 10 अप्रैल के अध्यादेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी कानागराज की नियुक्ति के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने एसईसी के रूप में सेवानिवृत्त नौकरशाह निम्मागड्डा रमेश कुमार को बहाल किया। रमेश कुमार ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का हवाला देते हुए स्थानीय निकाय चुनाव स्थगित कर दिए थे, जिसके बाद से वह मुख्यमंत्री रेड्डी के निशाने पर आ गए थे। न्यायमूर्ति कानागराज ने 11 अप्रैल को एसईसी के रूप में कार्यभार संभाला था। रमेश कुमार को पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार में नियुक्त किया गया था।

अदालत में रमेश कुमार की याचिका समेत कई रिट याचिकाएं दाखिल करके अध्यादेश और नए एसईसी की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जे रवि शंकर ने बताया कि अदालत ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास एसईसी के कार्यकाल में कटौती करने का अधिकार नहीं हैं और उसने नए एसईसी की नियुक्ति को भी खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं की सभी दलीलों पर विचार किया। वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने 10 अप्रैल को आंध्र प्रदेश पंचायत राज कानून, 1994 में संशोधन संबंधी अध्यादेश लाकर एसईसी का कार्यकाल, पांच साल से कम करके तीन साल कर दिया था और रमेश कुमार को अचानक पद से हटा दिया था। रमेश कुमार ने 15 मार्च को होने वाले ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कोविड–19 महामारी के मद्देनजर स्थगित कर दिए थे, जिसके बाद से मुख्यमंत्री उनसे खफा थे और उन्होंने राज्यपाल से भी इसकी शिकायत की थी।

भाजपा का मुख्य एजेंडा पूरा हुआ लेकिन कोविड-19 ने नई चुनौतियां पैदा की

भाषा। नई दिल्ली

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में विचारधारा से जुड़े भाजपा के मुख्य एजेंडे को अमल में लाने का काम किया लेकिन कोविड–19 से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के समक्ष बड़ी चुनौती पैदा हो गई है और ध्यान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की ओर आ गया है। भाजपा नीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की दूसरी सरकार शनिवार को अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। ऐसे में पहले साल को हिन्दुत्व विचारधारा से जुड़ी दशकों पुरानी मांग को पूरा करने के रूप में याद किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल हुई थी जो मुख्य एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपेक्षा के रूप में देखी जा रही थी।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे से जुड़े अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण जैसे दो मुद्दे का समाधान निकालने के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ए दोनों मुद्दे कई दशकों से भाजपा के घोषणापत्र में शामिल रहे हैं और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। सरकार ने अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने वाला विधेयक पारित कराने के साथ संसद में एक प्रस्ताव पारित करके जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। वहीं, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के आदेश से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

ये दोनों विषय हिन्दुत्व के एजेंडे में शीर्ष पर थे और भाजपा की विचारधार से जुड़े थे। इन मुद्दों की पैरोकारी करने के कारण ही भाजपा को 90 के दशक में सहयोगी जुटाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा भाजपा नीत सरकार ने मुस्लिम समुदाय में एक बार में तीन तलाक को अपराध बनाने वाला कानून बनाया। इसके अलावा विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित कराया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दूसरे कार्यकाल के लिए 30 मई 2019 को शपथ ली थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था।भाजपा के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने पीटीआई भाषा से कहा कि मोदी 2.0 ने अपने पहले साल में अपने सभी वायदों को पूरा किया। उन्होंने कहा, सरकार का पहला साल दृढ़ता, साहस और प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। पहला कार्यकाल कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने से जुड़ा था और इसके परिणाम भी सामने आए। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और सीएए का कदम स्वभाविक था क्योंकि भाजपा को 2019 में एक बार फिर से और बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ था। सीएए के पारित होने से मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों के ऐसे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता का मार्ग प्रशस्त हुआ जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं। इसके कारण कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने पर चर्चा नहीं की है। इसको लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा। इसी दौरान, कोविड–19 देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया और इस दौरान प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। इस महामारी का स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव सामने आया है। कोविड–19 ने सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती पेश कर दी है। सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि सरकार और भाजपा ने कोविड–19 की चुनौती से काफी साहस के साथ मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति में चुनौती को अवसर में बदलने का रास्ता महत्वपूर्ण है। कोविड–19 के कारण इस बार भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को सामान्य रूप से ही मनाया जाएगा। पिछले कुछ महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी संगठन और मोदी सरकार का मुख्य जोर कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने पर ही केंद्रीत रहा है। इस वर्ष के प्रारंभ में ही जे पी नड्डा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इससे पहले अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे जिन्हें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृह मंत्री का दायित्व सौंपा गया।

चुनावी मोर्चे पर भाजपा को झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वह मध्यप्रदेश और कर्नाटक में सत्ता प्राप्त करने में सफल रही। कर्नाटक में बी एस एदियुरप्पा और मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। इस दौरान हालांकि भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना उससे अलग हो गई और महाराष्ट्र में शिवसेना ने राकांपा और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जून से एक महीने का अभियान शुरू करेगी जिसमें देश के हर जिले में कम से कम एक वर्चुअल रैली आयोजित करना शामिल है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल

जयपुर में स्पेशल बस से उतरने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए प्रवासी।

पायनियर
नई दिल्ली, शनिवार, 30 मई, 2020

कर्नाटक के मंत्री का दावा

कांग्रेस के 22 विधायक संपर्क में

भाषा। बेंगलुरु

कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस के 22 विधायक उनके संपर्क में हैं और यदि भाजपा आलाकमान ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी, तो वह एक हफ्ते के अंदर परीक्षण के आधार पर उनमें से पांच का दल-बदल करा सकते हैं। इस पर फौरन ही कांग्रेस ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी से सिर्फ यह प्रदर्शित होता है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जरकीहोली ने चमराजनगर में संवाददाताओं से कहा, मेरे संपर्क में कांग्रेस के 22 विधायक हैं, लेकिन मैं परीक्षण के आधार पर उनमें से पांच को एक हफ्ते के अंदर तोड़ (भगवा पार्टी के पाले में ला) सकता हूं। गौरतलब है कि राज्यसभा की चार सीटों के लिए राज्य में होने वाले चुनाव के मद्देनजर एक दिन पहले उत्तर कर्नाटक के विधायकों के एक समूह ने बेलगावी जिले में पूर्व सांसद रमेश कट्टरी के आवास पर एक बैठक की थी। बैठक में शरीक होने वालों में शामिल विजयपुर से भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने राज्य मुख्यमंत्री बी एस एदियुरप्पा के कामकाज की शैली पर असंतोष प्रकट करते हुए कहा कि कुछ कार्य पूरे नहीं किए गए, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष इनका जिक्र किया था। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से कार्य थे। जरकीहोली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बैठक का ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए और उन्होंने दावा किया कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से चीजें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा, (एदियुरप्पा) सरकार अगले तीन साल, बल्कि मौजूदा कार्यकाल खत्म होन के बाद पांच साल के लिए भी सुरक्षित है। जरकीहोली की टिप्पणी पर कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सत्तारूढ़ भाजपा में सबकुछ ठीक नहीं है और यह सिर्फ भगवा पार्टी के विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश हे। पार्टी प्रवक्ता ए एन नटराज गौड़ा ने पीटीआई-भाषा से कहा, यदि सरकार स्थिर है, तब दल-बदल कराने की कोशिश करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, यह भाजपा के असंतुष्ट विधायकों को एक संदेश देने की कोशिश है कि यदि वे पार्टी छोड़ भी देते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। गौड़ा ने कहा कि एक साल के अंदर एदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस बीच, राज्य के कृषि मंत्री बी सी पाटिल ने भी कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है।

एदियुरप्पा के बेटे बी वाई विजएंद्र के सरकार में कथित तौर पर दखलंदाजी करने से जुड़े सवाल के जवाब में पाटिल ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सरकार में किसी अहम पद पर है, तब पारिवारिक संबंधों को तोड़ देना कैसे संभव है। पाटिल ने कहा, हमें यह निष्कर्ष क्यों निकालना चाहिए कि सरकार में उनकी भागीदारी दखलंदाजी है। जरकीहोली और बी सी पाटिल उन प्रमुख बागी नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने असंतुष्ट खेमे का नेतृत्व किया था। वे 2018 में कांग्रेस विधायक के तौर पर निर्वाचित हुए थे। लेकिन भाजपा में शामिल होने के लिए जून 2019 में कर्नाटक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वे दिसंबर 2019 में विधानसभा उपचुनाव जीते और एदियुरप्पा सरकार में मंत्री बन गए।

इस वर्ष लिपुलेख मार्ग से चीन के साथ सीमा व्यापार नहीं करेंगे उत्तराखंड के स्थानीय लोग

पिथौरागढ़। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों ने इस साल लिपुलेख दें के जरिए चीन के साथ सीमा व्यापार में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। धारचूला के उप संभागीय मजिस्ट्रेट ए के शुक्ला ने कहा कि बुधवार को प्रशासन द्वारा बुलाई गई तैयारी बैठक के दौरान उन्होंने वार्षिक व्यापार गतिविधियों में भाग लेने के प्रति अनिच्छा प्रकट की। शुक्ला ने कहा, भारतीय व्यापारियों ने कोविड-19 के खिलाफ एहतियात के तौर पर इस साल लिपुलेख दें के जरिए चीन के साथ व्यापार नहीं करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से सीमा व्यापार को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत-चीन व्यापार संगठन के संरक्षक विशान गर्ब्याल ने कहा, चीन इस घातक वायरस का केंद्र रहा है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए और उस देश में प्रवेश नहीं करना चाहिए। पिथौरागढ़ जिले की चांद घाटी में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दें के माध्यम से भारत-चीन सीमा व्यापार, 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद दशकों तक निलंबित रहने के बाद 1992 में फिर से शुरू हुआ था। यह हर साल जून में शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता है।

अहमदाबाद में शुक्रवार को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गश्त के बाद वापसी पर खुद को कीटाणुरहित करवाते सीमा सुरक्षा बल के जवान

झारखंड सरकार ने लेह में फंसे 60 प्रवासी मजूदरों को विमान के जरिए वापस लाने का किया प्रबंध

भाषा। लेहा, नई दिल्ली

सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करके अपने घर लौटने को मजबूर हुए प्रवासी मजदूरों की मार्मिक कहानियों के बीच झारखंड सरकार ने शुक्रवार को लद्दाख में फंसे अपने राज्य के 60 श्रमिकों को विमान के जरिए वापस लाने की पहल करके एक उम्मीद की किरण दिखाई है। ये सभी प्रवासी मजूदर लद्दाख में सीमा सड़क संगठन परियोजना में कार्यरत थे। दो महीने के तनाव और अनिश्चितता के बाद 60 मजदूरों का यह समूह विमान के जरिए दोपहर को नई दिल्ली पहुंचा और फिर यहां से शाम को अपने गृह राज्य झारखंड की उड़ान में सवार हुआ। सोमवार से घरेलू यात्री उड़ान शुरू होने के बाद से कई ऐसे मामले सामने आए, जिसमें संस्थानों अथवा नियोक्ताओं ने फंसे हुए श्रमिकों को विमान के जरिए वापस भेजने का प्रबंध किया। यद्यपि, यह पहला मामला है, जब किसी राज्य सरकार ने एक साथ कई प्रवासी मजदूरों को वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए लाने का प्रबंध किया हो। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड के दुमका जिले के रहने वाले मजदूर कारगिल जिले के बटालिक में फंसे हुए थे। सभी मजदूरों को चिकित्सीय परीक्षण के बाद सीमा सड़क संगठन की सहायता से बृहस्पतिवार को लेह लाया गया और उन्हें शिविर में ठहराया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, हम अपने प्रवासी मजूदरों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सरकार 60 मजदूरों को विमान के जरिए वापस ला रही है जोकि बटालिक-कारगिल में फंसे हुए थे। उन्हें लेह से रांची लाया जा रहा है। सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अंडमान-निकोबार, लद्दाख और उत्तर-पूर्वी राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को निजी विमान के जरिए वापस लाने की अनुमति देने की मांग की थी क्योंकि वहां से मजदूरों को वापस लाने के लिए कोई अन्य परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा, हालांकि, केंद्र की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री ने आगे बढ़कर प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए वाणिज्यिक उड़ानों का प्रबंध किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को वापस लाने के लिए करीब आठ लाख रुपए का खर्च आया। सूत्र ने कहा कि मजदूरों का समूह स्पाइसजेट की उड़ान के जरिए लेह हवाईअड्डे से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा। फिर दिल्ली हवाईअड्डे से इंडिगो की उड़ान से छह बजे रांची के लिए उड़ान भरी। लेह हवाईअड्डे से एक प्रवासी मजदूर जॉन पोलस हंसदा ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस बात की उम्मीद खो चुके थे कि वे दोबारा अपने परिवार को देख सकेंगे लेकिन मैंने मजूदरों से कहा कि हम अपने गांव लौटेंगे।

प्रज्ञा ठाकुर के लापता के पोस्टर: भाजपा ने कहा दिल्ली एम्स में हैं भर्ती

भाषा। भोपाल

भोपाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से एक चलित अस्पताल सेवा शुरू करने के बाद भी शुक्रवार को उनके लापता होने के पोस्टर शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे दिखाई दिए। भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि कैंसर और आंखों के इलाज के लिए प्रज्ञा अस्पताल में भर्ती हैं। भोपाल में लगे इन अनाम पोस्टरों में कहा गया है कि शहर के लोग कोरोना संक्रमण की महामारी से परेशान हैं और ऐसे में भोपाल की भाजपा सांसद लापता हैं। इस बीच, सांसद प्रज्ञा ने वीडियों कॉल के माध्यम से सहकार भारती द्वारा बैरागढ़ चिचली क्षेत्र में संचालित चलित अस्पताल सेवा शुरू की। सहकार भारती के पदाधिकारी उमाकांत दीक्षित ने दावा किया कि प्रज्ञा लापता नहीं हैं बल्कि दिल्ली के एक अस्पताल में हैं और स्वस्थ्य नहीं हैं। दीक्षित ने कहा कि वह फोन पर कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं और कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से परेशान प्रवासियों, विद्यार्थियों और जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इन पोस्टरों का समर्थन करते हुए कहा कि इस संकटपूर्ण समय में लोगों को अपनी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बारे में जानने का हक है।

न्यायालय इंडिया शब्द में बदलाव पर दो जून को करेगा सुनवाई

भाषा। नई दिल्ली

संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या हिन्दुस्तान करने का निर्देश केन्द्र को दिए जाने के लिए दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय दो जून को सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिन्दुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं। इस याचिका पर शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन इसे सूची से हटा दिया गया था।

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नोटिस के अनुसार, इस मामले की सुनवाई अब दो जून को प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद। में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर, देश को भारत या हिन्दुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की, औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। याचिका में 1948 में संविधान सभा में संविधान के तत्कालीन मसौदे के अनुच्छेद। पर हुई चर्चा का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि उस समय देश का नाम भारत या हिन्दुस्तान रखने की पुरजोर हिमायत की गई थी।

● याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिन्दुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं

याचिका के अनुसार, यद्यपि यह अंग्रेजी नाम बदलना सांकेतिक लगता हो लेकिन इसे भारत शब्द से बदलना हमारे पूर्वजों के स्वतंत्रता संग्राम को न्यायोचित ठहराएगा। याचिका में कहा गया है कि यह उचित समय है कि देश को उसके मूल और प्रमाणिक नाम भारत से जाना जाए।

केवल चार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को गंतव्य पर पहुंचने में लगे 72 घंटे: रेलवे

भाषा। नई दिल्ली

ट्रेनों के भटक जाने की खबरों पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी के यादव ने शुक्रवार को कहा कि एक मई से जब से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने लगी हैं, तब से अबतक कुल 3840 ऐसी ट्रेनों में केवल चार ट्रेनों ने ही अपने गंतव्य पर पहुंचने में 72 घंटे लिए।

उन्होंने यह भी कहा कि इन प्रवासी ट्रेनों में 90 फीसद ट्रेनें नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक औसत रफ्तार से चलीं। यादव ने कहा, 20-24 मई के दौरान, उत्तर प्रदेश और बिहार से अधिक मांगें होने के कारण 71 ट्रेनों के मार्ग बदले गए, क्योंकि देशभर से 90 फीसद ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार ही जा रही थीं। बिहार के लिए 51 ट्रेनों, उत्तर प्रदेश के लिए 16, झारखंड के लिए दो और मणिपुर के एक ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया। मार्ग परिवर्तन वाली ट्रेनें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान से चली थीं। यह स्पष्टीकरण तब आया है जब विलंब को लेकर यहां तक कह दिया गया कि प्रवासी ट्रेनें अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही गायब हो रही हैं। यादव के अनुसार 28 मई तक 3840 ट्रेनों ने 52 लाख यात्रियों को पहुंचाया।

उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में 1524 श्रमिक ट्रेनें चली हैं और 20 लाख से अधिक यात्री पहुंचाए गए। उन्होंने कहा, रेलवे ने भेजने वाले राज्यो के कभी सभी अनुरोधों को समायोजित किया और हम श्रमिकों की आवाजाही की सभी मांग पूरा करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष ने कहा, फिलहाल हमारे पास 492 ट्रेनों की मांग है। यादव ने यह भी कहा कि रेवले ने उन लोगों की सूची तैयार की जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मर गए। उन्होंने साथ ही पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे, गर्भवती महिलाओ और बुजुर्गों से अनावयक यात्रा से बचने की अपील की।

गुजरात के सीएम ने लोगों से कहा की लॉकडाउन के बारे में अफवाहों पर भरोसा न करें

अहमदाबाद। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने शुक्रवार को लोगों से अपील की कि वह कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन से संबंधित अफवाहों पर भरोसा नहीं करें। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त होने वाला है। रूपाणी को यह स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि राज्य सरकार एक जून से पूर्ण लॉकडाउन करने की योजना बना रही है क्योंकि प्रदेश में कोविड19 के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन का आदेश देगी। सबकुछ बंद करने का आदेश देगी। लोगों को इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और ऐसे चीजों के प्रसार से भी बचना चाहिए।

पेज एक का शेष

मोदी-ट्रंप...

में चार बार हो चुकी झड़प के बाद तनाव को खत्म करने के लिए कूटनयिक और सैन्य स्तर प्रयास जारी हैं। सेनाओं के स्थानीय कमांडरों के बीच सात दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा था कि भारत और चीन सैन्य तथा राजनयिक दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों ने सीमा पर शांति और स्थिरिता को बरकरार रखने के लिए कई प्रोटोकाल पर दस्तखत किए है। इस मुद्दे पर कई समझौते हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले 25 दिनों में भारत और चीन की सेनाओं के बीच चार स्थानों पर झड़प हो चुकी है। चीनी गलवान घाटी के हॉट स्प्रिंग इलाके में घुसपैठ की थी और यहां पर उसके 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। चीनी सेना गलवान घाटी में एलएसी के समानांतर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 250 किमी. लंबी रोड पर पुल के निर्माण पर एतराज जता रही है। लेकिन भारत का कहना है कि यह सड़क उसकी सीमा में हैं और वह किसी भी प्रकार से एलएसी का उल्लंघन नहीं कर रहा है। चीन ने एलएसी के बराबर में अपनी सीमा में बंकरों का निर्माण किया है और सैनिकों को ढोने वाले हथियारों से लैस भारी वाहनों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा उसने हेलीकॉप्टर से भी हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। भारत ने भी अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी है। साथ ही मालवाहक विमानों की उड़ान और लैंडिंग की तैयारी की अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ाई हैं। सूत्रों को कहना है कि यदि कोई समाधान नहीं निकला और गतिरोध बना रहा तो ये तैयारियां जरूरी हैं। सेना के शीर्ष कमांडरों की दो दिवसीय कमांडर्स कांफ्रेंस में गुरुवार को एलएसी पर चीन के आक्रामक रुख पर स्थिति की समीक्षा की गई। इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की शुक्रवार को अपने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर के अनुरोध पर टेलोफोन पर वार्ता हुई। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से जंग में अपने अनुभवों को साझा किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा की और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता जताई। सिंह ने एस्पर को भारत यात्रा का न्योता दिया।

चीन ने...

व्यक्त करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि दोनों देश मौजूदा सैन्य गतिरोध सुलझाने के लिए तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। झाओ ने यहां संवाददाता सम्मेलन में ट्रम्प के प्रस्ताव के बारे में पूछे जाने पर कहा, चीन और भारत के बीच सीमा संबंधी तंत्र और संवाद माध्यम हैं। उन्होंने कहा, हम वार्ता एवं विचार-विमर्श के जरिए अपने बीच मौजूद समस्याओं को उचित तरीके से सुलझाने में सक्षम हैं। हमें तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ट्रम्प ने बुधवार को एक ट्वीट किया था, हमने भारत और चीन, दोनों को सूचित किया है कि अमेरिका सीमा विवाद में मध्यस्थता करने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। उन्होंने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बृहस्पतिवार को फिर से अपनी यह पेशकश दोहराई। इस ट्वीट पर एक सवाल के जवाब में ट्रम्प ने कहा कि अगर मदद के लिए बुलाया गया तो मैं मध्यस्थता करुंगा। अगर उन्हें लगता है कि इससे मदद मिलेगी तो मैं यह करूंगा। ट्रम्प की मध्यस्थता की पेशकश पर बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने बुधवार को कहा था कि वह सीमा संबंधी विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए चीन से बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में सवालों का जवाब देते हुए कहा, हम इसके शांतिपूर्वक समाधान के लिए चीनी पक्ष के साथ बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले, ट्रम्प ने कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, लेकिन नई दिल्ली ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा, चीन-भारत सीमा के मामले पर चीन का रुख स्पष्ट है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। झाओ ने कहा, हम दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी अहम आम सहमति लागू कर रहे हैं, द्विपक्षीय समझौतों का पालन कर रहे हैं, क्षेत्रीय सम्प्रभुता की रक्षा करने और सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता एवं शांति को लेकर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपने पहले दिए बयान को दोहराते हुए कहा, चीन-भारत सीमा क्षेत्र में अब समग्र स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। बृहस्पतिवार को चीन के सरकारी समाचर पत्र ग्लोबल टाइम्स के एक विचार पृष्ठ पर भी ट्रम्प की मध्यस्थता की पेशकश पर बीजिंग का रुख प्रदर्शित हुआ। समाचार पत्र ने कहा कि चीन और भारत को सीमा पर मौजूदा दौर के टकरावों का हल करने के लिए अमेरिका से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसने इस बात का जिक्र किया कि दोनों देशों के नेतृत्व ने डोकलाम गतिरोध को सम्मिलित कोशिशों एवं बुद्धिमानी के साथ हल किया था। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर लद्दाख में और उत्तरी सिक्किम में कई क्षेत्रों में भारत और चीन, दोनों देशों की सेनाओं ने हाल ही में सैन्य जरूरतों के लिए निर्माण कार्य किए हैं। टकराव की दो अलग-अलग घटनाएं दो सप्ताह बाद भी दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने तथा दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने मोर्चे और अधिक मजबूत करने के स्पष्ट संकेत हैं। भारत ने कहा है कि चीनी सेना एलएसी पर लद्दाख और सिक्किम में उसके सैनिकों की सामान्य गश्त में अड़चन डाल रही है। भारत ने चीन की इस दलील को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है कि भारतीय बलों द्वारा चीन की सीमा में अतिक्रमण से दोनों सेनाओं के बीच तनाव बढ़ा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सभी गतिविधियां सीमा के इसी ओर की गई हैं और भारत ने सीमा प्रबंधन के संबंध में हमेशा बहुत ही जिम्मेदाराना रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत अपनी सम्प्रभुता और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को कहा था कि भारत एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय सैनिक सीमा प्रबंधन को लेकर बहुत जिम्मेदार रुख अपनाते हैं। उन्होंने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में कहा, दोनों पक्षों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकने वाली स्थितियों का वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तरों पर तंत्र स्थापित किए हैं और इन माध्यमों से चर्चा होती रहती है। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद है और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है, जबकि भारत का स्पष्ट रूप से कहना रहा है कि यह इसका अभिन्न हिस्सा है।

छत्तीसगढ़ के...

भर्ती कराया गया था। तब से उनकी हालत नाजुक थी। उन्होंने बताया कि आज दोपहर बाद उन्हें लगभग डेढ़ बजे दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो सके। जोगी परिवार के सदस्यों के अनुसार अजीत जोगी नौ मई को सुबह व्हीलचेयर पर गार्डन में घूम रहे थे और उसी दौरान वह अचानक बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती किए जाने के बाद से उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई। जोगी के परिवार में उनकी पत्नी कोटा क्षेत्र की विधायक रेणु जोगी तथा पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी हैं। जोगी परिवार के सदस्यों ने बताया कि जोगी के पार्थिव शरीर को शनिवार सुबह नौ बजे रायपुर स्थित उनके निवास स्थान सागौन बंगले से बिलासपुर के निवास स्थान मारवाही सदन ले जाया जाएगा। यहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद बिलासपुर जिले के ही कोटा, रतनपुर होते हुए उन्हें उनके पैतृक स्थान ले जाया जाएगा। जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद अमित जोगी ने ट्वीट कर कहा है कि 20 वर्षीय युवा छत्तीसगढ़ राज्य के सिर से आज उसके पिता का साया उठ गया। केवल मैंने ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ ने नेता नहीं, अपना पिता खोया है। माननीय अजीत जोगी जी ढाई करोड़ लोगों के अपने परिवार को छोड़ कर ईश्वर के पास चले गए। गांव-गरीब का सहारा, छत्तीसगढ़ का दुलारा हमसे बहुत दूर चला गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए अजीत जोगी वर्तमान में मारवाही विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी पत्नी रेणु जोगी कोटा क्षेत्र से विधायक हैं। जोगी वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद यहां के पहले मुख्यमंत्री बने तथा वर्ष 2003 तक इस पद पर रहे। राज्य में वर्ष 2003 में हुए विधानसभा के पहले चुनाव में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से पराजित हो गई थी। राज्य में कांग्रेस नेताओं से मतभेद के चलते जोगी ने वर्ष 2016 में नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का गठन कर लिया था और वह उसके प्रमुख थे।

कोविड-19...

रूस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार की सुबह तक एक दिन के भीतर संक्रमण के चलते देश में 175 लोगों की मौत हुई और 7,466 नए मामले सामने आए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब 24 घंटे में सात हजार से ज्यादा कोरोना केस मिले हैं। हालांकि, पिछली 22 मई से रोजाना 6 हजार से ज्यादा केस आ रहे थे। मंत्रालय ने बताया कि कुल 89,987 लोगों का इलाज चल रहा है जबकि 71,105 बीमार ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने के बाद एक मरीज विदेश भी जा चुका है। रिकवरी रेट की जानकारी देते एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक 42.89 फीसदी कोरोना मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, 29 मई की सुबह 9 बजे तक 34,83,838 नमूनों और पिछले 24 घंटे में 1,21,702 नमूनों की जांच की गई है। देश में मौत के कुल 4,706 मामलों में सर्वाधिक महाराष्ट्र (1,982) से सामने आए हैं और 960 की संख्या के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 321, दिल्ली 398, पश्चिम बंगाल 295 , उत्तर प्रदेश 197, राजस्थान 180, तमिलनाडु 145, तेलंगाना 67 और आंध्र प्रदेश में 59 लोगों की जान गई है। इसी तरह कर्नाटक में अभी तक 47, पंजाब में 40, जम्मू कश्मीर में 27, हरियाणा में 19, बिहार में 15, ओडिशा में 5, झारखंड-उत्तराखंड-असम और चंडीगढ़ में 4-4 जबकि मेघालय में एक मरीज की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट में यह कहा गया है कि मौत के 70 फीसदी से ज्यादा मामलों में मरीजों को अन्य बीमारियां थीं। पिछले 24 घंटे के दौरान सामने आए मौत के 175 मामलों में सर्वाधिक 85 महाराष्ट्र में, 22 गुजरात, 15 उत्तर प्रदेश, 13 दिल्ली, 12 तमिलनाडु, 8 मध्य प्रदेश, 7 राजस्थान, 6 पश्चिम बंगाल, 4 तेलंगाना और जम्मू कश्मीर-आंध्र प्रदेश और हरियाणा में एक-एक पाए गए हैं। सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमितों की संख्या के क्रम में भी 59,546 के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे बना हुआ है।

संभल के...

में सो रहे दोनों साधुओं पर धारदार हथियार से वार कर घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। दोनों साधु शिव मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करते थे। देर रात मंदिर परिसर में ही दोनों साधुओं की हत्या कर दी गई थी। मंदिर में साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले थे। पुलिस मामले में एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया था।

आर्थिक सेहत...

हुई थी। हालांकि, कृषि क्षेत्र का जीवीए चौथी तिमाही में बढ़कर 5.9 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो एक साल पहले समान तिमाही में 1.6 प्रतिशत था। निर्माण क्षेत्र का जीवीए चौथी तिमाही में 2.2 प्रतिशत घटा, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में यह 6 प्रतिशत बढ़ा था। वहीं खनन क्षेत्र की वृद्धि दर समीक्षाधीन तिमाही में 5.2 प्रतिशत रही, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में इसमें 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। आंकड़ों के अनुसार चौथी तिमाही में बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य सार्वजनिक सेवाओं की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 5.5 प्रतिशत रही थी। इसी तरह व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में चौथी तिमाही में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि एक साल पहले समान तिमाही में इन क्षेत्र की वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रही थी। समीक्षाधीन अवधि में वित्तीय, रीयल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं की वृद्धि दर 8.7 से घटकर 2.4 प्रतिशत रही गई। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि दर में भी गिरावट आई और यह 10.1 प्रतिशत पर आ गई। एक साल पहले समान तिमाही में यह 11.6 प्रतिशत रही थी। आंकड़ों के अनुसार, चौथी तिमाही में स्थिर (2011-12) मूल्य पर जीडीपी 38.04 लाख करोड़ रुपए रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 36.90 लाख करोड़ रुपए रही थी। पूरे वित्त वर्ष 2019-20 में वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद 145.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 31 जनवरी, 2020 को जारी पहले संशोधित अनुमान में इसके 139.81 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। मौजूदा मूल्य पर बीते वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय ।,34,226 रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। यह इससे पिछले वित्त वर्ष के ।,26,521 करोड़ रुपए के आंकड़े से 6.1 प्रतिशत अधिक है। इस बीच, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अलग आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते अप्रैल में आठ बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 38.1 प्रतिशत घटा है।

दिल्ली-एनसीआर...

महसूस किए गए। इससे पहले 12 और 13 अप्रैल को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा 10ए 15 और 29 मई को धरती कांपी है। 12 अप्रैल को भूकंप की तीव्रता 3੦5 थीए जबकि 13 अप्रैल को रिक्टर पैमाने पर इसे 2੦7 दर्ज किया गया था। इससे पहले जितने भी बार भूकंप आए थे उनकी तीव्रत चार से कम थी। बता दें कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली सिस्मिक जान चार में आती है।

कोरोना का कहर : 124 वर्षों में पहली बार रद्द की गई बोस्टन मैराथन

न्यूयार्क। कोरोना वायरस के कारण बोस्टन मैराथन को पिछले 124 वर्षों के इतिहास में पहली बार रद्द कर दिया गया है। बोस्टन के मेयर मार्टी वाल्श ने कहा कि यह मशहूर मैराथन स्वास्थ्य कारणों के कारण 14 सितंबर को भी आयोजित नही की जाएगी। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसका आयोजन अप्रैल में होना था लेकिन इसे सितंबर तक स्थगित कर दिया गया था।

ओलंपिक चैंपियन रूडिशा टखने में चोट के कारण 16 सप्ताह के लिए बाहर

नैरोबी। दो बार के ओलंपिक चैंपियन और 800 मीटर में विश्व रिकार्ड धारक धावक डेविड रूडिशा बाएं टखने में फ्रैक्चर के कारण अगले 16 सप्ताह तक ट्रैक से बाहर रहेंगे। यह 31 वर्षीय एथलीट पश्चिमी कीनिया स्थित किलगोरिस में 19 मई को चोटिल हो गया था। उनके बाएं टखने में मोच आ गई थी और चिकित्सकों ने कहा जांच की से पता चला है कि उसमें फ्रैक्चर है।

पैन पैसेफिक तैराकी चैंपियनशिप अब 2022 के बजाय 2026 में होगी

लास एंजिलिस। कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में हुए बदलावों को देखते हुए 2022 में होने वाली पैन पैसेफिक तैराकी चैंपियनशिप को अब 2026 तक टाल दिया गया है। पैन पैक चार्टर के चार देशों में से एक कनाडा अब भी इसकी मेजबानी करेगा। इन देशों में उसके अलावा आस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। ओलंपिक स्थगित होने के कारण अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर काफी व्यस्त हो गया है क्योंकि 2022 में इंग्लैड के बर्मिंघम में 27 जुलाई से सात अगस्त के बीच राष्ट्रमंडल खेल होने है जबकि विश्व तैराकी महासंघ (फिना) ने जापान के फुकुओका में 2021 में होने वाली विश्व चैंपियनशिप को 2022 तक स्थगित कर दिया है।

विश्व जूनियर चैम्पियनशिप अगले साल जनवरी में होगी

नई दिल्ली। बैडमिंटन विश्व जूनियर चैम्पियनशिप के कार्यक्रम मे शुक्रवार को बदलाव किया गया और कोविड -19 महामारी के कारण बाधित हुए अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर में अब इसका आयोजन अगले साल जनवरी में किया जाएगा। बैडमिंटन विश्व महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने पुष्टि की कि विश्व जूनियर चैम्पियनशिप अब अगले साल 18 से 24 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।

ब्रिटिश ओर आस्ट्रेलियाई ग्रां प्री रद्द

लंदन। कोरोना वायरस के कारण शुक्रवार को ब्रिटिश और आस्ट्रेलियाई मोटो ग्रां प्री को रद्द कर दिया गया। ब्रिटिश रेस सिल्वरस्टोन मे 28 से 30 अगस्त के बीच जबकि आस्ट्रेलियाई ग्रां प्री फिलिप आइलैंड में 23 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जानी थी।

केवल एक स्थान पर हो सकती है भारत और आस्ट्रेलिया की टेस्ट श्रृंखला

कार्यक्रम में बदलाव की संभावना : सीए

भाषा। मेलबर्न

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने कोविड-19 परिस्थितियों को देखते हुए भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के कार्यक्रम में बदलाव की संभावना से इन्कार नहीं किया है और यहां तक उसने केवल एक स्थान पर मैचों के आयोजन के विकल्प को भी खुला रखा है।
क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने गुरुवार को घोषणा की थी भारत के खिलाफ टेस्ट मैच क्रमशः ब्रिस्बेन (3-7 दिसंबर), एडिलेड (11-15 दिसंबर), मेलबर्न (26-30 दिसंबर) और सिडनी (3-7 जनवरी) में खेले जाएंगे। हालांकि क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन राबर्ट्स ने कहा कि स्वास्थ्य संकट को देखते हुए यात्रा पाबंदियों के कारण कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है। उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा, वर्तमान कार्यक्रम यह मानकर तैयार किया गया कि उस समय प्रांतीय सीमाएं यात्रा के लिए खुली रहेंगी। यह उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है और हो सकता है कि हमें इनका आयोजन एक या दो स्थानों पर ही करना पड़े। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। कई तरह के विकल्प हैं। हमारे पास चार प्रांतों के चार स्थान है या फिर हम केवल एक प्रांत के एक स्थान पर इसका आयोजन कर सकते हैं। अभी अनगिनत संभावनाएं हैं। भारतीय श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित होने के तुरंत बाद पश्चिम आस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ की प्रमुख क्रिस्टीना मैथ्यूज ने इस महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला के लिए पर्थ के बजाय ब्रिस्बेन को प्राथमिकता देने की आलोचना की थी। राबर्ट्स ने कहा कि भारतीय टीम दो साल पहले जब आस्ट्रेलियाई दौरे पर आई थी तब गाबा को टेस्ट मैच नहीं मिला और संतुलन बनाने के लिए इस बार पर्थ को नजरअंदाज किया गया। अगर पर्थ को इस साल भारत के खिलाफ टेस्ट मेजबानी मिल जाती तो इसका मतलब होता कि पर्थ आठ साल के चक्र में इंग्लैंड के खिलाफ दो और भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगा जबकि ब्रिस्बेन के खाते में केवल दो टेस्ट ही जाते। इससे भविष्य के दौरा कार्यक्रम में असंतुलन पैदा होता है। भारतीय टेस्ट मैच ब्रिस्बेन को सौंपने का मतलब अधिक संतुलन पैदा करना है। इससे आठ साल के चक्र में पर्थ को भारत और इंग्लैंड के खिलाफ तीन और ब्रिस्बेन को भी इतने की टेस्ट मैचों की मेजबानी मिल रही हैं। राबर्टस ने इसके साथ ही कहा कि अगर टी20 विश्व कप आयोजन नहीं होता है तो देश के क्रिकेट बोर्ड को आठ करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का नुकसान होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने टी20 विश्व कप पर फैसला दस जून तक टाल दिया। उसने कहा कि उसे आपात योजनाओं पर काम करने के लिए कुछ और समय चाहिए। यहां तक कि अगर टूर्नामेंट होता भी है तो इसे खाली स्टेडियमों में आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे क्रिकेट आस्ट्रेलिया को लगभग पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का राजस्व मिलता है। टी20 विश्व कप पर सवालिया निशान लगा हुआ है जिससे क्रिकेट आस्ट्रेलिया को लगभग दो करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमें इस सत्र में मैचों के आयोजन के लिए जैव सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ेंगे जिसमें एक करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर की लागत आएगी।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने माना टी20 विश्व कप का भाग्य अनिश्चित

मेलबर्न। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के कारण आस्ट्रेलिया में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप का भाग्य अनिश्चित बना हुआ है जिससे उनकी संस्था को राजस्व का काफी नुकसान हो सकता है। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन राबर्ट्स ने माना कि इस प्रतियोगिता के आयोजन के साथ जोखिम भी जुड़े है। हम सभी आशान्वित रहे है कि अक्टूबर-नवंबर में इसका आयोजन किया जा सकता है लेकिन आपको यह समझना होगा कि ऐसी संभावना से जोखिम भी जुड़े है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इस प्रतियोगिता पर फैसला दस जून तक टाल दिया। उसने कहा कि उसे आपात योजनाओं पर काम करने के लिए कुछ और समय चाहिए। राबर्ट्स ने कहा कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया को इससे आठ करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का नुकसान हो सकता है। यहां तक कि अगर टूर्नामेंट होता भी है तो इसे खाली स्टेडियमों में आयोजित किए जाने की संभावना है। इससे क्रिकेट आस्ट्रेलिया को लगभग पांच करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का राजस्व मिलता है। टी20 विश्व कप पर सवालिया निशान लगा हुआ है जिससे क्रिकेट आस्ट्रेलिया को लगभग दो करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमें इस सत्र में मैचों के आयोजन के लिए जैव सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ेंगे जिसमें एक करोड़ आस्ट्रेलियाई डालर की लागत आएगी। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के प्रमुख हालांकि भारत के खिलाफ तीन दिसंबर से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला के प्रति अधिक आशान्वित है। पूर्व कार्यक्रम के अनुसार भारत के खिलाफ श्रृंखला चार स्थानों ब्रिस्बेन, एडिलेड, सिडनी और मेलबर्न में खेली जाएगी लेकिन राबर्टस ने कहा कि इसक कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान कार्यक्रम यह मानकर तैयार किया गया कि उस समय प्रांतीय सीमाएं यात्रा के लिए खुली रहेंगी।

लॉकडाउन में मानसिक तौर पर मजबूत रहना जरूरी: नारंग

नई दिल्ली। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को कहा कि खिलाड़ियों को इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक तौर पर शांत और एकाग्र रहना होगा। लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता नारंग ने खेल मंत्री किरेन रीजीजू के साथ फिटनेसउ जीवन का तरीका विषय पर ऑनलाइन चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर बात की। निशानेबाजी 98 प्रतिशत मानसिक, 2 प्रतिशत शारीरिक खेल है। इस लॉकडाउन परिदृश्य में मानसिक रूप से फिट होना काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप मानसिक रूप से फिट नहीं है तो यह आपके खेल पर दिखता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ राइफल निशानेबाजों में से एक 37 साल के इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, शारीरिक और मानसिक फिटनेस एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं, तो आपको सही विचार नहीं आएगा। पिछले कुछ वर्षों में यह खेल और भी मुश्किल हुआ है।

मैथ्यूज की 2011 विश्व कप फाइनल में अनुपस्थिति भारी पड़ी थी : संगकारा

कोलकाता। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा का मानना है कि भारत के खिलाफ 2011 विश्व कप फाइनल में एंजेलो मैथ्यूज का चोट के कारण बाहर होना उनकी टीम को काफी महंगा पड़ा था। मेजबान भारत ने तब 28 साल बाद खिताब जीता था। न्यूजीलैंड के खिलाफ रोमांचक सेमीफाइनल में अहम भूमिका निभाने वाले मैथ्यूज को मांसपेशियों में खिंचाव के कारण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल से बाहर होना पड़ा था। भारत के हाथों छह विकेट से हार के बारे में श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने कहा कि मैथ्यूज की चोट के कारण उन्हें 6-5 का संयोजन अपनाना पड़ा और यही वजह थी कि उन्हें टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करना पड़ा। संगकारा ने भारतीय आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत में कहा, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो उस विश्व कप फाइनल में मुझे यही सबसे बड़ी बात नजर आती है। आप कैच छोड़ना और ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन यह टीम का संयोजन था और हमें महत्वपूर्ण मैच में हमें बदलाव करने को मजबूर होना पड़ा।

रोहित की दबाव झेलने की क्षमता ने उसे सबसे सफल आईपीएल कप्तान बनाया : लक्ष्मण

भाषा। नई दिल्ली

अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि रोहित शर्मा का इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कप्तान के तौर सफलता का सबसे बड़ा कारण दबाव की परिस्थितियों में भी शांत चित बने रहना है। मुंबई इंडियन्स के 33 वर्षीय कप्तान रोहित ने अब तक आईपीएल में चार खिताब जीते है जो चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से एक खिताब अधिक है। इससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। लक्ष्मण ने याद किया कि डेक्कन चार्जर्स की तरफ से पहले आईपीएल में खेलते हुए रोहित एक बल्लेबाज और नेतृत्वकर्ता के रूप में कैसे बेहतर बना। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट कनेक्टेड में कहा, वह डेक्कन चार्जर्स की टीम में रहते हुए ही नेतृत्वकर्ता बन गया था। जब वह पहले साल आया तो काफी युवा था और तब वह टी20 विश्व कप में ही खेला था और उसे भारत की तरफ से पदार्पण किए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। हमारी टीम आईपीएल के पहले सत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी लेकिन रोहित ने बेहतरीन खेल दिखाया था। उसने जिस तरह से मध्यक्रम में दबाव में बल्लेबाजी की वह शानदार था। रोहित आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक 188 मैचों में 31.60 की औसत से 4898 रन बनाए हैं जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 109 रन है। प्रत्एक मैच और हर एक सफलता के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह कोर ग्रुप में शामिल हो गया। वह युवाओं की मदद करता और अपने विचार रखता। यह उसकी नेतृत्वक्षमता के शुरुआती लक्षण थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दबाव की परिस्थितियों से पार पाना था क्योंकि इस तरह की मुश्किल परिस्थितियों में बल्लेबाजी करके उसने साबित किया था और वह निरंतर बेहतर बनता रहा।

जून में होगी प्रीमियर लीग की वापसी, लिवरपूल का चैंपियन बनना तय

लंदन। कोरोना वायरस के कारण तीन महीने तक ठप्प रहने के बाद प्रीमियर लीग फुटबाल की 17 जून को वापसी होना तय है जिससे लिवरपूल के चैंपियन बनने का रास्ता साफ होगा और साथ ही यूरोपीय चैंपियनशिप में खेलने वाली टीमो का भी निर्धारण हो जाएगा। लिवरपूल का 30 वर्ष मे पहली बार चैंपियन बनना तय है, लेकिन जब खाली स्टेडियमों में मैच होंगे तो कई अन्य मसले भी सुलझ जाएंगे जिनमें दूसरी श्रेणी मे जाने वाली टीमों और अगले साल यूरोपीय चैंपियनशिप में जगह बनाने वाली टीमो का निर्धारण भी शामिल है।

लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर चार साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली। पिछले साल भारतीयो मे टाटा स्टील कोलकाता 25के जीतने वाली लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर विश्व एथलेटिक्स डोपिंग निरोधक एजेंसी ने प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में चार साल का प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय डोप जांच लेबोरेटरी पर विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने निलंबन लगा रखा है। इसी वजह से कौर के नमूने दोहा मे वाडा की अधिकृत लैब में भेजे गए थे। 32 वर्ष की कौर से टाटा स्टील कोलकाता 25के का शीर्ष पुरस्कार भी छीन लिया जाएगा। उनके प्रतिबंध की अवधि 15 दिसंबर से शुरू हो गई है जिस दिन उनके नमूने लिए गए थे।

अध्यक्ष या महासचिव की सहमति के बिना खर्च करने का अधिकार नहीं : खन्ना

भाषा। नई दिल्ली

तोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए होटल बुकिंग में देरी के कारण हुए नुकसान के मुद्दे पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के वित्त समिति (एफसी) के अध्यक्ष अनिल खन्ना ने शुक्रवार को अपना बचाव करते हुए कहा कि अध्यक्ष या महासचिव की मंजूरी के बिना एफसी को एक रुपए खर्च करने का भी अधिकार नहीं है। आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने 15 दोहरे कमरों की बुकिंग की स्वीकृति में विलंब पर सवाल उठाते हुए गुरुवार को खन्ना से तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। बत्रा ने बताया कि इस देरी के कारण आईओए को लगभग 73 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ए बुकिंग 18 रात के लिए थी। कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे के माध्यम से भेजे गए पत्र के जवाब में खन्ना ने कहा कि एफसी ने इस मामले पर जून 2019 में एक बैठक की थी, लेकिन इसने बुकिंग को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई प्रशासनिक मंजूरी नहीं थी। खन्ना ने अपने पत्र में लिखा, तोक्यो के होटल खर्चों के संबंध में मैंने इसकी पुष्टि की है कि एफसी को जून 2019 में भुगतान करने के लिए सूचना दी गई थी। एफसी ने 15 जून को बताया कि किसी भी भुगतान से पहले फाइल पर अध्यक्ष और महासचिव की प्रशासनिक स्वीकृति की जरूरत होती है जो नहीं मिला था। एफसी ने सही फैसला किया था। अब मैं वित्त विभाग से इस मामले के बारे में पूछ रहा हूं कि आईओए कार्यालय ने क्या कार्वाई की। प्रशासनिक चूक कैसे और कहां हुई। तोक्यो ओलंपिक खेल इसी साल जुलाई-अगस्त में होने थी लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इन्हें अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया। खन्ना का यह बचाव बत्रा और महासचिव राजीव मेहता के बीच बढ़ती तकरार के दौरान आया है।

ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड के 55 खिलाड़ियों के दल में नहीं हेल्स और प्लंकेट

लंदन। इंग्लैंड ने शुक्रवार को 55 खिलाड़ियों के ट्रेनिंग ग्रुप की घोषणा की जिसमें एलेक्स हेल्स और विश्व कप विजेता लियाम प्लंकेट को शामिल नहीं किया गया है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस के कारण घरेलू सत्र शुरू होने में विलंब हुआ और यह कम से कम जुलाई तक शुरू नहीं होगा। टीम को वेस्टइंडीज, पाकिस्तान, आयरलैंड और आस्ट्रेलिया के खिलाफ पूर्ण टेस्ट और सीमित ओवर की श्रृंखलाएं खेलनी हैं जिसकी तैयारी के लिए उसने इस ग्रुप में 14 अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी चुना है। डेविड विली को भी इसमें दल में शामिल किया गया है जो विश्व कप से पहले जोफ्रा आर्चर को वनडे टीम में स्थान गंवा बैठे थे जिसके बाद इंग्लैंड ने पिछले साल पहली बार विश्व कप अपने नाम किया था। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट दर्शकों की अनुपस्थिति में बंद स्टेडियम में जैविक रूप से सुरक्षित स्टेडियमों में खेले जाएंगे। यह ग्रुप एक स्थल पर ट्रेनिंग नहीं करेगा बल्कि कई काउंटी स्थलों पर व्यक्तिगत सत्र कराए जाएंगे जैसा पिछले हफ्ते गेंदबाजों के साथ नेट में अभ्यास शुरू किया गया था।

सीमित ओवरों के बजाय टेस्ट खेलना पसंद करूंगा : मार्क वुड

लंदन। विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे मार्क वुड ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण अगर इस सत्र में व्यस्त कार्यक्रम के बीच हर प्रारूप के लिए अलग अलग टीमों को उतारा जाता है तो वह इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा बनना पसंद करेंगे। इंग्लैंड 45 खिलाड़ियों का एक पूल तैयार कर रहा है जिनमें 18 गेंदबाजों ने पहले ही व्यक्तिगत अभ्यास शुरू कर दिया है। जल्द ही बल्लेबाज और विकेटकीपर भी अभ्यास शुरू कर देंगे। महामारी के कारण सत्र में देरी के बावजूद इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) अपने सभी अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसमें वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ तीन तीन टेस्ट तथा आस्ट्रेलिया और आयरलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखलाएं शामिल हैं।

ब्रिटेन की भारत समेत 10 देशों को मिलाकर 5जी क्लब बनाने की योजना

लंदन। ब्रिटेन की सरकार ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुआवेई को लेकर सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतों के मद्देनजर भारत समेत 10 लोकतांत्रिक देशों का 5जी क्लब बनाने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है। एक स्थानीय खबर मे इसकी जानकारी दी गई। स्थानीय अखबार दी टाइम्स की खबर के अनुसार, लोकतांत्रिक देशो के इस डी-10 क्लब में जी7 देशों ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान और कनाडा के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत शामिल होंगे। इस समूह का लक्ष्य 5जी उपकरणो के लिए वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था तैयार करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। यह कदम इस लिहाज से प्रासंगिक हो जाता है कि ब्रिटेन ने हुआवेई पर अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधो के मद्देनजर कंपनी के खिलाफ नई जांच की शुरुआत की है। अखबार ने ब्रिटेन की सरकार के एक सूत्र के हवाले से लिखा, हमें बाजार में नए भागीदारों की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमने हुआवेई के साथ आगे बढ़ने के निर्णय को रोक दिया। यूरोप की कंपनियो मे सिर्फ नोकिया और एरिक्सन ही है, जो 5जी से संबंधित उपकरणो की आपूर्ति करती है। बाजार विशेषज्ञो का मानना है कि ए दोनो कंपनियां हुआवेई की तरह 5जी उपकरणो की जल्दी आपूर्ति करने में सक्षम नही है। हालांकि ब्रिटेन ने हुआवेई को उच्च-जोखिम वालो विक्रेता करार दिया है।

भारत, अमेरिका आने वाले दिनों में कर सकते हैं छोटा व्यापार समझौता: भारतीय राजदूत

वाशिंगटन। अमेरिका मे भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधु ने कहा है कि भारत और अमेरिका आने वाले दिनो में एक अपेक्षाकृत छोटा व्यापार समझौता कर सकते है। उन्होने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जो चुनौतियां बनी है, उससे प्रति बाधित हुई है क्योकि सरकारो का ध्यान स्वास्थ्य संकट से निपटने पर है। अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के वेस्ट कोस्ट समिट को वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए संबोधित करते हुए संधु ने कहा कि भारत द्वारा मलेरिया के इलाज मे उपयोगी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) की अमेरिका को आपूर्ति से दोनो देशो मे परस्पर भरोसा काफी बढ़ा है। भारत इस दवा का सबसे बड़ा विनिर्माता है और उसे अमेरिका को बड़ी मात्रा मे मानवीय आधार पर एचसीक्यू दवाएं भेजी हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर मॉल में दकानें खोलने पर जल्द होगा निर्णय

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देश पर गौर करने के बाद मॉल में दुकानें खोले जाने के बारे मे निर्णय जल्द लिया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ व्यापार संगठनो के प्रतिनिधियो की वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए बृहस्पतिवार को हुई बैठक मे खुदरा कारोबारी के मुद्दो पर चर्चा की गई। दिशानिर्देशो मे छूट के बाद भी खुदरा कारोबारियो को हो रही कठिनाइयो के संदर्भ मे उन्होने कहा कि जरूरी और गैर-जरूरी वस्तुओं का अंतर किए बिना ज्यादातर दुकानो को खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशो पर विचार करने के बाद मॉल के अंदर अन्य दुकानो को खोलने के बारे में जल्दी निर्णय किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस संकट से पार पाने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की कर्ज गारंटी की घोषणा की है। इसमें व्यापारी भी शामिल है। गोयल ने व्यापारियो से कहा कि उन्हें ई-वाणिज्य कंपनियो से घबराने की जरूरत नही है क्योकि आम लोगो को यह समझ आ गया है कि पड़ोस की खुदरा दुकानो से ही संकट के समय उन्हे मदद मिली है। सरकार खुदरा कारोबारियो के लिए कंपनियो के बीच (बी2बी) व्यापार को सुगम बनाने के लिए व्यवस्था पर काम कर रही है और उनका दायरा बढ़ाने के लिए तकनीकी मदद उपलब्ध करा रही है।

गैर-जरूरी वस्तुओं पर कर न बढ़ाने के पक्ष में वित्त मंत्रालय

जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने

भाषा। नई दिल्ली

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की बैठक अगले महीने होना है। कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते कर संग्रह घटने के बावजूद वित्त मंत्रालय गैर-जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी कर की दर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों ने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं पर यदि जीएसटी की दर बढ़ाई जाती है तो यह उनकी मांग को कम करेगा। अंततः इससे अर्थव्यवस्था के फिर पटरी पर लौटने की रफ्तार कम होगी। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को हर मोर्चे पर बेहतर करना होगा। इसके लिए अनिवार्य वस्तुओं के अलावा भी मांग बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि जीएसटी की दर बढ़ाने पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद करेगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं। देश के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने के लिए यह शीर्ष इकाई है। जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक मार्च में हुई थी। तब कई वस्तुओं पर जीएसटी कर की दर कम की गई थी। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। इसके चलते सरकार के जीएसटी संग्रह में कमी आई है। सरकार ने अप्रैल के जीएसटी संग्रह आंकड़े फिलहाल जारी नहीं किए हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी राजकोषीय घाट को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है सूत्रों ने कहा कि कोविड19 महामारी क्या रूप लेने जा रही है, इसका अर्थव्यवस्था पर आगे उसका क्या असर होगा अभी यह कोई नहीं जानता।

मंत्रियों, नीति निर्माताओं ने निवेश बढ़ाने को लेकर वैश्विक निवेशकों के साथ की परिचर्चा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी इनवेस्ट इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकारो के नीति निर्माताओ के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाकर वैश्विक निवेशकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से एक सेमिनार का आयोजन किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बयान के अनुसार परिचर्चा में एप्पल, हेवलेट पैकर्ड, इंटेल, सैमसंग और एलजी जैसी कंपनयां शामिल हुई है। ठेके पर विनिर्माण और एसेंबल का काम करने वाली फॉक्सकॉन, जाबिल और फ्लेक्स जैसी कंपनियो के प्रतिनिधि भी इसमे शामिल हुई। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात के मंत्रियो और वरिष्ठ अधिकारियो ने निवेश के विभिन्न अवसरो और निवेशकों के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के बारे मे जानकारी दी। कार्यक्रम मे करीब 18 देशो से 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग कर लैंड बैंक पोर्टल शुरू किया है। साथ ही विनिर्माताओ को विभिन्न प्रोत्साहन और वित्तीय मदद देने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक नीति बनाई है। महाराष्ट्र के उद्योग, खनन और मराठी भाषा मामलो के मंत्री सुभाष देसाई ने निवेशकों को राज्य मे निवेश का निमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य मे एकल मंजूरी व्यवस्था है और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियो के लिए अनुकूल नीति है। बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव (आईटी और इलेक्ट्रॉनिक) आलोक कुमार ने कहा कि निवेशकों के लिए करीब 20,000 एकड़ जमीन के साथ सरकार और निजी इकाइयों की 5-6 लाख वर्ग मीटर बिल्कुल तैयार सुविधाएं किराए पर उपलब्ध है।

पेट्रोल, सीएनजी की होम डिलिवरी शुरू करने की तैयारी में है सरकार

नई दिल्ली। सरकार उपभोक्ताओ की सुविधा के लिए डीजल के बाद अब पेट्रोल और सीएनजी जैसे ईंधनो की होम डिलिवरी शुरू करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होने कहा कि सरकार सभी प्रकार के ईंधनो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी (संपीड़ित प्राकृतिक गैस), एलएनजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) और एलपीजी (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी रसोई गैस) के लिए खुदरा बिक्री का नया स्वरूप सामने लाने पर विचार कर रही है। इन नए स्वरूप मे ए सारे ईंधन एक ही जगह बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। देश की सबसे बड़ी खुदरा ईंधन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प (आईओसी) ने सितंबर 2018 मे एक मोबाइल डिस्पेंसर के माध्यम से डीजल की होम डिलिवरी शुरू की। हालांकि यह सेवा अभी केवल कुछ चुनिंदा शहरों मे ही उपलब्ध है।

सार्वजनिक सूचना

इस विज्ञापन के माध्यम से यह सूचित किया जाता है मेरे मुवक्किल श्री हरसहाय भेरवाल पुत्र स्व. श्री रामहेत भेरवाल और श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री हरसहाय भेरवाल निवास 9/324-बी, हर्ष निवास, ललिता पार्क लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092, अपनी पिछली सूचना को वापस ले रहे हैं / रद्द कर रहे हैं और अपने पुत्र श्री सोनू भेरवाल को अपनी चल या अचल संपत्ति से बेदखल / रोकने के संबध में दिनांक 02 अक्टूबर 2012 विराट वैभव समाचार पत्र में प्रकाशित अपनी पिछली सूचना को वापस ले रहे हैं / रद्द कर रहे है और अब उनके इस पुत्र श्री सोनू भेरवाल का अभी से अपने सभी भाईयों के बराबर ही उनके सभी चल या अचल संपत्ति में समान अधिकार होगा ।

कमाल सक्सेना (एडवोकेट)
चैम्बर नंबर 422, वेस्टर्न विंग
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली -110054

मद्रास उच्च न्यायालय ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन एमएफ, सेबी को नोटिस दिया: निवेशक समूह

नई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निवेशक समूह की याचिका पर संकटग्रस्त फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड और सेबी को नोटिस जारी किया है। निवेशक समूह के बयान के मुताबिक फंड हाउस द्वारा छह योजनाओं को बंद करने और इसके चलते निवेशकों के करीब 28,000 करोड़ रुपए सुरक्षित करने के संबंध मे यह नोटिस दिया गया है। निवेशक समूह के बयान मे यह भी कहा गया कि सभी प्रभावित निवेशकों को एक साथ लाने के लिए अलग से एक ऑनलाइन याचिका शुरू की जा रही है और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय और फंड हाउस के अमेरिकी अभिभावक और अमेरिकी बाजारों के नियामक एसईसी को भेजा जाएगा। बयान में कहा गया कि म्यूचुअल फंड और कोष प्रबंधकों को निवेश के संबंध मे निर्णय लेने के तरीकों, विनियामक और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने के बारे मे सवालों के जवाब देने चाहिए।

शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 224 अंक चढ़ा

भाषा। मुंबई

शेयर बाजारों में बढ़त का सिलसिला शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी तथा वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के बावजूद एफएमसीजी, वित्तीय और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों में बढ़त से बाजार में तेजी आई। निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सप्ताह देश में लॉकडाउन नियमों में और ढील दी जाएगी। हालांकि, वे चौथी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के आंकड़ों से पहले सतर्क बने हुए थे। आंकड़े बाजार बंद होने के बाद जारी किए गए जिसके अनुसार पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही जनवरी-मार्च में जीडीपी वृद्धि दर मात्र तीन दशमलव एक प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष की वृद्धि चार दशमलव दो प्रतिशत रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 223.51 अंक या 0.69 प्रतिशत की बढ़त के साथ 32,424.10 पर पहुंच गया।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, परियोजना मण्डल क्र.-02 कांकेर, ठा. पुष्कर सिंह मार्ग, संजय नगर कांकेर जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

फोन नं. : 07868-223480   ई-मेल: sejdp2@gmail.com

क्रमांक/233/तक 1731/मुमंग्रागौपयो/छग ग्रासविअ/2020 कांकेर, दिनांक 27/05/2020

संक्षिप्त मैनुअल निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में ''डी'' एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत स्वीकृत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा दिनांक 22.02.2018 से लागू दर अनुसूची पर द्वितीय बार मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

(राशि लाख में एवं लंबाई मीटर में)

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	लंबाई (मी.मं.)	अनुमानित लागत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नारायणपुर	नारायणपुर	खैराभाट	खड़कागांव	सी.सी. सड़क सह नाली निर्माण आश्रित ग्राम खैराभाट के स्कुलपारा से बांधपारा तक	400.00	38.02

उपरोक्त निर्माण कार्यों हेतु निविदा संबंधी शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा हेतु निधारित समय-सारणी निम्नानुसार है:-

1. निविदा प्रपत्र विक्रय करने की निर्धारित तिथि : दिनांक 01.06.2020 प्रातः 10.30 बजे से दिनांक 08.06.2020 संध्या 05:30 बजे तक
2. पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : दिनांक 11.06.2020 संध्या 05:30 बजे तक

(मुकेश संतोषी)
अधीक्षण अभियंता,
छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण,
परियोजना मण्डल क्र.-02 कांकेर, जिला-उ.ब.कांकेर

संवाद-25506/5

ट्रंप ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों पर साधा निशाना

● शासकाय आदेश पर किए दस्तखत

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं द्वारा डाली गई सामग्री पर मिले कानूनी संरक्षण को समाप्त करने के उद्देश्य से एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं।

एक दिन पहले ही ट्रंप ने ट्विटर पर चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। ट्विटर ने ट्रंप के दो ट्वीट के साथ फैक्ट-चेक लिंक जोड़ दिए थे। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को शासकीय आदेश पर दस्तखत करने के बाद संवाददाताओं से कहा, आज मैं अमेरिकी लोगों के स्वतंत्रता से बोलने के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक शासकीय आदेश पर दस्तखत कर रहा हूं। इस समय ट्विटर जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को इस सिद्धांत के आधार पर जवाबदेही से अभूतपूर्व संरक्षण मिल जाता है कि वे तटस्थ मंच हैं और वे एक नजरिए के साथ संपादन का कार्य कर रहे हैं।

संचार शिष्टता कानून की धारा 230 के तहत शासकीय आदेश में नए नियमों का प्रावधान किया गया है जिससे सेंसर करने या किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने वाली सोशल मीडिया कंपनियां उत्तरदायित्व से छूट नहीं पा सकेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यह बड़ी बात है। उनके पास एक कवच है, वे जो चाहें कर सकती हैं। अब उनके पास यह कवच नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि शासकीय आदेश में संघीय व्यापार आयोग को इन सोशल मीडिया कंपनियों को धोखेबाजी का कोई काम नहीं करने देने या वाणिज्य को प्रभावित करने वाले काम नहीं करने देने का निर्देश भी दिया गया है।

बढ़ा विवाद: चीन के स्नातक स्तर के छात्रों को निकाल सकता है अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका और चीन के संबंधों में तनाव का असर अमेरिकी विश्वविद्यालयों से स्नातक कर रहे उन हजारों चीनी छात्रों पर पड़ सकता है जिन्हें ट्रंप प्रशासन जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा सकता है। अमेरिका चीन के अधिकारियों पर नई पाबंदियां भी लगा सकता है। गौतलब है कि व्यापार, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, मानवाधिकार और हांगकांग के दर्जे को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह चीन के बारे में शुक्रवार को घोषणा करेंगे। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि वह चीन के खुफिया विभाग या पीपल्स लिबरेशन आमी से संबद्ध चीन के शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े छात्रों के वीजा रद्द करने के महीनों पुराने प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप चीन के अधिकारियों पर यात्रा एवं वित्तीय पाबंदियां लगाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा था, चीन के बारे में हम क्या कर रहे हैं यह घोषणा हम कल करेंगे। हम चीन से खुश नहीं हैं। वीजा रद्द करने के प्रस्ताव का अमेरिकी विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संगठनों ने विरोध किया है। इस बारे में अधिकारियों का कहना है कि कोई भी पाबंदी इस तरह से लगाई जाएगी जिससे कि केवल वे छात्र प्रभावित हों जो जासूसी या बौद्धिक संपदा की चोरी जैसा खतरा पैदा कर सकते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने छात्रों को निकाला जाएगा हालांकि यह कहा कि यह देश में मौजूद चीनी छात्रों का एक छोटा सा हिस्सा होगा।

थाईलैंड में सियाम मुसुम में मास्क लगी विशालकाय नागवंक की प्रतिमा को देखता व्यक्ति

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर पार्टी से हुए बर्खास्त

भाषा। कुआलालम्पुर

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को उनकी पार्टी बरसातू से बर्खास्त कर दिया गया है। महातिर ने इस कदम को चुनौती देने का संकल्प लिया है। 94 वर्षीय महातिर को उनके बेटे और तीन अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ बृहस्पतिवार को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। राजनीतिक तनातनी के बाद महातिर ने फरवरी में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद उनकी पार्टी के सदस्य मोहिउद्दीन यासीन महातिर की आपत्ति के बावजूद प्रधानमंत्री बने। इसके बाद से पार्टी दो खेमों में बंट गई है।

महातिर के बेटे मुखरिज महातिर ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में मोहिउद्दीन को चुनौती दी है। अध्यक्ष पद के लिए होने वाला चुनाव कोरोना वायरस महामारी के कारण टल गया है। महातिर और बर्खास्त किए गए चार अन्य नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा, बरसातू अध्यक्ष ने बिना किसी वैध कारण के हमें बर्खास्त करने का एकतरफा कदम पार्टी चुनाव को लेकर अपने डर और देश के प्रशासन के इतिहास में सबसे अस्थिर प्रधानमंत्री के रूप में अपनी असुरक्षित स्थिति के कारण उठाया है।

उन्होंने कहा कि यह कदम अवैध है और वे इस कदम को चुनौती देने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कदम उठा सकते हैं कि बरसातू सत्ता के लालची लोगों का हथियार न बनने पाए। मलेशिया में सत्ता का संकट उस वक्त पैदा हुआ जब महातिर और अनवर इब्राहिम का सत्तारूढ़ पैक्ट ऑफ होप गठबंधन टूट गया। इस गठबंधन ने दो साल पहले नजीब रजाक की सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसके बाद महातिर ने इस्तीफा दे दिया जिससे प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ शुरू हुई जिसमें यासीन ने जीत हासिल की। उनके गठबंधन में देश के जातीय मलय मुस्लिम बहुसंख्यकों की संख्या अधिक है।

अमेरिका में पुलिस हिरासत में व्यक्ति की मौत पर मिनीपोलिस के बाहर भी प्रदर्शन, थाने में आगजनी

भाषा। मिनीपोलिस

अमेरिका में पुलिस हिरासत में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत को लेकर हो रहे प्रदर्शन बृहस्पतिवार को मिनीपोलिस क्षेत्र के बाहर भी पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने सेंट पॉल मार्ग पर लूटपाट और आगजनी की तथा वे उस जगह पर फिर से पहुंच गए जहां हिंसक प्रदर्शन के चलते पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने मिनीपोलिस में एक थाने को भी आग लगा दी जिसे पुलिस विभाग ने हिंसक प्रदर्शनों चलते खाली कर दिया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि बृहस्पतिवार रात 10 बजे के बाद अपने कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रेसिंक्ट थाने को खाली कर दिया गया था। प्रदर्शनकारी एक वीडियो में थाने में घुसते और इमारत को आग लगाते दिखाई देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को लेकर टिप्पणी की कि मिनीपोलिस में नेतृत्व का पूरी तरह अभाव है। उन्होंने ट्वीट किया, अभी गवर्नर टिम वाल्ज से बात की और उनसे कहा कि सेना उनके साथ है। जब लूटपाट शुरू होती है तो गोलीबारी शुरू होती है। जॉर्ज फ्लोयड नाम के हथकड़ी लगे एक अश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर श्वेत पुलिस अधिकारी द्वारा घुटना रखे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी रोष है। वीडियो में दिख रहा है कि अधिकारी कम से कम आठ मिनट तक अपने घुटने से व्यक्ति की गर्दन दबाए रखता है। इस दौरान व्यक्ति सांस रुकने की बात कहता नजर आता है। गत सोमवार को हुई घटना के वीडियो में दिखता है कि व्यक्ति का हिलना-डुलना और बोलना बंद हो जाने पर भी पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन अपना घुटना नहीं हटाता। यह वीडियो एक राहगीर ने बनाया था।

फ्लोयड की मौत के बाद लगातार तीसरी रात भी हिंसक प्रदर्शन हुए। ट्विन सिटीज क्षेत्र में दर्जनों कारोबारी प्रतिष्ठानों ने लूटपाट से बचने के लिए बृहस्पतिवार को अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखे। अमेरिकी कंपनी टार्गेट ने अपने दो दर्जन स्टोर को अस्थाई रूप से बंद रखने की घोषणा की। मिनीपोलिस में सुरक्षा चिंताओं के चलते रेल और बस सेवाएं बाधित हुई हैं। सेंट पॉल में धुएं का गुबार उठता देखा गया। कई जगह लगाई गई आग को बुझाने के लिए दमकल दस्तों को मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कड़ी नजर रख रही है। टार्गेट कंपनी के एक प्रतिष्ठान के बाहर अधिकारी खड़े नजर आए जो प्रदर्शनकारियों को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। हिंसा पर उतारू प्रदर्शकारी अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों के शीशों को तोड़ते नजर आए। सैकड़ों प्रदर्शनकारी बृहस्पतिवार को मिनीपोलिस के पास उस स्थान पर फिर से पहुंच गए जो हिंसा का केंद्र बनकर उभरा है। सारी रात इस जगह पर हंगामा होता रहा। मिनीपोलिस में दूसरी तरफ हजारों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया और न्याय की मांग की।

भारतीय मूल की डॉक्टर ने की डाउनिंग स्ट्रीट तक मौन प्रदर्शन की अगुवाई

भाषा। लंदन

कोरोना वायरस महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और नर्सों सहित अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की कमी को लेकर, ब्रिटेन सरकार के खिलाफ कानूनी लड़ाई में 53 हजार पाउंड का फंड जुटाने वाली भारतीय मूल की एक डॉक्टर ने, मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए यहां डाउनिंग स्ट्रीट तक मौन प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आठ माह की गर्भवती डॉक्टर मीनल विज के साथ इस प्रदर्शन में बृहस्पतिवार की शाम डॉक्टरों का एक समूह शामिल था। प्रदर्शन संयोग से ऐसे समय हुआ जब स्थानीय समयानुसार बृहस्पतिवार रात आठ बजे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में क्लैप फॉर केयरर्स पहल का साप्ताहिक कार्यक्रम हुआ।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी पहल के दसवें सप्ताह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों का सम्मान करने के लिए डाउनिंग स्ट्रीट स्थित अपने कार्यालय से बाहर निकले। उनसे कुछ कदमों की दूरी पर प्रदर्शनकारियों के समूह ने भौतिक दूरी के नियम का पालन करते हुए मौन प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने वाली विज ने कहा, एक डॉक्टर के रूप में, मैंने क्लैप फॉर केयरर्स के दौरान आपके समर्थन की प्रशंसा की है। लेकिन ताली बजाने की जगह मैं महामारी के दौरान जान गंवाने वाले अपने 237 सहकर्मियों की याद में मौन रखूंगी। विज अपने डॉक्टर पति निशांत जोशी के साथ पीपीई जैसे जीवनरक्षक उपकरण के मुद्दे पर लंदन उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के आग्रह से संबंधित प्रक्रिया से जुड़ी हैं।

अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद यूरेनियम संवर्द्धन जारी रखा जाएगा : ईरान

तेहरान। ईरान ने शुक्रवार को कहा कि ईरानी वैज्ञानिकों पर इस हफ्ते के प्रारंभ में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद उसके विशेषज्ञ यूरेनियम संवर्द्धन गतिविधियां जारी रखेंगे। सरकारी टीवी ने देश के परमाणु विभाग के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि दो ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर प्रतिबंध लगाने का अमेरिका का फैसला यह संकेत देता है कि अमेरिका अपना शत्रुतापूर्ण रुख जारी रखे हुए है। बयान में कहा गया है कि प्रतिबंधों के कारण वे अपनी कोशिशें पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा देंगे। बयान में कहा गया है कि प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के दो अधिकारियों-- माजिद आगा और अमजद साजगर पर प्रतिबंध लगा दिया था। ए लोग परमाणु संवर्द्धन के लिए सेंट्रीफ्यूग का विकास एवं उत्पादन करने में शामिल थे।

इंडोनेशिया के बेकासी अल बरखा ग्रैंड मस्जिद में कोरोनो वायरस के प्रसार पर अंकुश के लिए दुआ मांगते लोग

चीन में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखने वाले पांच नए मामले

बीजिंग। चीन में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखने वाले पांच नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल ऐसे मामलों की संख्या 409 तक पहुंच गई है। बहरहाल, देश में संक्रमण के लक्षण दिखने वाला कोई नया मामला सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग (एनएचसी) ने बताया कि बृहस्पतिवार को कोई भी संदिग्ध मामला या किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं है। आयोग ने बताया कि बृहस्पतिवार को संक्रमण के लक्षण नहीं दिखनेवाले पांच नए मामले सामने आए हैं। इस वायरस का केंद्र माने जाने वाले वुहान में इस तरह के 337 मामले हैं। संक्रमण के लक्षण नहीं दिखने वाले 409 लोग चिकित्सीय निगरानी में हैं। संक्रमण के लक्षण नहीं दिखने वाले लोग कोरोना वायरस से संक्रमित तो होते हैं लेकिन उनमें कोई बुखार, सर्दी या गले में परेशानी जैसे लक्षण नहीं दिखते हैं। हालांकि ऐसे लोगों से दूसरे लोगों के संक्रमित होने का खतरा बरकरार रहता है।

न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का केवल एक सक्रिय मामला, अन्य देशों में स्थिति गंभीर

भाषा। वेलिंगटन

न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का लगभग उन्मूलन हो गया है और 50 लाख की आबादी वाले इस देश में आज की तारीख में महामारी का केवल एकमात्र सक्रिय मामला बचा है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है और पाकिस्तान में इस विषाणु के कहर से बड़ी संख्या में मौत होने की खबर है।

अमेरिका में धीरे-धीरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने के बावजूद पिछले सप्ताह महामारी से उत्पन्न स्थितियों के चलते 20 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। अब यह डर बढ़ता जा रहा है कि कोरोना वायरस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों की नौकरी छिनने संबंधी अमेरिकी श्रम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के चलते मार्च के मध्य में हुई तालाबंदी के बाद से चार करोड़ दस लाख अमेरिकी लोगों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है। न्यूजीलैंड में एक सप्ताह से कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश में कोरोना वायरस की चपेट में आए ।,504 लोगों में से 22 की मौत हो गई है और एक व्यक्ति को छोड़कर शेष अन्य ठीक हो गए हैं। पाकिस्तान में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 57 लोगों की मौत दर्ज की गई जो देश में महामारी के शुरू होने के बाद से एक दिन में मौतों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही देश में महामारी से मरनवालों की कुल संख्या ।,300 के आंकड़े को पार कर गई है और संक्रमण के मामलों की संख्या 64 हजार से अधिक हो गई है।

फिलीपीन में दो महीने से अधिक समय से चली आ रही कड़ी पाबंदी के बाद राजधानी मनीला में लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया गया है जहां हाल में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखने को मिली थी। अमेरिका में इस महामारी से सर्वाधिक मौत हुई हैं और मृतकों की संख्या ।,01,000 के आंकड़े को पार कर गई है। हालांकि, देश के आर्थिक आंकड़ों में कुछ उत्साहजनक संकेत दिखे हैं। संकट शुरू होने के बाद से बेरोजगारी भत्ते का लाभ ले रहे लोगों की संख्या ढाई करोड़ से घटकर दो करोड़ दस लाख रह गई है। अमेरिका में अप्रैल में बेरोजगारी की दर 14.7 प्रतिशत थी और कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मई में यह 20 प्रतिशत रहेगी। यूरोपीय देशों को भी इस महामारी के चलते आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। जॉन हॉप्किन्स विश्वविद्यालय के अनुसार विश्वभर में वायरस ने 58 लाख से अधिक लोगों को अपने संक्रमण की चपेट में लिया है और लगभग 3,60,000 लोगों की मौत हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी से संबंधित आंकड़े उपलब्ध आंकड़ों से काफी अधिक हो सकते हैं क्योंकि अनेक लोग ऐसे हैं जिनकी कोरोना वायरस से संबंधित जांच ही नहीं हुई और उनकी मौत हो गई।

खैबर पख्तूनख्वा में अल्पसंख्यक समुदाय को धार्मिक स्थलों में पूजा की अनुमति

पेशावर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा और प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। हालांकि, इस दौरान सभी को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने के साथ ही कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू अन्य उपायों का भी पालन करना होगा। कोरोना वायरस प्रसार के मद्देनजर कई प्रांत की सरकारों ने धार्मिक स्थलों पर पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पाकिस्तान में अब तक 64,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में हैं जबकि ।,346 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौलानों के दबाव बनाने के बाद इमरान खान सरकार ने रमजान के महीने में कुछ शर्तों के साथ मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की अनुमति दे दी थी। खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने शुक्रवार को हिंदू, सिख और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को धार्मिक स्थलों में जा कर पूजा-प्रार्थना करने की अनुमति दे दी।

पाकिस्तान सरकार ने कड़े लॉकडाउन का निर्णय नहीं लिया है: मंत्री

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान में शुकवार को कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 64,000 के पार चले जाने के बावजूद एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने के लिए सख्त लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लिया है। सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा कि सरकार अस्पतालों में स्थिति को लेकर संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि कुछ अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं लेकिन कुल मिला कर स्थिति संतोषजनक है। मंत्री ने डॉन अखबार से कहा कि कुछ अस्पतालों में बोझ ज्यादा है क्योंकि लोगों में मुख्य एवं प्रसिद्ध अस्पतालों में पहुंचने की प्रवृति होती है।

फराज ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि फिलहाल देश में 404 गंभीर मरीज हैं जिनमें 161 जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, इसका तात्पर्य है कि गंभीर मरीजों के लिए अब भी उनके पास बड़ी संख्या में जीवन रक्षक प्रणालियां हैं। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मुश्किल स्थिति में नहीं हैं और हमारे पास उपयुक्त सुविधाएं भी हैं। मंत्री ने कहा कि पहले कोविड-19 के जितने मरीजों का अनुमान था, वर्तमान में उससे कम मरीज हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2,636 नए मरीज सामने आने के साथ ही देश में इस महामारी के मामले बढ़ कर 64,028 हो गए। पिछले 24 घंटे में 57 मरीजों की मौत के साथ ही इस महामारी से अब तक देश में 1317 लोगों की जान जा चुकी है। एक सवाल के जवाब के दौरान मंत्री ने मानक संचालन प्रक्रिया का लोगों द्वारा उल्लंघन किए जाने पर चिंता तो प्रकट की लेकिन कहा कि देश में कड़े लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ से अधिक निर्धन आबादी वाले देश में लॉकडाउन अधिक समय तक नहीं रह सकता है।

पाकिस्तान में कोविड-19 के मामले 64 हजार के पार, मृतक संख्या 1,317 हुई

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2,636 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 64,028 हो गए। वहीं 57 और लोगों की जान जाने के बाद मरने वालों की संख्या ।,317 हो गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सिंध में 25,309, पंजाब में 22,964, ख़ैबर पख़ूतूनख़्वा में 8,842, बलूचिस्तान में 3,928, इस्लामाबाद में 2,100, गिलगित-बाल्टिस्तान में 658 और आजाद कश्मीर (पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर) में 227 मामले हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में अभी तक 23,305 मरीज ठीक हो चुके हैं।अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11,931 जांच की गई। अभी तक कुल 5,20,017 लोगों की जांच की गई है।इस बीच, पेशावर में एक वरिष्ठ पत्रकार की बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस से मौत हो गई।

दक्षिण अफ्रीका में जांच किट की कमी होने के कारण करीब एक लाख नमूनों को परीक्षण का इंतजार

जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि जांच किट की कमी होने के कारण देश में कोविड-19 के लिए करीब 100,000 नमूनों का परीक्षण किया जाना लंबित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार रात को जारी एक बयान में गत सोमवार तक 96,480 परीक्षण लंबित होने की बात कही। मंत्रालय ने कहा, यह चुनौती वैश्विक स्तर पर जांच किट की सीमित उपलब्धता के कारण है। इसमें कहा गया कि अस्पताल में भर्ती मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों के नमूनों की जांच को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्य अफ्रीकी देशों के मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक संख्या में कोविड-19 के नमूनों की जांच की जा रही है। इस देश में अब तक 655,000 परीक्षण किए जा चुके हैं और इस महाद्वीप में सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में 27,403 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं।

आस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर में दो शेरों ने महिलाकर्मी को बुरी तरह घायल किया

भाषा। सिडनी

आस्ट्रेलिया में बंद पड़े एक चिड़ियाघर में शुक्रवार को दो शेरों ने अपने बाड़े के अंदर हमलाकर एक कर्मचारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस और एंबुलेंस ने एक बयान में कहा कि सिडनी के उत्तरी हिस्से में शोआलहैवेन चिड़ियाघर में शुक्रवार की सुबह आपात सेवा को फोन किया गया क्योंकि 35 साल की एक महिला कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी, उसके सिर और गले पर गहरे घाव थे। इस महिलाकर्मी को विमान से सिडनी के अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यह चिड़ियाघर कोरोना वायरस महामारी के चलते बंद है। एंबुलेंस अधिकारी फे स्टॉकहोम ने इस हमले को बहुत भयावह बताया। उन्होंने कहा कि इस कर्मी के उपचार के वास्ते, सबसे पहले बाड़े में जाना भयावह था। यह मेरी नौकरी का अब तक का सबसे बुरा अनुभव है।

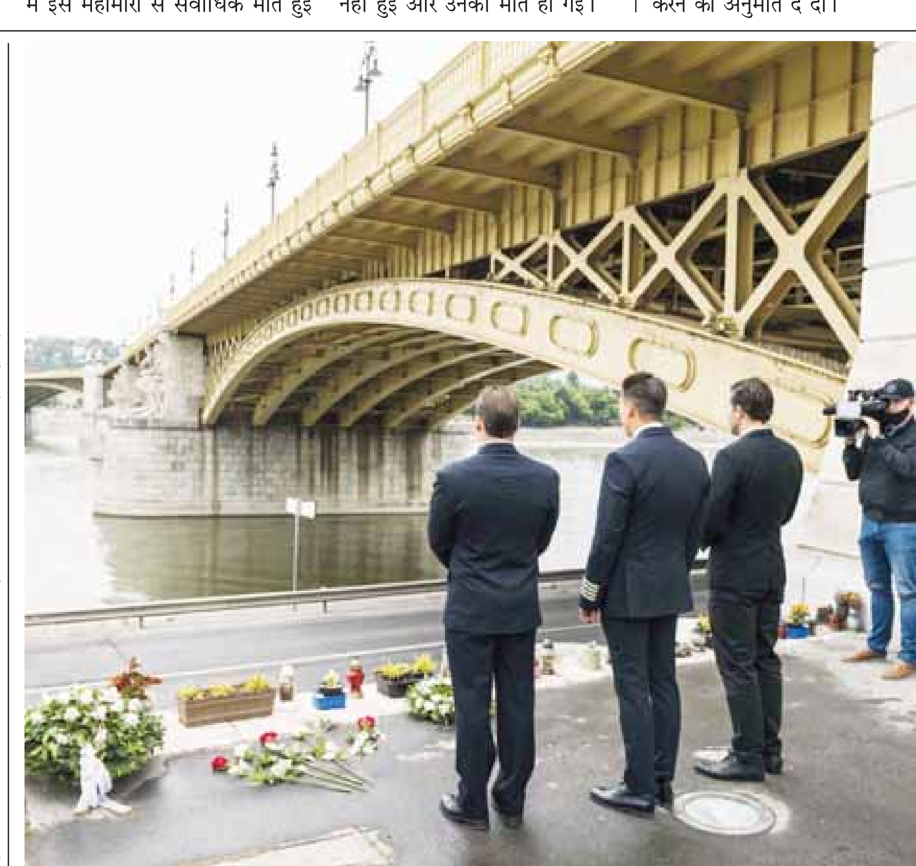

बुडापेस्ट में पैनोरमा डेक शिपिंग कंपनी के सेल्स डायरेक्टर तामस सेस्तानको, क्रिएटिव डायरेक्टर ज़ोल्टन फिगरर और प्रवक्ता मिहाली टोथए ने हबलियन बोट का संचालन किया

फिल्मों में नायिका की परिभाषा में आया परिवर्तन

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का मानना है कि दर्शकों द्वारा अपने से जुड़ाव वाली कहानियों में रुचि लेने कारण वर्तमान में 'नायिका' शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है।

भूमि ने बताया, 'मेरे द्वारा अब तक की गई सभी फिल्मों में मेरी भूमिका एक दूसरे से भिन्न थी। इनमें कुछ समानता भी हो सकती है उदाहरण के लिए मेरे सभी चरित्र सामान्य नागरिको की कहानी को ही प्रस्तुत करते हैं।' 'मैंने अभी तक जो भी फिल्में की हैं मुझे उनपर गर्व होता है। इससे मैं अपने दर्शकों से जुड़ाव स्थापित करने में सफल हो सकी हूं। आज के समय में कह सकते हैं कि 'नायिका' शब्द की परिभाषा में विशाल परिवर्तन तथा विकास देखने को मिलता है।'

माधुरी के जीवन की झांकी है फिल्म 'कैंडल'

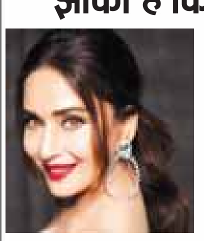

लगातार कई हिट फिल्में देने वाली अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का कहना है कि उनकी फिल्म 'कैंडल' में उनकी अब तक की यात्रा की ही एक झांकी प्रस्तुत की गई है जिसमें सुखद आश्चर्य, संघर्ष, आयोजन और आत्मनिरीक्षण जैसी बातें वास्तविकता थीं। मेरी यात्रा को जो एक बात पूरे समय बांधे रही वो थी प्यार और आशा, कि हर घटना का एक सही कारण भी होता है। मुझे लगता है कि मेरे प्रशंसकों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि उन्हें गहन परिश्रम करना चाहिये, फिर चाहे राह में किसी भी प्रकार का अवरोध क्यों न हों।

वरुण धवन सीख रहे हैं स्पैनिश भाषा

अभिनेता वरुण धवन का फिल्म 'फुकरे' में नाम था चूचा, अब वो भाषा के अपने कौशल को और बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान लॉकडाउन में वो स्पैनिश भाषा सीख रहे हैं। उन्होंने बताया, 'स्वंय को हर समय व्यस्त रख पाना कठिन होता है यही कारण है कि मैंने एक नए कौशल को सीखने का निर्णय किया। मैं अब एक नई भाषा सीख रहा हूं। मैं सदा से ही एक नई भाषा सीखना चाहता था और अब मुझे इसके लिए समय मिल गया है।'

इससे पहले वो अपनी मां की सहायता से पेंटिंग भी सीखते रहे हैं।

काम की बात करें तो वरुण, राजकुमार राव तथा जान्हवी कपूर के साथ फिल्म 'रूही अफ्ज़ाना' में दिखेंगे।

कोरोना के कारण बच्चे के जन्म को लेकर चिंतित थीं अभिनेत्री अमेरिका फरेरा

हॉलीवुड अभिनेत्री अमेरिका फरेरा ने स्वीकार किया है कि उन्हें कोरोना वायरस महामारी के समय बच्चे को जन्म देने को लेकर गहन चिंता हो गई थी। इसी माह फरेरा जो अगली बेटी, शो में अपने चरित्र को लेकर लोकप्रिय हैं, ने हाल ही में अपने दूसरे बच्चे एक पुत्री 'लूसिया मेरिसोल' को जन्म दिया है। कटीज़ क्रिब पॉडकास्ट के एक एपिसोड में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें गर्भावस्था के समय समाचार देखना कम करना पड़ा था ताकि किसी प्रकार के भय और चिंता से बचा जा सके। उन्होंने बताया, 'मुझे तो इसे रोकने के लिए कुछ करना ही था क्योंकि मेरे पास इसे पचाने के लिए आवश्यक भावनात्मक क्षमता नहीं थी।'

'फिल्म 'एंग्री इंडियन गॉडेसेज़' के बाद मुझे जीवन की राह मिल गई'

पवलीन गुजराल, 'एंग्री इंडियन गॉडेसेज' की पम्मी से, अधिवक्ता से अभिनेता बनने की कहानी वाले उनके नए शो, और वापसी के लिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही क्यों चुना, जैसे विषयों पर उनके विचार जाने पायनियर संवाददाता शालिनी सक्सेना ने। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश-

■ आप अपने शो 'मर्ज़ी' में अपनी भूमिका के बारे में कुछ प्रकाश डालिये...

ये सीरीज़ बीबीसी ऑरिजिनल सीरीज़ 'लायर' का ही हिंदी रूपांतरण है। जब कोई परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हो और किसी महत्वपूर्ण संस्था के सहयोग से प्रारंभ होती है तो उसपर एक प्रकार का विश्वास सा बन जाता है। इसमें राजीव खंडेलवाल और अहाना कुमरा लीड रोल कर रही हैं। मैं सदा से राजीव खंडेलवाल के साथ काम करना चाहती थी। हमें उनकी क्षमताओं के बारे में पता ही है और उनका काम भी मैं देख चुकी हूं। दूसरी बात ये है कि इसकी पटकथा और स्क्रीनप्ले बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा वायाकॉम भी इससे जुड़ा है तो इसके रूपांतरण के बारे में किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता। इसके बाद मुझे अपने चरित्र के बारे में छोटी छोटी बातों का पता चला जो अति महत्वपूर्ण होती हैं इनमें इस बात की व्याख्या होती है कि चरित्र किस प्रकार से कहानी से जुड़ता है।

■ आप इस परियोजना से किस प्रकार से जुड़े थे?

इसके लिए मुझे ऑडिशन के तीन चक्रों से गुजरना पड़ा था। लेकिन रोचक बात ये है कि मुझे इनके लिए कभी मुंबई नहीं जाना पड़ा। मैंने इसके लिए सेल्फटेस्ट अर्थात स्व-परीक्षण भेजा और इसी से काम चल गया।

इसके अलावा निर्माताओं ने मेरे पूर्व के प्रोजेक्ट देखे थे और उन्हें उनके बारे में गहन जानकारी थी। मैं अपने पूर्व की परियोजनाओं को लेकर भी भाग्यशाली रही हूं। इनमें भोर, एंग्री इंडियन गॉडेसेज़ तथा सिटी ऑफ ड्रीम्स जैसे प्रोजेक्ट थे। ये सभी प्रोजेक्ट मुझे बिना किसी ऑडिशन या कहीं के फोन पर ऑडिशन के माध्यम से मिले थे। मैंने कई ऑडिशन दिये थे लेकिन मुझे सेल्फटेस्ट या मेरे पूर्व के काम के आधार पर ही काम मिला था। लेकिन ये भी सही है कि सब कुछ किसी प्रोजेक्ट विशेष पर ही निर्भर करता है।

■ आपने 'एंग्री इंडियन गॉडेसेज़' के बाद ब्रेक ले लिया था। अब वापस आकर काम करना कितना कठिन प्रतीत हो रहा है?

देखिये, ऐसा करना कठिन तो होता ही है। लेकिन कुछ बातें मेरे विपरीत भी रहीं। मैं मुंबई में नहीं रहती। मैं तो दिल्ली में ही रह रही हूं। जब मैंने ब्रेक लिया तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी। यही कारण था कि मुझे ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज ये इंडस्ट्री ऐसे पड़ाव पर है जहां यदि अभिनेत्री अच्छी है तो आयु का बंधन नहीं रहता और उसे काम मिलता रहता है।

■ क्या आपको विश्वास है कि आप पामेला के बाद भी लोग आपको देखना पसंद करेंगे?

जी हां, पामेला के बाद मैंने भोर में काम किया जिसमें मैं एक ग्रामीण अध्यापिका बनी हूं। उसमें मुझे जरा सा भी मेकअप नहीं लगाना था। मुझे साड़ी पहननी थी और चश्मा भी लगाना था। जबकि 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' में मेरा रोल पूरी तरह से भिन्न प्रकार का था। मैंने विविध प्रकार की भूमिकाएं की हैं और इस प्रकार अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। लेकिन आज भी मुझे बहुत काम करना शेष है।

■ आपको आपकी परियोजना 'एंग्री इंडियन गॉडेसेज़' में काम करने से कितना प्रोत्साहन मिला?

मैं इतना कह सकती हूं कि इसके बाद इंडस्ट्री में लोगों को अभिनेत्री के रूप में मेरी उपस्थिति का पता चला। इसके बाद ही कई कास्टिंग निर्देशकों ने मुझसे संपर्क करना प्रारंभ किया। जब सुभाष के झा जैसे समीक्षकों ने मेरे काम का विशेष उल्लेख किया और मुझे संदेश भी भेजा कि फिल्म में मेरा प्रदर्शन ऐसा था जिसे कोई भी अपने बच्चों को दिखाना चाहेगा। इससे मैं बहुत भावुक हो गई थी। जब समीक्षक आपके काम की प्रशंसा करें और दर्शकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिले तो इससे मेरा जीवन परिवर्तित हो गया।

■ लोगों का कहना है कि पहली फिल्म ही आपके कॅरियर को बना या बिगाड़ सकती है। इससे आप कितना सहमत हैं?

मुझे ये बात पूरी तरह से सच नहीं लगती। ये तो इस बात पर निर्भर होता है कि आपको पहली फिल्म में किस प्रकार का रोल मिला था। इसके अलावा फिल्म का बैनर और निर्देशक आदि भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। यदि आपका रोल छोटा है लेकिन फिल्म बड़ी है तो आपका काम चल जाएगा लेकिन यदि ये फिल्म हिट हो जाती है तो ये आपके लिए अतिरिक्त लाभ हो जाता है। अत: आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ होती है बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है।

■ क्या फिल्म का मनोरंजन प्रधान होने के स्थान पर कंटेंट प्रधान होना जरूरी है तभी वो सफल मानी जाएगी?

दोनों का एक आदर्श संतुलन होना आवश्यक है। लोग किसी भी फिल्म को मूलत: मनोरंजन के लिए ही देखता है। अब यदि ये पूरी तरह से कंटेंट आधारित होगी तो लोग इसे देखेंगे ही नहीं। उदाहरण के लिए आप लघु फिल्म 'देवी' को ही लीजिये। ये कंटेंट आधारित होने के साथ ही मनोरंजक भी थी। फिल्म 'एंग्री इंडियन गॉडेसेज़' में भी एलजीबीटीक्यूआई अधिकार, महिला सशक्तीकरण, महिला आत्मनिर्भरता जैसे संदेश भी इसमें थे, लेकिन ये अत्यंत रोचक बन पड़ी थी। फिल्म 'मर्ज़ी' में भी संदेश यही था कि न का अर्थ न ही होता है, कुछ और नहीं। लेकिन इसे भी अत्यंत रोचक ढंग से तथा कई रोचक मोड़ देते हुए प्रस्तुत किया गया है ताकि दर्शकों को बांधे रखा जा सके।

■ आपने एक अधिवक्ता से लेकर अभिनेता तक की यात्रा की है। ये कैसे संभव हो सका?

मैंने विधि की पढ़ाई की है और छः माह तक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी की है। मैंने स्कूल के समय कई थियेटर भी किये हैं और अभिनेत्री बनना चाहती थी लेकिन मेरे परिवार में इसे कोई भी कॅरियर नहीं मानता। यही कारण था कि मैंने विधि का अध्ययन किया और ये अच्छा लग रहा था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा था कि इसमें मुझे वो आनंद नहीं आ रहा था। फिर मैंने मॉडलिंग, एमसी और होस्ट के रूप में कॅरियर बनाने का प्रयास किया, मैं आज भी ये कर रही हूं। इसके बाद ही मुझे एंग्री इंडियन गॉडेसेज़ मिल गई और फिर तो मुझे मेरी राह ही मिल गई।

■ आपने वापसी के लिए वेब सीरीज़ को ही क्यों चुना?

फिल्म 'एंग्री इंडियन गॉडेसेज़' के बाद मुझे कई और प्रोजेक्ट भी मिले, लेकिन उनसे मुझे खुद को जानने में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। मैं किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो दबाव में किया गया लगे। लेकिन 'मर्ज़ी' का मिलना अच्छा रहा और ये मेरे लिए अच्छा अनुभव साबित होगा।

भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी दीजिये...

फिल्म भोर तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी जबकि 'मेड इन हेवेन2' की शूटिंग प्रारंभ होने वाली है। इसके अलावा 'मर्ज़ी 2' भी बनने वाली है। इसके बाद दो और फिल्में हैं जो इसी साल रिलीज़ होने वाली थीं। लेकिन अब हर बात अनिश्चित प्रतीत होती है।

मानुषी छिल्लर ने थामा यूनीसेफ का हाथ

मासिक धर्म के प्रति फैलाएंगी जागरुकता

भाषा। मुंबई

पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर मासिक धर्म के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए यूनीसेफ के साथ आई हैं।

मॉडल की टीम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि वह इस संबंध में स्वच्छता, पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और महिला स्वच्छता से जुड़े उत्पादों की पहुंच के संबंध में प्रचार करेंगी। छिल्लर खुद भी प्रोजेक्ट शक्ति के नाम से मासिक धर्म से जुड़ी पहल चला रही हैं। यह भारत के कई राज्यों में काम करता है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरुकता फैलाना बहुत जरूरी है। पूर्व मिस वर्ल्ड ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक लड़की को अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी होने का अधिकार है और बिना सही जानकारी के वह प्राय: यह नहीं जान पाती हैं कि मासिक धर्म से सुरक्षित तरीके से कैसे गुजरें। काफी चीजें हुई हैं लेकिन बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम सभी को इस संबंध में जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। मैं खुद को सम्मानित महसूस करती हूं कि मैं इसके लिए यूनिसेफ के उस पहल से जुड़ी हूं जिसका लक्ष्य गलत जानकारी को खारिज करना, मिथकों को तोड़ना और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूकता फैलाना है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर 28 मई को पूर्व मिस वर्ल्ड ने यूनिसेफ के वैश्विक पहल रेड डॉट चैलेंज में हिस्सा लिया था। इस संकेत का इस्तेमाल विश्व की इस इकाई ने मासिक धर्म के चक्र को दर्शाने के लिए किया है। छिल्लर अभिनेता अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वह इसमें राजकुमारी संयोगिता का किरदार निभाएंगी।

सोनू सूद ने विशेष विमान से 177 लड़कियों को केरल से ओडिशा भेजा

भाषा। मुंबई

अभिनेता सोनू सूद ने शुक्रवार को 177 लड़कियों को ओडिशा में उनके घर पहुंचाने में मदद की। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ये लड़कियां केरल में फंस गई थी। अभिनेता के एक करीबी सूत्र ने बताया कि सूद को उनके, भुवनेश्वर के रहने वाले एक दोस्त ने इन लड़कियों के बारे में बताया था और उन्होंने इनकी मदद करने का निर्णय किया। सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, कोच्चि और भुवनेश्वर हवाईअड्डे खुलवाने के लिए अभिनेता ने विभिन्न अनुमति लेने के साथ काम शुरू किया। कोच्चि से इन 177 लड़कियों को ले जाने के लिए बेंगलुरु से एक विशेष विमान मंगाया गया, जो इन्हें भुवनेश्वर ले जा कर इनके परिवार से मिलाएगा। उन्होंने कहा, गांव से भुवनेश्वर का रास्ता दो घंटे का है और वहां पहुंचने के बाद ही लड़कियां अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगी। राज्यसभा सांसद अमर पटनायक ने ट्विटर पर सूद का धन्यवाद करते हुए इसे एक नेक प्रयास करार दिया। पटनायक ने कहा, प्रिय सूद जी, केरल से लड़कियों को ओडिशा लाने में मदद करना सराहनीय है। आपके नेक प्रयासों को सलाम। आपको और हिम्मत मिले। अपनी मित्र नीति गोयल के साथ घर भेजो पहल चला रहे सोनू सूद अपने प्रयासों से लाखों दिल जीत चुके हैं। अभिनेता ने अभी तक मुम्बई से कई प्रवासी मजदूरों को कर्नाटक, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी भेजा है। उन्होंने हाल ही में प्रवासियों की मदद के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया था।

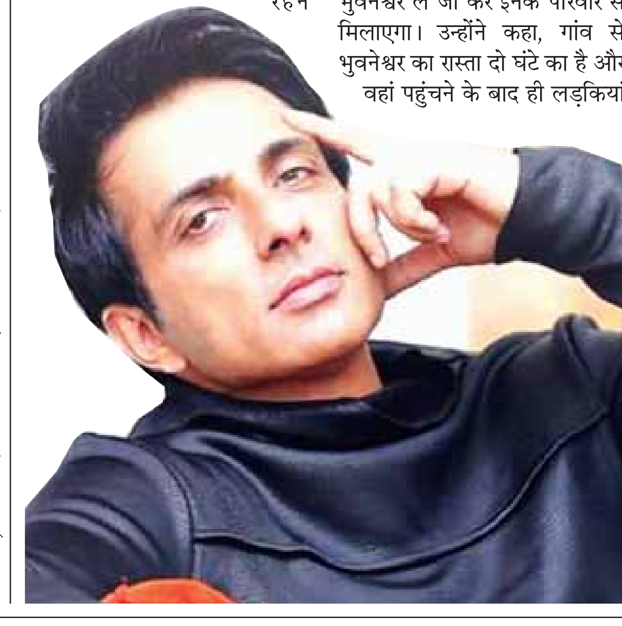

अभिनेता नहीं इंजीनियर बनना चाहते थे परेश रावल

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता परेश रावल अपने दमदार अभिनय से लगभग चार दशक से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं लेकिन वह पहले इंजीनियर बनना चाहते थे। परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को हुआ। 22 वर्ष की उम्र में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मुंबई आ गये और सिविल इंजीनियर के रूप में काम पाने के लिए संघर्ष करने लगे। उन्ही दिनों उनके अभिनय को देख कर कुछ लोगों ने कहा कि वह अभिनेता के रूप में अधिक सफल हो सकते है। परेश रावल ने अपने सिने कैरियर की शुरूआत 1984 में प्रदर्शित फिल्म 'होली' से की। इसी फिल्म से आमिर खान ने भी अभिनेता के रूप में अपने सिने कैरियर की शुरूआत की थी। इस फिल्म के बाद परेश रावल को हिफाजत 'दुश्मन का दुश्मन' लोरी और भगवान दादा जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला लेकिन इनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। वर्ष 1986 में परेश रावल को राजेन्द्र कुमार निर्मित फिल्म 'नाम' में काम करने का अवसर मिला (संजय दत्त और कुमार गौरव अभिनीत इस फिल्म में वह खलनायक की भूमिका में दिखाई दिये। फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुयी और वह खलनायक के रूप में कुछ हद तक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गये। 'नाम' की सफलता के बाद परेश रावल को कई अच्छी फिल्मों के प्रस्ताव

जन्मदिन आज

मिलने शुरू हो गये 'जिनमें मरते दम तक', 'सोने पे सुहागा', 'खतरो के खिलाड़ी', 'राम लखन' ,'कब्जा', 'इज्जत' जैसी बड़े बजट की फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों की सफलता के बाद परेश रावल ने सफलता की नयी बुलंदियों को छुआ और अपनी अदाकारी का जौहर दिखाकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। वर्ष 1993 परेश रावल के सिने कैरियर का महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस वर्ष उनकी दामिनी 'आदमी और मुकाबला' जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुयीं। फिल्म सर के लिये उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फ़ेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ जबकि फिल्म वो छोकरी में अपने दमदार अभिनय के लिए वह राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किये गये।वर्ष 1994 में प्रदर्शित फिल्म 'सरदार' परेश रावल कैरियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में एक है । केतन मेहता निर्मित इस फिल्म में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को रूपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय से उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान बना ली। वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म 'तमन्ना' परेश रावल की महत्वपूर्ण फिल्म में शुमार की जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे 'हिजड़े' की भूमिका निभाई। जो समाज के तमाम विरोध के बावजूद एक अनाथ लड़की का पालन-पोषण करता है। हालांकि यह फिल्म टिकट खिड़की पर कोई खास सफल नही हुयी लेकिन उन्होंने अपने भावपूर्ण अभिनय से दर्शकों के साथ ही समीक्षकों का भी दिल जीत लिया। वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म हेराफ़ेरी परेश रावल की सर्वाधिक सफल फिल्म में शुमार की जाती है। प्रियदर्शन निर्देशित इस फिल्म में उन्होंने बाबू राव गणपत राव आप्टे नामक मकान मालिक का किरदार निभाया। इस फिल्म में परेश रावल अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की तिकड़ी के कारनामों ने दर्शकों को हंसाते हंसाते लोटपोट कर दिया।

लॉकडाउन में हैरी पॉटर पढ़ रही हैं आलिया

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट लॉकडाउन में मशहूर उपन्यास हैरी पॉटर पढ़ रही है।

आलिया भट्ट लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हैं कुछ समय पहले उन्होंने अपनी फिटनेस और हेयरकट को लेकर एक पोस्ट लिखी थी और अब आलिया जेण् के रॉलिंग के मशहूर उपन्यास हैरी पॉटर को पढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आलिया ने किताब के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और इस तस्वीर के कैप्शन में लिखाए मैजिक हमारे आस.पास ही है। हमें उसे बस महसूस करना है। या पढ़ना है। आलिया ने इसके अलावा एक और पोस्ट में बताया कि उन्हें कभी बचपन में हैरी पॉटर को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया लेकिन पिछले दो महीनों में उन्होंने इस उपन्यास को पढ़ा है और उन्हें ये काफी पसंद आया है। रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने भी रिएक्ट कर उन्हें बधाई दी है।आलिया भट्ट फिल्म ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में वह पहली बार रणबीर कपूर के साथ काम कर रही हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय जैसे सितारे भी नजर आएंगे।